चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

अग्निपरीक्षा में बिहार की जनता जीती

पेज-3

गठबंधन से लड़ने लड़ाने की चुनौती

पेज-4

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल-II

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 06 दिसंबर-12 दिसंबर 2010 | मूल्य 5 रुपये

इतिहास का नायक

बिहार चुनाव का फ़ैसला चौंकाने वाला है. नीतीश कुमार के बोये चेतना के बीज ने बिहार की जनता को मंडल कमीशन की विचारधारा से आगे बढ़ा दिया है. महिलाओं, अति पिछड़ों और महादलितों ने पहली बार दबंगों की आंखों में आंखें डाल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया. यह सब इतनी ख़ामोशी से हुआ, जिसे लालू यादव और राम विलास पासवान भांप भी नहीं पाए. कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई, क्योंकि कांग्रेस कभी अपने उद्देश्य में साफ़ रह ही नहीं पाई और लोगों ने नीतीश कुमार को इतना समर्थन दिया कि वह इतिहास के नायक बन गए.

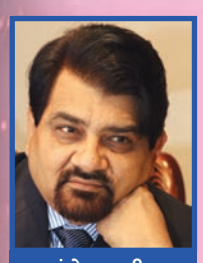

संतोष भारतीय

बिहार में नीतीश कुमार की जीत उनकी अपनी है या बिहार की जनता की है, यह सवाल बहुतों के मन में है. इसका उत्तर बहुत साफ है, बिहार में जनता जीती है और उसने नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा नेता चुना है, जिस पर बहुत से सपनों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी है. बिहार की जनता ने समय-समय पर बड़े ऐतिहासिक फ़ैसले किए हैं. यह फ़ैसला भी उनमें से एक है.

याद करें तो महात्मा बुद्ध याद आते हैं, तीर्थंकर महावीर याद आते हैं, चाणक्य याद आते हैं, वैशाली गणतंत्र याद आता है, नालंदा विश्वविद्यालय याद आता है, गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत का केंद्र चंपारण याद आता है. भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद याद आते हैं और याद आते हैं लोकनायक जय प्रकाश नारायण, जिन्होंने देश में लोकतंत्र और बुनियादी परिवर्तन की लड़ाई शुरू की. लोकनायक जय प्रकाश के आंदोलन से निकले बहुत से लोग आज राजनीति के शीर्ष पर हैं, जिनमें बिहार के लालू यादव, राम विलास पासवान और नीतीश कुमार प्रमुख हैं. बिहार की जनता ने इस बार इन तीनों में साफ तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है.

साठ के दशक के अंतिम चरण में जब बिहार में बूथ कैप्चर करने की शुरुआत हुई तो उसने पंद्रह सालों में इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि कभी लगता ही नहीं था कि अब साफ-सुथरे चुनाव देखने को मिलेंगे. सारे देश में यह तकनीक बिहार से गई, बिहार का नाम देश में काफी बदनाम हुआ. फिर आया लालू यादव का दौर. बिहार में सत्ता में वे आए, जिन्हें कभी सत्ता में हिस्सेदारी मिली ही नहीं थी. पिछड़ों, दलितों के समूहों में बहुत आशाएं पैदा हुईं, पर पंद्रह सालों में बहुत सी आशाएं टूट गईं. ऐसा लगा कि सत्ता है ही ऐसी, जिसके पास आती है, वह एक ही चरित्र का हो जाता है.

पंद्रह सालों में विकास तो हुआ ही नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी न दबे-कुचलों को मिली और न अल्पसंख्यकों को. इसके विपरीत बिहार में अपराध बढ़ गए. रंगदारी, अपहरण के उद्योग खड़े हो गए. व्यापारी से लेकर रिक्शा वाला असुरक्षित हो गया. अपराधियों के लिए करोड़पति और पचास रुपये रखने वाला सिर्फ़ शिकार बन गया. महिलाएं शाम के बाद सड़कों पर निकलती नहीं थीं, कहा जाने लगा कि शाम के बाद जितनी बड़ी गाड़ी निकलती थी, उसमें उतना ही बड़ा गुंडा नेता की पोशाक में निकलता था. विकास के नाम पर बिहार शून्य था. विकास का पहला क़दम सड़क ग़ायब हो गई थी. कहा जाने लगा था कि बिहार में सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है. बिहार में किसी को आशा नहीं थी कि दृश्य बदलेगा. जाति का इतना गहरा असर था कि लोग मानने लगे थे कि बिहार जाति की राष्ट्रीय राजधानी है. हर जाति या नेता अपनी जाति को अपनी जागीर मानने लगा था.

फिर आया फरवरी दो हज़ार पांच. सरकार नहीं बन पाई. आया नवंबर दो हज़ार पांच, जिसमें जनता ने साधारण बहुमत से नया प्रयोग किया, सत्ता नीतीश के हाथों में गई. और अब आया चौबीस नवंबर दो हज़ार दस, जिसमें बिहार की जनता ने ऐतिहासिक फ़ैसला दिया, न कोई लाग, न लपेट, न कोई संदेह. इतना बहुमत नीतीश को दे दिया कि वह जो चाहें करें, उन्हें रोकने की ताक़त किसी के पास नहीं है, न लालू यादव और न राम विलास पासवान के. यह फ़ैसला देश का सबसे बड़ा राजनैतिक फ़ैसला है, जिसमें बिहार की जनता ने एक झटके में जाति का बंधन तोड़ दिया और धर्म आधारित राजनीति को भी बांध दिया. इसमें सभी शामिल रहे, यादव भी, मुसलमान भी और दलित भी.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया. अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया, इससे इनमें संदेश गया कि अब इन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है.

बिहार का यह फ़ैसला मंडल कमीशन से आगे जाता है. बिहार के लोगों ने उन लोगों को नकार दिया, जो मंडल कमीशन से निकले राजनैतिक फ़ायदे को सिर्फ़ पिछड़ों के मज़बूत वर्गों तक ही सीमित रखना चाहते थे. एक नई आशा पैदा हुई है कि अब कमज़ोर वर्गों में भी नया नेतृत्व उभर सकता है. अति पिछड़ों और महादलितों के साथ महिलाएं भी वंचित रही हैं. नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया. अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया, इससे इनमें संदेश गया कि अब इन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है. इतना ही नहीं, स्कूलों में उन्हें नौकरी मिली, स्थानीय निकायों के एकल पदों पर भी महिलाओं की नियुक्तियां हुईं. प्राइमरी शिक्षकों की लगभग दो लाख के बराबर नियुक्तियां हुईं, जिससे लोगों में आशाएं जगीं. हालांकि इसमें नालायक और सिफ़ारिशी अयोग्य लोग भी नियुक्त हुए, पर एक शुरुआत हुई, जिसका आम लोगों ने स्वागत किया. स्कूलों में पोशाकें बंटीं, लड़कियों को साइकिलें मिलीं. यह बिहार के लिए नई बात थी. झुंड के झुंड लड़कियों के स्कूल जाने लगे.

यह सब इतनी ख़ामोशी से हुआ कि इसका असर लालू यादव और राम विलास पासवान भांप ही नहीं पाए. ये अपने कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं सुनना चाहते थे. हालांकि कार्यकर्ता इन्हें बताना चाहते थे कि ज़मीनी सच्चाई बदल रही है. दोनों महाबली मानते थे कि जब ये मिल जाएंगे तो बिहार में उन्हीं की सत्ता आएगी, क्योंकि दबंग यादव और मज़बूत पासवान का जवाब कमज़ोर अति पिछड़े और महादलित क्या देंगे. मुसलमानों को तो ये अपनी जेब का चिल्लर समझते थे कि वे उन्हें छोड़कर जाएंगे कहां. साल भर पहले हुए उपचुनावों ने दोनों को आश्वस्त कर दिया था. जीत के बाद लालू यादव की पार्टी ने जिस तरह जश्न मनाए, उससे बिहार के लोग आशंकित हो गए. लालू यादव और राम विलास पासवान चुनावों से छह महीने पहले बिहार में सक्रिय हुए. ये सचमुच विश्वास करते थे कि यादव, पासवान और मुसलमान का गठजोड़ उनके हाथ में सत्ता लाने वाला है.

पर उधर नीतीश कुमार का ख़ामोशी से बोया चेतना का बीज प्रभावी ढंग से अपना नाम कर रहा था, जिसका असर ये दोनों महसूस ही नहीं कर पाए. इनके कार्यकर्ता और नेता ज़मीनी हक़ीक़त जानते थे, इसलिए इनसे टूटकर नीतीश की पार्टी में शामिल होने लगे. इन्हें कोई चिंता नहीं हुई. पासवान की तो पूरी अल्पसंख्यक इकाई ही नीतीश के साथ चली गई. ये दोनों महाबली पंद्रह साल पुरानी रणनीति पर चल रहे थे. इस बार लालू यादव को लगा कि वह अपने बेटे को चुनावों में जनता के सामने लाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे. उनका बेटा तेजस्वी आम सभाओं में भाषण देने लगा. राजनीति में अपने पापा को अपना कोच बताने लगा. उधर राम विलास पासवान ने अपने परिवार के छह लोगों को विधानसभा चुनाव में खड़ा कर दिया, जिनमें उनके दोनों भाई भी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ख़बर है कि गृह सचिव जी के पिल्लई ने कैडर रिव्यू के साथ हर साल भर्ती किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या में 60 पदों की वृद्धि का निर्देश दिया है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आईपीएस अधिकारियों की कमी

आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं के साथ-साथ कई अन्य परेशानियों से जूझ रहे भारत जैसे देश में आईपीएस अधिकारियों की कमी एक बड़ी चिंता का कारण है. आंकड़ों के मुताबिक़, वर्तमान समय में पूरे देश में आईपीएस अधिकारियों के 630 पद खाली पड़े हैं. वैसे तो हर राज्य में पुलिस अधिकारी कॉरपोरेट जगत की ओर रुख़ कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है. सूत्रों के मुताबिक़, राजधानी में आईपीएस अधिकारियों के कुल 4013 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में केवल 3383 अधिकारी ही उपलब्ध थे. ख़बर है कि गृह सचिव जी के पिल्लई ने कैडर रिव्यू के साथ हर साल भर्ती किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या में 60 पदों की वृद्धि का निर्देश दिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे स्थिति में ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती. पिल्लई और गृहमंत्री पी चिदंबरम के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है कि सीबीआई, आईबी और रॉ जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं भी अधिकारियों की कमी की समस्या से जूझ रही हैं. संवेदनशील राज्यों, जैसे जम्मू-कश्मीर में आईपीएस अधिकारियों के 28 पद रिक्त हैं, जबकि बिहार में 48 और पश्चिम बंगाल में 71 पद रिक्त हैं. अधिकारियों की इस कमी ने मंत्रालय के बाबुओं के कान खड़े कर दिए हैं और वे स्थिति में सुधार के लिए हाथ-पैर मारने की कोशिशों में लग गए हैं, लेकिन अब तक इन कोशिशों का कुछ नतीजा निकलता नहीं दिख रहा.

पारदर्शिता से घबराई नौकरशाही

सूचना अधिकार क़ानून के इस दौर में जब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए आम जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा है, नौकरशाहों के लिए इस नई चुनौती से निपटना खासा मुश्किल साबित हो रहा है. लेकिन केंद्रीय मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय के जजों द्वारा सूचना अधिकार क़ानून के तहत अपनी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए सहमति देने के बाद अब नौकरशाहों पर भी इसके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा मांग किए जाने के बाद सरकार ने चार महीने पहले आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक किए जाने के संबंध में उनकी राय पूछी थी. रोचक बात यह है कि आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के संगठन जहां इसके लिए राजी हो गए, वहीं आईएएस एसोसिएशन अब तक इसका कोई जवाब देने से बच रहा है. आधिकारिक तौर पर आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि उसने अपनी राज्य इकाइयों से इस संबंध में राय मांगी है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नौकरशाही के चिर परिचित टालमटोल वाले रवैये के रूप में देख रहे हैं. हालांकि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पास यह ब्योरा पहले से ही मौजूद है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कार्मिक सचिव शांतनु कॉन्सुल कोई फ़ैसला लेने से पहले आईएएस एसोसिएशन का मंतव्य जानने को इच्छुक हैं. अब यह देखना है कि एसोसिएशन इसके लिए राजी होती है या फिर मुख्य सूचना आयुक्त ए एन तिवारी को ख़ुद ही इसके लिए आगे पहल करनी होगी.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

12 की बस फिर छूटी

वर्ष 1984 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों में से 12 अधिकारियों की किस्मत मानों उनसे रूठ गई है. संयुक्त सचिव के लिए बनाई गई सूची में इन अधिकारियों का नाम शामिल नहीं हो पाया है. इस सूची के लिए दूसरी बार पुनरीक्षण का काम ख़त्म हो चुका है.

सुजाता की जगह चंद्रमौली

आंध्र कैडर की आईएएस अधिकारी के सुजाता राव स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पद से नवंबर महीने के आख़िरी दिन हट जाएंगी. उनकी जगह के चंद्रमौली लेंगे. चंद्रमौली 1975 बैच और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

शरण डीजीसीए में

डॉ. नसीम ए जैदी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बन गए हैं. वह 1976 बैच और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. इससे पहले वह डीजीसीए में थे. उनके जाने के बाद डीजीसीए का अंतरिम प्रभार ए के शरण को दे दिया गया है.

प्रवीण एफआईयू के निदेशक

प्रवीण कुमार तिवारी फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए निदेशक बनेंगे. तिवारी 1985 बैच के अधिकारी हैं. इस पद पर पहले अरुण गोयल थे, जिन्हें भारतीय दूतावास जापान भेज दिया गया है.

राज सिंह एनसीएमइआई में

राज सिंह को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए बने राष्ट्रीय आयोग में भेजा जा सकता है. यह पद संयुक्त सचिव पद के समकक्ष होता है.

इतिहास का नायक

पृष्ठ 1 का शेष

शामिल थे. लालू यादव और राम विलास पासवान के पास चुनाव जीतने की कोई योजना थी ही नहीं. लालू यादव की योजना बनाने वाले उनके शिवानंद तिवारी जैसे साथी उन्हें छोड़ गए और जो साथ थे जाबिर हुसैन जैसे, वे ख़ामोश बैठ गए. इन्होंने न केवल अपनी पार्टी को, बल्कि जनता को भी टेकेन फार ग्रांटेड लिया. स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित करना लालू यादव के लिए ज़हर हो गया और पशुपति पारस को उप मुख्यमंत्री घोषित करना पासवान के लिए हार का कारण बन गया.

इस फ़ैसले ने बताया कि लालू यादव सिर्फ़ यादवों के हाथ में ताक़त देना चाहते हैं, जैसा उन्होंने अपने पूरे कैंपेन में खुलेआम कहा. इससे बिहार के लोगों को लगा कि लालू यादव कहीं भी अपराधियों पर लगाम लगाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि सत्ता उनके हाथ में देने की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ में इन दिनों नहीं है. लोग कांप गए. तेजस्वी यादव के सभाओं में जाने से लग गया कि अगला मुख्यमंत्री या पार्टी का नेता अब उनका बेटा होगा. लालू यादव की बेटियां और दामाद भी राजनीति में आ सकते हैं, इसने पार्टी में असंतोष बढ़ाया. यादव समाज को लगा कि अब तक रंजन यादव जो कहते रहे हैं, वह सच है कि लालू यादव सारे यादव समाज का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं. रंजन यादव ने पागलपन की हद तक जाकर यादव समाज को बताया कि उनका हित नीतीश के साथ है, लालू यादव के साथ नहीं. लालू यादव के साथ दबंग यादव रह गए, बहुमत नीतीश के साथ चला गया. राबड़ी देवी दोनों जगहों से हार गईं. झाझा में नब्बे हज़ार यादव हैं, वहां लालू यादव का यादव उम्मीदवार हार गया, नीतीश जी का जीत गया. राधोपुर में एक लाख यादव हैं, वहां नीतीश कुमार का यादव उम्मीदवार जीता. यादव समाज ने लालू यादव को छोड़ दिया.

राम विलास पासवान हमेशा मुसलमानों के हितों की बात करते आए, पर फ़ैसले का वक़्त आया तो उन्होंने अपने भाई को उप मुख्यमंत्री घोषित किया, किसी मुसलमान को नहीं. काश वह किसी मुसलमान को पहले घोषित कराते तथा अपने भाई को दूसरा उप मुख्यमंत्री घोषित कराते. परिवार के छह लोगों को खड़ा करना भी कार्यकर्ताओं को उनका लालू यादव के रास्ते पर जाना लगा. पंद्रह सालों तक लालू यादव का साथ देने वाले मुसलमानों को लगा कि लालू सिर्फ़ वायदे करते हैं और पासवान जुबानी जमा ख़र्च करते हैं. मुसलमानों ने इनका साथ छोड़ दिया तथा नीतीश के साथ भाजपा का साथ दे दिया. राम विलास पासवान का चुनावों में अपने बेटे को

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

घुमाना भी वैसा ही माहौल बना गया, जैसा तेजस्वी के लिए बना था. लोग देखने आते थे, पर दोनों के पिताओं की आलोचना करते जाते थे. मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने नीतीश और भाजपा का साथ बहुत सोच-समझ कर दिया है. पंद्रह सालों तक उन्हें कुछ नहीं मिला. इस बार जिस तरह नीतीश ने अति पिछड़ों, महादलितों और महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन किया तथा नौकरियों के दरवाज़े खोले, अब उनके लिए भी खुलेंगे. इसीलिए उन्होंने नीतीश के साथ भाजपा को भी जमकर वोट दिया है. यह आशा कितनी पूरी होगी, पता नहीं, पर अगर नीतीश ने मुसलमानों के लिए भी वैसा ही रास्ता निकाला, जैसा दूसरे वंचित वर्गों के लिए निकाला है तो देश के मुसलमान नीतीश कुमार में अपना एक नया नेता देखना शुरू कर देंगे.

कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई, क्योंकि कांग्रेस कभी अपने उद्देश्य में साफ रह ही नहीं पाई. एक साल से ज़्यादा समय तक रहे अनिल शर्मा ने बिहार कांग्रेस में जान फूंक दी थी. पर बाद में किसके कहने से सारे दलों के खारिज माल को कांग्रेस में शामिल करने का अभियान सा चला. बाद में जगदीश टाइटलर को बिहार का प्रभारी बनाया. उनका अनिल शर्मा से झगड़ा निम्नतम स्तर पर चला गया. कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ख़ामोश रहा. अचानक चार महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक मुसलमान बैठा दिया तथा मुकुल वासनिक को इंचार्ज बना दिया, जिन्हें उत्तर भारत की राजनीति का अ ब स नहीं पता. राहुल गांधी अपने उत्साह में नौजवानों से वायदा करते रहे, पर टिकट उन्हें नहीं मिला. कांग्रेस ने सभी सीटें लड़ीं और सभी हारीं. सिर्फ़ चार लोग अपने बूते जीते. अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव और राम विलास पासवान को बिहार की राजनीति से साफ करने के लिए यह रणनीति बनाई थी. पर लोगों ने तो नीतीश के एजेंडे का समर्थन किया है. कांग्रेस ने पड़ोसी का अपशकुन करने के लिए अपनी आंख फोड़ ली, इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है. कांग्रेस ने बिहार में जानबूझ कर राहुल गांधी को फेल किया या वह स्वयं फेल हो गए, यह कांग्रेस को सोचना है. कांग्रेस को समझना चाहिए कि किसी धर्म या जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देने से उस जाति या धर्म का समर्थन नहीं मिल जाता. योग्यता भी होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक बुद्धिमानी का काम किया कि उसने चुनावों में नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी को नहीं बुलाया. इससे मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार में ताक़त है. साथ ही सुशील मोदी का चेहरा भी और उनकी भाषा भी डरावनी नहीं है. दरअसल सुशील मोदी को बिहार में मुसलमानों सहित दूसरे वर्गों ने विकास का चेहरा माना है. भाजपा में निकट भविष्य में बहस हो सकती है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चले या सुशील मोदी के. इन चुनावों ने सुशील मोदी के रूप में भाजपा को एक सभ्य, सुशील और मोहक राष्ट्रीय नेता दे दिया है.

नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. अगर देखें तो पिछले पांच साल में नीतीश कुमार ने सामान्य मुख्यमंत्री का अच्छा काम किया, पर यह बुद्धिवादी तर्क है. बिहार की जनता ने नीतीश के काम को असामान्य माना. उसे लगा कि बिहार में प्रशासनिक अंधेरा था, विकास का अंधेरा था, क़ानून व्यवस्था का अंधेरा था, उसमें नीतीश ने एक मोमबत्ती जलाई, अंधेरे में आशा की एक किरण. अब उसे लगा कि मोमबत्ती जलाने वाला अंधेरे को मिटाने वाला उजाला भी ला सकता है. यह बात न राम विलास समझे, न लालू यादव और न ही पत्रकार. नीतीश ने जीवनशैली से भी बिहार के लोगों को प्रभावित किया. उनके रिश्तेदार कभी सामने नहीं आए, दिल्ली में वह कभी चकाचौंध में नहीं रहे. कभी उद्योगपतियों और दलालों के साथ नहीं दिखे. ऐसे विधायकों को घास नहीं डाली, जो ट्रांसफर- पोस्टिंग का उद्योग चलाते थे. इसे जनता ने काफी पसंद किया. इतना ही नहीं, नीतीश का मानवीय स्वभाव भी लोगों ने पसंद किया. जार्ज फर्नांडिस ने नीतीश का विरोध किया, संसद का चुनाव लड़ा, नीतीश की पार्टी के सामने दूसरों का समर्थन किया, पर उनकी तबियत ख़राब थी. नीतीश ने उन्हें बुलाकर राज्यसभा में भेजा. दूसरा उदाहरण दिग्विजय सिंह की पत्नी का है. दिग्विजय सिंह और नीतीश में दूरियां विरोध के स्तर तक बढ़ गई थीं. दिग्विजय सिंह का लंदन में देहांत हो गया. उनकी पत्नी पुतुल सिंह का समर्थन नीतीश कुमार ने लोकसभा उपचुनाव में बिना शर्त किया. वह भारी मतों से जीत गईं. आजकल ऐसी सदाशयता राजनीति में देखने में नहीं आती.

लेकिन चुनौतियां हैं. विकास का पहला इम्तहान बड़ी संख्या में सड़कों का बनना है. घर-घर बिजली पहुंचाने का वादा पूरा करना है. पचास लाख एकड़ ज़मीन बीस लाख परिवारों में बांटना है. भूमि सुधारों को लागू करना है. बड़े शिक्षण संस्थान बनवाना है. रोज़गार के अवसर कैसे बढ़ें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैय्या कराना है, ताकि राज्य में विनिवेश हो सके. क़ानून व्यवस्था और बेहतर करनी है. मुसलमानों के लिए वैसी ही योजना बनानी है, जैसी अति पिछड़ों के लिए बनी है. विपक्ष तो नहीं है, इसलिए शिक़ायतों पर ज़्यादा ध्यान देना है. बाहुबलियों को नियंत्रण में रखना है. नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि कोसी की बाढ़ में जान बचाने के लिए सारे बिहार से नावें आई थीं. मल्लाहों ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया. आधी से ज़्यादा नावें वापस नहीं लौटीं. मल्लाहों को न मज़दूरी मिली और न खोई नावों का मुआवज़ा. ये ग़रीब नीतीश की तरफ़ आज भी देख रहे हैं.

इन चुनावों में नीतीश को महिलाओं, अति पिछड़ों और महादलितों ने संगठित होकर वोट दिया. इन्हें पहली बार अपनी ताक़त का एहसास हुआ और इन्होंने पहली बार ही दबंग यादवों और मज़बूत पासवान समाज की आंखों में आंख डाल, जान पर खेल अपने वोट का इस्तेमाल किया. यह समर्थन इतना ताक़तवर होगा और नीतीश कुमार को इतिहास का नायक बना देगा, यह स्वयं नीतीश कुमार को भी पता नहीं होगा.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 39
दिल्ली, 06 दिसंबर–12 दिसंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बिहार चुनाव में नीतीश की आंधी या लहर नहीं, बल्कि चक्रवात नज़र आया. जो राजनीतिक दल जनता को मूर्ख समझते हैं, बिहार चुनाव ने उन्हे सबक दिया है.

अग्निपरीक्षा में बिहार की जनता जीती

मनीष कुमार

बिहार की जनता को झुक कर सलाम करना होगा. बिहार चुनाव के नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया. पहली बार बिहार के लोगों ने यह बताया कि प्रजातंत्र में चुनाव का मतलब नेताओं और राजनीतिक दलों की हार-जीत नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है. यही वजह है कि पहली बार बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया, धर्म की ज़ंजीरें टूट गईं. नीतीश कुमार ने जनता के सरोकार को चुनावी मुद्दा बनाया, वहीं लालू यादव और राम विलास पासवान ने धर्म और जातीय समीकरण पर भरोसा किया. नतीजा आपके सामने है. कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को आगे कर युवाओं और मुसलमानों को अपनी तरफ़ खींचना चाहा, लेकिन वह हर परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए. राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिहार चुनाव से उलझ गया है. कांग्रेस पार्टी यह भूल गई कि बिहार का चुनाव दूसरे राज्यों के चुनाव से अलग है, क्योंकि यहां की जनता राजनीतिज्ञों के इशारों को भी समझती है.

बिहार चुनाव में नीतीश की आंधी या लहर नहीं, बल्कि चक्रवात नज़र आया. जो राजनीतिक दल जनता को मूर्ख समझते हैं, बिहार चुनाव ने उन्हे सबक दिया है. यह उन राजनीतिक दलों के लिए सबक है, जो बिना एजेंडे के, बिना पॉलिसी के, बिना विकास के किसी रोडमैप के, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतते आए हैं. ऐसे ही नेताओं और राजनीतिक दलों को जनता ने नकार दिया. लोगों ने नीतीश कुमार को वोट इसलिए नहीं दिए कि बिहार की सारी समस्याएं ख़त्म हो गईं. बिहार विकसित राज्य बन गया है या फिर अपराध ख़त्म हो गया है. नीतीश कुमार को इसलिए वोट मिला, क्योंकि लोगों को लगा कि यही एक नेता है, जो बिहार को विकास की राह पर ले जा सकता है.

किसी भी विश्लेषक के लिए बिहार का चुनाव हमेशा से जटिल रहा है. चौथी दुनिया ने बिहार में एक चुनावी सर्वे किया था. यह सर्वे 20 से 29 सितंबर, 2010 के बीच किया गया, जिसे हमने 11-17 अक्टूबर के अंक में छापा था. चौथी दुनिया का सर्वे जिस समय किया गया, उस वक़्त मुख्य उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी. चुनाव में लोग अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का व्यक्तित्व और व्यवहार आदि बिंदु बहुत मायने रखते हैं. इसके अलावा बिहार के चुनावों को पढ़ पाना इसलिए भी जटिल हो जाता है, क्योंकि यहां मुद्दों से ज़्यादा जातिगत स्तर पर वोटिंग होती है. उस वक़्त किए गए सर्वे के मुताबिक़, जनता दल यूनाइटेड एवं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 130 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल एवं लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को 95 सीटें मिलने की उम्मीद थी. अब यह सवाल है कि 29 सितंबर के बाद ऐसा क्या हो गया कि सारे समीकरण बदल गए. नीतीश कुमार ने जादू की वह कौन सी छड़ी घुमाई कि उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हो गई और लालू यादव एवं राम विलास पासवान से ऐसी क्या ग़लती हुई, जिससे उनकी सीटें 95 से 25 पर पहुंच गईं. समझने वाली बात यह है कि जितने वोटों से एनडीए की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी को उतने वोट भी नहीं मिले.

जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ऐसी जीत इसलिए हुई, क्योंकि बिहार की जनता यह मानती है कि नीतीश कुमार की सरकार लालू यादव की सरकार से काफ़ी बेहतर है. चौथी दुनिया के सर्वे में 73 फ़ीसदी लोगों ने इस बात को माना था और सिर्फ़ 12 फीसदी लोगों को यह लगता था कि लालू यादव की सरकार नीतीश सरकार से बेहतर थी. इसका मतलब यह है कि लोग जब वोट देने गए तो उनके दिमाग में जाति और धर्म से ज़्यादा सरकार का परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण रहा. इसके अलावा लोगों की राय यह है कि पिछले पांच सालों में अपराध कम हुआ है. यही वजह है कि नीतीश सरकार को लोगों का ज़्यादा समर्थन मिला. चौथी दुनिया के सर्वे में 56 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि पिछले पांच सालों में संतोषजनक विकास हुआ है. 28 फ़ीसदी लोगों का कहना था कि पिछले पांच सालों में विकास नहीं हुआ है. जिन लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ है, वे साथ-साथ यह भी कह रहे थे कि नीतीश सरकार बेहतर सरकार है. लालू प्रसाद यादव ने ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताकर लोगों को फ़ैसला आसान कर दिया. उन्हें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में एक को चुनना था. लालू यादव के चेहरे के साथ-साथ 15 सालों का कुशासन भी याद आया, इसलिए लोगों ने नीतीश को चुना.

चुनाव के नतीजे आने से पहले तक यह माना जा रहा था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं, लेकिन चौथी दुनिया के सर्वे से यह पता चला कि 23 फीसदी मुसलमानों का भी वोट जदयू-भाजपा गठबंधन को मिलेगा. उर्दू टीचरों की बहाली की वजह से मुसलमानों में नीतीश सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है. लेकिन जो मुसलमान लालू यादव और राम विलास पासवान के समर्थक थे, उन्हें झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं मिला. बिहार में 54 सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमानों की जनसंख्या 20 फ़ीसदी से ज़्यादा है. इन सीटों में से 43 सीटें जदयू-भाजपा गठबंधन को मिलीं. हैरानी की बात यह है कि इस गठबंधन को मिली सीटों में से 30 भारतीय जनता पार्टी और 13 जनता दल यूनाइटेड ने जीतीं. इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने पहली बार भाजपा को जमकर वोट दिया. भारतीय जनता पार्टी से सबा जफर ने जिस सीट (अमौर) से चुनाव जीता, वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 70 फ़ीसदी है. पहली बार मुसलमानों ने अपने धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों से बाहर निकल कर बिहार राजनीति की मुख्यधारा में आकर वोट दिए. मुसलमानों ने यह संदेश दिया है कि बिहार में उन्हें बाबरी मस्जिद, उर्दू की बढ़ोत्तरी, नौकरी में रिजर्वेशन, मदरसों को सहयता से पहले बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था चाहिए. यह संदेश उन राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है, जो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का हौवा खड़ा कर मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते. बिहार की यह हवा अगर पूरे देश में फैल गई तो कई पार्टियों की टोपी उड़ जाएगी. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 55 से बढ़कर 91 हो गईं और लालू प्रसाद यादव एवं राम विलास पासवान अपने परंपरागत वोटरों को खो बैठे, जिससे भीषण नुकसान हुआ.

चौथी दुनिया के सर्वे में यह भी पूछा गया कि क्या चुनाव में राहुल फैक्टर का असर होगा तो सिर्फ़ 36 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का बिहार में असर होगा. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन किया, जिस तरह बिना किसी योजना और बिना किसी रोडमैप के लोगों के बीच गए, उससे लोग राहुल गांधी से भी निराश हो गए. यह बात नतीजे से सच साबित होती है. हमें यह याद रखना चाहिए कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी के विजन, संगठन शक्ति, लोकप्रियता और चुनाव जिताने की क़ाबिलियत की अग्निपरीक्षा था. बिहार में सफलता का मतलब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ़ होना था. बिहार में राहुल गांधी फेल हो गए हैं, यह जानने के लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार नहीं करना पड़ा. नतीजे आने से दो सप्ताह पहले के चौथी दुनिया के अंक में हमने ही यह लिख दिया था कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं. राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में पहली बार बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. संगठन को मज़बूत करने में पूरी ताक़त लगा दी. राहुल के कई नजदीकी सलाहकार बिहार में कई महीने पहले से कैंप कर रहे थे. राहुल गांधी और उनके आभामंडल के इर्द-गिर्द की सारी तैयारियों, युवा भारत का सर्वमान्य नेता बनने की उनकी रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने भी बिहार में कैंपेन किया. कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए हुई कि बिहार के लोगों को यह बात समझ में आ गई कि मामला किसानों का हो या फिर उड़ीसा के नियमगिरि के आदिवासियों का, राहुल गांधी के नज़रिये और केंद्र सरकार की नीतियों में मतभेद है. राहुल गांधी ग़रीबों, किसानों और आदिवासियों के साथ नज़र आने का प्रचार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की लाइन दूसरी है. राहुल गांधी की कथनी और केंद्र सरकार की करनी में ज़मीन-आसमान का अंतर है. बिहार के मुसलमानों को भी यह समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की इच्छुक नहीं है. इसलिए राहुल गांधी जहां गए, भीड़ तो हुई, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ़ देखने आए. किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए राहुल गांधी के नाम पर लोगों ने वोट नहीं दिया. दक्षिण भारत में ऐसी कलाबाज़ियां छिप जाती हैं. बिहार में यह खेल कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ गया. जो वोट कांग्रेस को मिलने थे, वे भी नीतीश की झोली में चले गए. ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की चुप्पी ने कर दिया.

ऐसा नहीं है कि बिहार में पिछले पांच सालों के दौरान सब कुछ ठीकठाक था. कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जिन्हें लेकर बिहार की जनता सरकार से नाराज़ है. जैसे बिजली की समस्या. ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पिछले पांच सालों में बिजली की समस्या बद से बदतर हो गई है. साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग निराश हैं. उन्हें लगता है कि नीतीश सरकार के दौरान अधिकारी पहले से ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं. कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं में अब गांव के लोग भी भ्रष्टाचार के मायाजाल के हिस्सेदार हो गए हैं. जिस मुद्दे को लालू प्रसाद यादव और राम विलास पासवान को उठाना था, उस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठा दिया. चुनाव प्रचार के दौरान अपनी ख़ामियों के लिए जनता से उन्होंने माफ़ी भी मांगी. वह जहां गए, उन्होंने यही कहा कि पिछले पांच सालों में उन्होंने अपराध कम किया है और अगले पांच सालों में वह भ्रष्टाचार का ख़ात्मा करेंगे. लोगों ने नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा किया. यही वजह है कि नीतीश कुमार धीरे-धीरे अपनी सीटें 130 से बढ़ाते चले गए.

चुनावी इतिहास में ऐसे मौक़े कम आते हैं, जब सदन में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली होती है. नेता विपक्ष बनने के लिए 10 फ़ीसदी सीटें पाना ज़रूरी है. बिहार में किसी भी पार्टी के पास 10 फ़ीसदी सीटे नहीं हैं. इस बार बिहार में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी. अब नीतीश कुमार इस स्थिति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह उन भर निर्भर करता है. ख़तरा इस बात का है कि नई सरकार कहीं निरंकुश न हो जाए.

manish@chauthiduniya.com

15 नवंबर-21 नवंबर 2010 के अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी

सभी फोटो- प्रभात पाण्डेय

आर पी यादव

सिर्फ़ आर पी यादव पर ही क्यों गिरी गाज?

फर्डिनो इलैकियो रिबेलो

संतोष श्रीवास्तव

आर सी सिन्हा

उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विसेज़ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आर पी यादव को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है. सैकड़ों करोड़ रुपये के पीएफ घोटाले में दाग़ी जज आर पी यादव को उत्तर प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विसेज़ ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया था. फिर ऐसा कौन सा क़ानूनी बखेड़ा अचानक आ खड़ा हुआ कि शासन को उन्हें बर्खास्त करने का फ़ैसला करना पड़ा? पीएफ घोटाले में दाग़ी जजों की सूची लंबी-चौड़ी है, फिर अकेले आर पी यादव ही क्यों? इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा, पर अभी यही रंग देने की कोशिश है कि पीएफ घोटाले में दाग़दार होने की वजह से उन्हें ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद से हटाया गया है. अभी पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फर्डिनो इनैकियो रिबेलो लखनऊ में ही थे. शासन ने उनसे सीधे कहा कि न्यायिक प्रशासन के भी प्रमुख होने के नाते वह जस्टिस आर पी यादव को इस्तीफ़ा देने के लिए कहें, अन्यथा शासन की ओर से जस्टिस यादव के खिलाफ एक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ...और जस्टिस आर पी यादव को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा. एक दिसंबर से उनका इस्तीफ़ा लागू मान लिया जाएगा. जस्टिस यादव का इस्तीफ़ा भले ही एक दिसंबर से मंजूर माना जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में उनका काम पहले से ही रोक दिया गया है. स्टेट पब्लिक सर्विसेज़ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के बतौर श्री यादव का कार्यकाल 14 जुलाई 2011 तक था, लेकिन आठ महीने पहले ही राज्य सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया.

ट्रिब्यूनल के वरिष्ठ मुख्य प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (सीनियर चीफ प्रेजेंटिंग अफसर) आर सी सिन्हा और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव को भी राज्य सरकार ने बर्खास्त करने का फरमान जारी किया है. ट्रिब्यूनल के वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की बर्खास्तगी के आदेश से राज्य सरकार सवालों के घेरे में फंस गई है. जस्टिस आर पी यादव को अगर पीएफ घोटाले में दाग़दार होने की वजह से बर्खास्त किया गया तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को निकाले जाने की आख़िर क्या वजह है? ऐसी कौन सी गहरी नाराज़गी है, जिस वजह से सरकार ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एवं दो वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया? इन सवालों का जवाब अपेक्षित है. आपको यह जानकारी दे दें कि स्टेट पब्लिक सर्विसेज़ ट्रिब्यूनल की 13 सदस्यीय प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की टीम में आर सी सिन्हा सबसे वरिष्ठ हैं और टीम के प्रभारी भी. श्री सिन्हा 1998 से ही ट्रिब्यूनल की विधिक सेवा में हैं. दोनों प्रेज़ेंटिंग अफसरों को न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने अपने आदेश (संख्याः ए-286/सात-न्याय-8-10-24/28/88, दिनांक-11.11.2010) के ज़रिए सेवा से बर्खास्त (आबंधन रद्द) करने का फ़रमान जारी किया.

उल्लेखनीय है कि पीएफ घोटाला मामले में सीबीआई ने तीन जुलाई 2010 को 78 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों आर पी यादव, आर एन मिश्रा एवं ए के सिंह और ग़ाज़ियाबाद के तीन ज़िला जजों आर पी मिश्रा, आर एस चौबे एवं अरुण कुमार अभियुक्त बनाए गए. सीबीआई की जांच के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना समेत अन्य कई अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और सबूत वग़ैरह जुटाने का काम बहुत हद तक पूरा कर लिया था. पीएफ घोटाले के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना का इक़बालिया बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत बाक़ायदा ग़ाज़ियाबाद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की मौजूदगी में दर्ज किया गया था. बाद में मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई. सीबीआई ने जांच की और कहा कि 41 जजों और न्यायिक अधिकारियों में से 17 के ख़िलाफ़ ठोस सबूत नहीं मिल पाए. शेष 24 जजों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस नहीं बनता, केवल विभागीय कार्रवाई का मुकम्मल मामला बनता है. इन 24 जजों में एक सुप्रीमकोर्ट के जज भी शामिल हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं. कुल 78 लोगों के ख़िलाफ़ सीबीआई ने चार्जशीट दाख़िल की, इसमें छह रिटायर्ड न्यायाधीश शामिल हैं.

सीबीआई ने कहा कि पीएफ घोटाले के दौरान ग़ाज़ियाबाद की अदालत में तैनात रहे और जांच के घेरे में आए 17 जजों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिले हैं. जिन जजों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें से दो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं और एक घोटाले के समय हाईकोर्ट के महापंजीयक थे. जिन्हें सीबीआई की क्लीन चिट मिली, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद निगम, न्यायाधीश विष्णु सहाय एवं घोटाले के दौरान रजिस्ट्रार जनरल रहे पी के गोयल शामिल हैं. इसके अलावा घोटाले के वक़्त ग़ाज़ियाबाद में अतिरिक्त ज़िला जज के पद पर तैनात रहे आर ए कौशिक, हमीदुल्लाह, सी के त्यागी, सुभाष चंद अग्रवाल, निर्विकार गुप्ता, अशोक कुमार चौधरी, श्रीप्रभु, ए के अग्रवाल, रमेश चंद सिंह और ग़ाज़ियाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे वी के श्रीवास्तव, कौशलेंद्र यादव, अखिलेश दुबे, हिमांशु भटनागर एवं वी एस पटेल शामिल हैं. सीबीआई ने 24 न्यायाधीशों पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन इसका शिकार अकेले आर पी यादव ही क्यों बने? सवाल सामने है...

प्रभात रंजन दीन
prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

बिहार से अलग उत्तर प्रदेश में छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल कह लें या जातीय छत्रप, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार दर्ज हो रही है.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव परिणाम

गठबंधन से लड़ने-लड़ाने की चुनौती

प्रभात रंजन दीन

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी घोषित हुए. इसके पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, जिसे विधानसभा चुनाव के पहले का रिहर्सल मानकर पूरे उत्साह से लड़ा गया. पंचायत चुनावों के परिणामों को लेकर हो रही खींचतान और दावे-प्रतिदावे 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ट्रेलर के बतौर देखे जा रहे हैं. लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी सचेत-सतर्क कर दिया है. अब यहां के मतदाताओं में भी इस बात पर बहस होने लगी है कि उत्तर प्रदेश का विकास कौन कर सकता है...और विकास के अलावा चुनाव का दूसरा कोई आधार नहीं होना चाहिए. बिहार के चुनाव परिणाम और उत्तर प्रदेश में उसे लेकर हो रही व्यापक चर्चाओं का असर राजनीतिक दलों पर भी है, ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में. बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा अलग, उत्तर प्रदेश में छोटे जातीय राजनीतिक छत्रपों की सक्रियता अधिक है और अब वे नए सिरे से विकास के मुद्दे पर ही सही, लेकिन विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी के सवाल पर एकजुट होने लग गए हैं. प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी बड़ी मौजूदगी का एहसास सभी बड़ी पार्टियों को करा ले गए हैं. उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी तक़रीबन दो वर्ष बाक़ी हैं. 2007 में भारी बहुमत से सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी पत्थर की मूर्तियों का जाल बिछाने के आर्थिक अपव्यय और भीषण भ्रष्टाचार को लेकर विकास के सवालों में जिस बुरी तरह घिरी है, उससे उबरने की मायावती की छटपटाहट अब दिख रही है. मायावती ने विकास के वे काम सामने उठाए हैं, जो सड़क पर लोगों को दिखें और प्रभावित करें, मसलन लखनऊ शहर का सौंदर्यीकरण, सरकारी कर्मचारियों को भत्ते आदि का प्रलोभन वग़ैरह. लेकिन शहर और गांवों के बीच जो विकास और राजनीतिक व्यवहार का भेद सामने खड़ा हुआ है, वह विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त भूमिका अदा करने वाला है. आधारभूत ढांचे को लेकर बिहार पूरे देश में निंदा और हास्य का पात्र बनता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों से होकर गुजरें या शहरों-कस्बों में जाएं तो भीषण अव्यवस्था और आधारभूत ढांचे के जर्जर होने का आपको अनुभव मिलेगा. तब आपको यह एहसास होगा कि बिजली की चकमक और पानी से धोई गई सड़क का सर्राटा केवल राजधानी लखनऊ में है और वह भी केवल सत्ता गलियारे के नजदीक. बाक़ी जगह ऊबड़-खाबड़ सड़कें, गंदगी, कूड़े का अंबार और अंधेरा. अब मतदाता स्पष्ट तौर पर यह सवाल उठाने लगा है कि कुलीन वोट और मलिन वोट अलग-अलग नहीं होता, शहरी वोट और ग्रामीण वोट अलग-अलग नहीं होते, फिर सुविधाएं अलग-अलग क्यों?

बहरहाल, उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा ने आधिकारिक तौर पर अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था. मायावती ने यह फ़ैसला पहले ही ले लिया था. लेकिन इस फ़ैसले के पीछे राजनीतिक उदारता कोई वजह नहीं थी, बल्कि ख़ुफ़िया एजेंसियों की वे ख़बरें थीं, जो आम आदमी की प्रतिक्रिया और रुझान से सत्ता को लगातार अवगत करा रही थीं. पंचायत चुनावों में भी सत्ताधारी दल भगदड़, अनुशासनहीनता और फ़ज़ीहतें झेल चुका था. लिटमस टेस्ट के लिए लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बसपा ने अपना अ(न)धिकृत उम्मीदवार उतारा, लेकिन इसमें भी पार्टी का तथाकथित कठोर अनुशासन सार्वजनिक रूप से बिखर गया. बसपा के सक्रिय सदस्य पवन गुप्ता बसपाई रंगों के साथ मैदान में जुटे और बसपा के (अ) घोषित प्रत्याशी के बतौर मैदान में डटे रहे. यहां भी दो बसपाइयों में टक्कर हो गई और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के इरादे से बसपा ने पवन गुप्ता को पार्टी से निकालने तक का ऐलान कर दिया. फिर अब्दुल अजीज उर्फ़ राजे सिद्दीकी बसपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन पवन को राजे सिद्दीक़ी से काफ़ी अधिक वोट हासिल हुए और बसपा को ज़मीनी टेम्परेचर का पता चल गया. यही हाल एटा के निधौलीकलां विधानसभा उपचुनाव में भी हुआ. इन दोनों विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी बसपा एवं अचानक कुबेर हो गए स्थानीय बसपा नेताओं के प्रति लोगों का गुस्सा स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त हुआ. निधौलीकलां में बसपा ने कल्याण सिंह की पार्टी को अपना समर्थन देकर क़र्ज़ा चुकाने की कोशिश की. कल्याण सिंह ने खुली सभा में बसपा से क़र्ज़ा चुकाने का आह्वान भी किया था. कल्याण सिंह का वह आह्वान और उनका क़र्ज़ा चुकाने के लिए किया गया समर्थन, यह सब गठबंधन की अनिवार्यता के ही संकेत दे रहे हैं.

इन दो उपचुनावों में राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा, दोनों की ख़ूब फजीहत हुई. यह साफ़ ज़ाहिर हुआ कि किसी ताक़तवर क्षेत्रीय दल का साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी राष्ट्रीय दल का सत्ता में आना मुश्किल है. जदयू-भाजपा गठबंधन की तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसे किसी ताक़तवर गठबंधन का रास्ता फिर से खुल रहा है. इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के वरिष्ठ नेता गंभीरता से विचार कर रहे हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के कुछ वरिष्ठ नेताओं से इस मसले पर चौथी दुनिया की बातचीत हुई, फ़िलहाल वे ज़ाहिराना तौर पर कुछ बोलना पार्टी हित में नहीं मानते, लेकिन ऐसे समीकरण की ज़रूरत पुरज़ोरी से महसूस करते हैं और कहते भी हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है. इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं से हुई चर्चा का लब्बोलुबाव निकालें तो कांग्रेस-सपा और भाजपा-बसपा के बीच गठबंधन का सिरा मिलता दिखता है. हालांकि ज़ाहिर तौर पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाकर रखेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और 2012 के चुनाव में सत्ता में आएगी. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी. बिहार चुनाव के परिणाम और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के परिणामों की अखिलेश अलग समीक्षा करते हैं. कहते हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम ने यह दिखाया कि जातीयता टूट रही है और विकास पर वोट हो रहा है. इसका असर केवल बिहार पर थोड़े ही पड़ेगा, यह उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी असर डालेगा और जाति या धर्म की राजनीति करने वालों को धोएगा. अखिलेश प्रताप कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती थी, लेकिन राहुल ने बेहतर गवर्नेंस के आधार पर वोट डालने का एजेंडा जनता के समक्ष पेश किया. जनता ने भी वही किया. राहुल का ही एजेंडा चला. बिहार में जो बेहतर गवर्नेंस दे रहा था, लोगों ने उसे वोट देकर सत्ता पर बैठाया. उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए, वे तो सहानुभूति वाले चुनाव थे. विधायकों के निधन से खाली हुई सीटों पर राजनीति काम नहीं करती, सेंटिमेंट काम करता है. फिर भी कांग्रेस का वोट बढ़ा है, घटा नहीं. बहरहाल कांग्रेस, सपा या भाजपा किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, वे गठबंधन की संभावनाओं से अभी तो इंकार करते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म राजनीतिक बाध्यता होती जा रही है, इससे वे सहमत भी होते हैं.

बिहार से अलग उत्तर प्रदेश में छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल कह लें या जातीय छत्रप, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार दर्ज हो रही है. लिहाज़ा इन छोटे छत्रपों की उपेक्षा कर किसी बड़े राजनीतिक दल को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली. लखीमपुर सदर और निधौलीकलां विधानसभा सीट और उसके पहले डुमरियागंज उपचुनाव में भी छोटे दलों ने अपनी मज़बूत शिनाख्त दर्ज कराई और अपने प्रत्याशी को जितवाने में नहीं, बल्कि बड़े दलों के प्रत्याशियों को हरवाने का काम ज़रूर किया. लखीमपुर सदर में पीस पार्टी के प्रत्याशी शशिधर मिश्रा उर्फ नामे महाराज की वजह से कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें तक ज़ब्त हो गईं. यही हाल निधौलीकलां में हुआ, जहां कल्याण सिंह की जनक्रांति पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद अन्य दलों के प्रत्याशियों की जमानतें ज़ब्त करा दीं. आपको याद होगा कि डुमरियागंज उपचुनाव में भी पीस पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडेय ने सारी पार्टियों के राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर डाले थे. लखीमपुर सदर और निधौलीकलां दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन छोटे क्षेत्रीय दलों की ही बदौलत. लखीमपुर खीरी में पीस पार्टी की बदौलत और निधौलीकलां में जनक्रांति पार्टी की बदौलत. छोटे दलों के कारण राजनीतिक समीकरण किस तरह बदल रहे हैं और नई शक्ल ले रहे हैं, यह लखीमपुर सदर के चुनाव में सामने आया. यहां पीस पार्टी के कारण मुस्लिम वोट (ख़ास तौर पर अंसारी वोट) एक तरफ़ पोलराइज़्ड हुआ तो उसे बैलेंस करने के लिए सारे हिंदू वोट सपा की तरफ़ केंद्रित हो गए. लिहाज़ा आप यह भी कह सकते हैं कि लखीमपुर सदर में समाजवादी पार्टी हिंदू (ग़ैर ब्राह्मण) वोटों के कारण जीत गई. निधौलीकलां में समाजवादी पार्टी हिंदू वोटों के बिखरने की वजह से जीत गई. कल्याण सिंह और भाजपा फैक्टर में हिंदू वोटों के बंटने का फ़ायदा सपा को मिल गया. यानी यहां भी छोटे दल की भूमिका ही जीत और हार की वजह बनी.

इन छोटे, किंतु प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर चलने की राजनीतिक ज़रूरत अमर सिंह के मैदान में आने के कारण और शिद्दत से महसूस की जाने लगी है. नए सिरे से पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का मसला, छोटे दलों की एकजुटता का मसला और सुविधाओं में कुलीन बनाम मलिन का मसला गरमाने लगा है. छोटे छत्रपों को साथ लेकर अमर सिंह नए सिरे से उभरने की कोशिशों में लग गए हैं, निश्चित तौर पर उनकी यह सक्रियता मिशन 2012 ही है. हालांकि राजनीतिक-प्रशासनिक उपेक्षा के सवाल पर शहर बनाम गांव का मसला सबसे पहले राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पारख महासंघ ने उठाया और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं और जनप्रतिनिधि चुनने वाले मतदाताओं की उपेक्षा के सवाल पर प्रदेश भर में सभाएं, धरना-प्रदर्शन भी आयोजित किए. अब पूर्व सांसद इलियास आजमी ने भी इनके समर्थन में साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है. इसी समर्थन की निशानदेही पर राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवं पारख महासंघ के अध्यक्ष कौशल किशोर को लखीमपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़वाया गया. प्रदेश के विकास और शहर बनाम गांव के सवाल और सत्ता वंचित जातियों को राजनीति की मुख्यधारा में शामिल करने के मसले पर यही छोटे दल अब उत्तर प्रदेश में एमपीएम समीकरण दुरुस्त करने में लग गए हैं. ठीक उसी तरह, जिस तरह बिहार में तेजी से एमएमएम समीकरण उभरा और सारे सत्ता समीकरण ध्वस्त कर दिए. बिहार में मुस्लिम-मध्यम वर्ग और महिला समीकरण लालू के ख़िलाफ़ अधिक प्रतिक्रियात्मक तरीक़े से एकजुट हुआ. उसी तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम-पासी-महादलित समीकरण दुरुस्त करने की ग्रासरूट स्तर पर तेजी से कोशिशें हो रही हैं. पूर्व सांसद इलियास आजमी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ-साथ सभी सत्ता वंचित जातियों और महादलितों को एकजुट किया जा रहा है. इस व्यापक एकजुटता में पासी, मुस्लिम, लोनिया, कहार, लोध, गड़रिया, मौर्य, कुम्हार, चौरसिया, बनिया, बढ़ई, लोहार, साहू, कोरी, खटिक, कलवार, नाई, भुर्जी, धोबी एवं धानुक जैसी सत्ता वंचित जातियां शामिल हो रही हैं. राजभर व कई अन्य ऐसी जातियों को लेकर चलने वाले दलों को भी इसमें शामिल करने के लिए बातचीत हो रही है. पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश की तमाम मुस्लिम तंजीमों से भी बात हो रही है और यह बातचीत ठोस शक्ल ले चुकी है. मुस्लिम तंजीमें भी यह समझती हैं और समझदार मुसलमान यह जानता है कि मुरादाबाद में 1980 में ईदगाह पर हुई फायरिंग के विरोध में मैंने लखनऊ से दिल्ली तक पदयात्रा की थी. इसी दौरान मेरी पत्नी का निधन हो गया और मैं उनके अंतिम संस्कार में भी शरीक नहीं हो सका. उपचुनावों में पीस पार्टी की भूमिका और मुस्लिमपरस्त बयानबाज़ियों पर आजमी ने तल्खी से कहा कि पीस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की डमी पार्टी है.

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बसपा सरकार ने जिन आदिवासी जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कीं और पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया, उन्हें भी साथ लेने की ठोस पहल हो रही है. आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल हुई जातियों के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण देने, अन्यथा पंचायत चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन मायावती सरकार इसके ख़िलाफ़ सुप्रीमकोर्ट चली गई और वहां से उसने चुनाव कराने की हरी झंडी ले ली थी. जनसंघर्ष मोर्चा के दिनकर कपूर भी कहते हैं कि जनजातियों के प्रति बसपा सरकार के अलोकतांत्रिक रुख़ के ख़िलाफ़ लोगों में काफी नाराज़गी है. गोंड, खरवार, पनिका, चेरो, अगरिया, भुइयां, बैगा, कोल, धांगर, उरांव, कोरवा, करहिया जैसी कई उपेक्षित जनजातियों की इस नाराज़गी को राजनीतिक एकजुटता में लाने और उन्हें उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

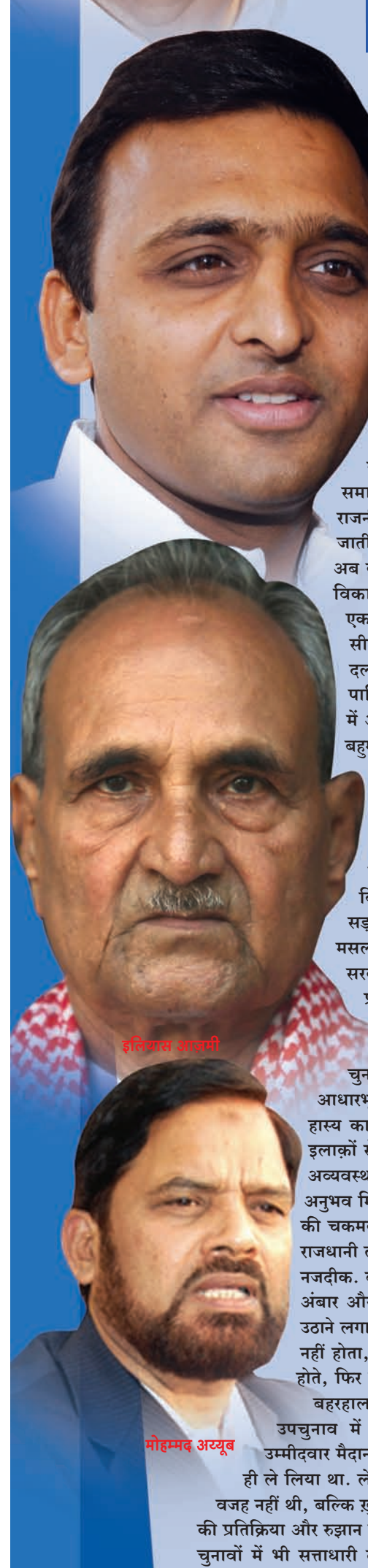

इलियास आज़मी

मोहम्मद अय्यूब

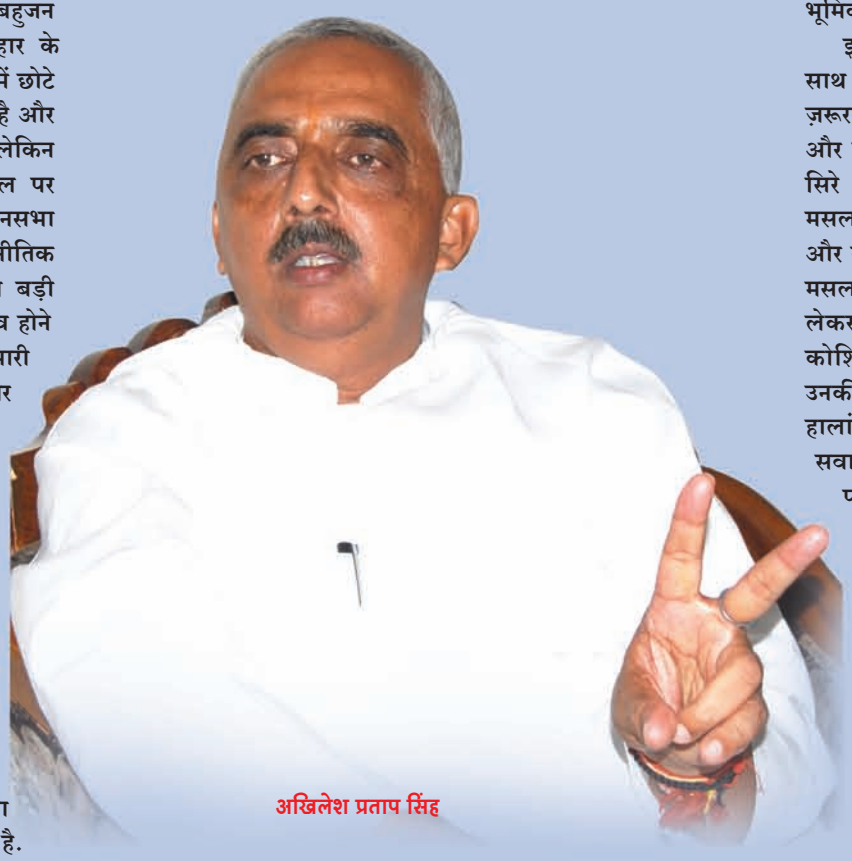

अखिलेश प्रताप सिंह

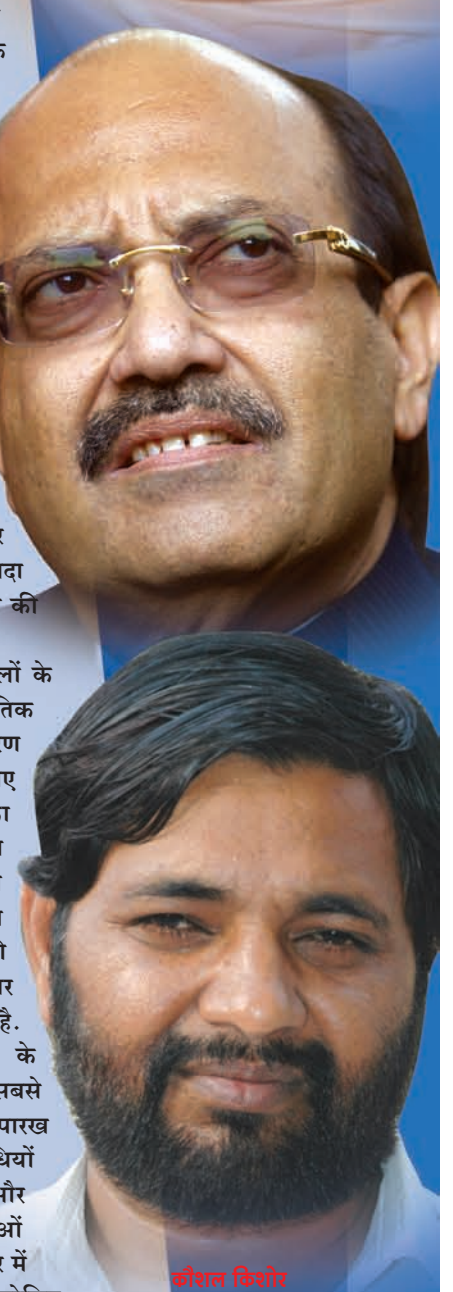

कौशल किशोर

पीस पार्टी भाजपा की डमी!

उपचुनावों में राजनीतिक समीकरण ध्वस्त करने वाली पीस पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी की डमी पार्टी है? पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ इलियास आजमी का यह आरोप बहुत गंभीर है. हाल के विधानसभा उपचुनावों में पीस पार्टी द्वारा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बनाने की कोशिशों के बावजूद भाजपा को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया, लेकिन पीस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पृष्ठभूमि के लोगों को उपचुनावों में टिकट दिए जाने की शिक़ायतें विचारणीय तो हैं ही. इलियास आजमी का कहना है कि लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पीस पार्टी के प्रत्याशी शशिधर मिश्रा उर्फ नामे महाराज आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं. यह बात किसी से भी तस्दीक की जा सकती है. उन्होंने कहा कि डुमरियागंज उपचुनाव में भी पीस पार्टी ने जिस सच्चिदानंद पांडेय को टिकट दिया था, वह आरएसएस के सदस्य रहे हैं और उन्होंने बाबरी मस्जिद की ईंट अपने शौचालय में लगवाई थी. पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी ने श्रावस्ती से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था, वह भी संघ का काडर रहा है.

कनि को पहले पकड़ना पड़ेगा. करुणानिधि को तीन मंत्रिमंडल सीटों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कबाड़ा किया हुआ है.

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल-II

नीरा राडिया के बरखा दत्त एवं वीर सांघवी जैसे बड़े पत्रकारों के साथ गठजोड़ के बारे में चौथी दुनिया ने महीनों पहले अपने पाठकों को बताया था कि कैसे सुपर दलाल नीरा राडिया ने इन प्रसिद्ध पत्रकारों का इस्तेमाल कुछ कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने और ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के लिए किया. इसके बाद चौथी दुनिया के पास कई पाठकों के पत्र आए, जो नीरा राडिया एवं प्रभु चावला, वीर सांघवी एवं बरखा दत्त जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों के बीच हुई बातचीत को सुनना चाहते थे. हमने इनके बीच हुई बातचीत को अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध टेप से साभार लिया है. प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके पास इन तीनों पत्रकारों और नीरा राडिया के बीच हुई बातचीत के हज़ारों घंटे के टेप उपलब्ध हैं.

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त के बीच हुई बातचीत

राडिया : नमस्ते, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया?
बरखा: नहीं, मैं जगी हुई थी.
राडिया: हां सुनो, बात यह है कि उन्हें उससे ही बात करनी है, समस्या इसी वजह से है.
बरखा: हां, लगता है पी एम वास्तव में इस बात से नाराज़ हैं कि वह जनता में गए.
राडिया: पर वह तो बालू कर रहा है न, करुणानिधि ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा है.
बरखा: ओह, उन्होंने नहीं कहा?
राडिया: नहीं. उसे बाहर आकर यह कांग्रेस आलाकमान को बताने को कहा गया था.
बरखा: और वह जनता में चला गया?
राडिया: अच्छा, मीडिया बाहर थी.
बरखा: हे भगवान, अब? मैं उनसे क्या कहूं? तुम्हीं बताओ मैं क्या कहूं उनसे?
राडिया: मैं तुम्हें बताती हूं समस्या क्या है. मेरी उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों से बात हुई.
बरखा: हां, हां.
राडिया: समस्या यह है कि किसी और से नहीं, कांग्रेस को बालू से परेशानी है, उन्हें जाकर करुणानिधि से बात करनी चाहिए. करुणानिधि से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं.
बरखा: सही, हां.
राडिया: तुमने देखा होगा, क्योंकि बालू और मारन के सामने वे नहीं बात कर सकते.
बरखा: हां.
राडिया: इसलिए उसे सीधे ही बताना होगा. तमिलनाडु में बहुत से कांग्रेसी नेता हैं. उन्हें वहां जाकर उसे सब कुछ बताना होगा. उन्हें चाहिए कि वह सीधे जाकर अपनी बात कहें.
बरखा: वह ठीक है, पर क्या करुणा बालू को छोड़ देगा?
राडिया: देखो, अगर तुम उसे कहोगे कि बालू ही एक अकेली समस्या है, मुझे पता है वह उन्हें हटा देगा.
बरखा: पर यह देखो कि अभी तो पोर्टफोलियो को लेकर भी समस्या है न.
राडिया: नहीं. उन्होंने कुछ नहीं कहा है. पोर्टफोलियो के बारे में तो बात भी नहीं हुई.
बरखा: कांग्रेस का दावा है कि जो भी हो, डीएमके भूतल परिवहन, बिजली, आईटी, दूरसंचार, रेलवे और स्वास्थ्य चाहता था.
राडिया: और कांग्रेस मीडिया और बाक़ी माध्यम से यह सूचना फैला रही है कि मारन सबके बीच में अकेला स्वीकार्य व्यक्ति है.
बरखा: वो...हां हां हां...यह मुझे पता है.
राडिया: पर यह ठीक नहीं है न?
बरखा: नहीं, मुझे पता है, हमने वह हटा लिया है.
राडिया: लेकिन कांग्रेस को करुणानिधि को यह भी बताना होगा कि हमने मारन के बारे में कुछ नहीं कहा है.
बरखा: ठीक है, मुझे उनसे दोबारा बात करने दो.
राडिया: हां, उम्मीदवारों का चुनाव हम तुम पर छोड़ते हैं. बालू केबारे में हमारी कुछ आपत्तियां हैं, उन्हें आपत्तियों के बारे में बता दो. और हमने मारन के बारे में कुछ नहीं कहा है.

बरखा दत्त नीरा राडिया को एक विश्वसनीय बिचौलिया बनने का आश्वासन देती हैं.

22 मई, 2009 10:47:33
बरखा: हां नीरा?
राडिया: बरखा, मैंने कल तुमसे कांग्रेस के बारे में जो कहा था न, जाने वे डीएमके में किसके बारे में विचार कर रहे हैं?
बरखा: हां...मारन ही होगा.
राडिया: नहीं, वे कहते हैं कि बुनियादी पोर्टफोलियो मारन या बालू को नहीं दिया जाना चाहिए.
बरखा: नहीं. ऐसा इसलिए है कि वे यह पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते हैं.
राडिया: उन्हें राजा को टेलीकाम देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
बरखा: ओह, अच्छा!
राडिया: उन्होंने शायद यह बात किसी और से कही होगी या मारन से कहा होगा, जो सच नहीं बता रहा है.
बरखा: मेरे ख़याल से मारन से कहा होगा.
राडिया: हां. तो अब होना यह चाहिए कि वे कनि से बात करें, जिससे वह अपने पिता के साथ चर्चा कर सके, क्योंकि यहां तक कि प्रधानमंत्री और करुणानिधि के बीच बातचीत को भी उनकी बेटी ही अनुवाद कर रही थी और यह चर्चा बहुत छोटी थी...मिनट की.
बरखा: ओ के.
राडिया: हमें इसे दुरुस्त करना होगा और जल्दबाज़ी में ऐसा कोई फ़ैसला न हो, जो हम लोगों के हक़ के विरुद्ध हो.
बरखा: नहीं, वे जैसे ही बैठक से बाहर आते हैं, मैं करती हूं.
राडिया: पता है, वह यह कह रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा कोई सीनियर ही यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है.
बरखा: हां हां हां.
राडिया: ठीक है, हम जो भी बात होगी, कनिमोझी को बता देंगे. फिर वह अपने पिता को बता सकती है कि मुझे कांग्रेस से यह संदेश मिला है.
बरखा: ठीक है कोई समस्या नहीं. मैं आज़ाद से बात कर लूंगी. रेसकोर्स रोड से बाहर निकलते ही मैं आज़ाद से बात कर लूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है.
राडिया: हां, फिर उसने कहा है कि जब पिता जी आएंगे तो उनसे बात करेगी.
बरखा: ठीक है.

22 मई, 2009 15:31:29

राडिया: वे उससे बात करेंगे?
बरखा: हां.
राडिया: कौन? गुलाम?
बरखा: गुलाम. हां.
राडिया: पता है कनिमोझी... बजे की फ्लाइट है चेन्नई वापस आने को, दयानिधि मारन शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहा है, जबकि सिर्फ़ राजा शपथ ग्रहण में शामिल होने को अधिकृत है. मारन ने करुणानिधि से जाकर कह दिया कि अहमद पटेल ने ख़ास तौर पर उसे शपथ ग्रहण में शामिल होने को कहा है.
बरखा: अहमद कहता है कि यह सब बकवास है.
राडिया: पर मैं कह रही हूं न, ऐसा है. करुणानिधि बहुत असमंजस में हैं.
बरखा: नहीं, पर कनिमोझी रुककर क्यूं नहीं शपथ ग्रहण में शामिल होती?
राडिया: वह नहीं शामिल होना चाहती, क्योंकि उसके पिता ने उसे वापस आने को कहा है. उसे अपने पिता का कहा मानना होगा. गुलाम को फोन करो.

22 मई, 2009 19:23:

बरखा: कांग्रेस में जिसे भी जानती हूं, सब शपथ ग्रहण में हैं, इसलिए मैं ऊपर के लोगों से बात नहीं कर पाई. मेरा काम अभी ख़त्म हुआ और अब मैं फोन करने जा रही हूं.
राडिया: कनि अभी चेन्नई पहुंची है, अभी मैंने बात की.
बरखा: दया कहां है? मारन कहां है?
राडिया: मारन शपथ ग्रहण में नहीं आया, क्योंकि उसे वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उसने करुणानिधि को जाकर यह कहा कि अहमद पटेल ने उससे शपथ ग्रहण में आने को कहा था. इस पर करुणानिधि ने नाराज़ होकर कहा कि तुम कांग्रेस में ही चले जाओ.
बरखा: (हंसती है) तो अब?
राडिया: राजा ही अब अकेला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को अधिकृत है, वह अब फ्लाइट पकड़ने जा रहा है.

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार प्रभु चावला के बीच हुई बातचीत

राडिया : कुछ खास बात नहीं, मैं तो तुम्हारे विचार जानना चाहती थी, क्योंकि तुम काफी समझदार आदमी हो.
प्रभु: हैं..हैं..हैं.. ऐसा तो कुछ नहीं, बस लोगों को जानता हूं, दोस्ती निभाता हूं और काम चलाता हूं.
राडिया: अभी तो मैं जानना चाहती हूं कि अंबानी बंधुओं के बीच झगड़े में सुप्रीमकोर्ट ने जो फ़ैसला दिया और देश के हित से ऊपर दो भाइयों का हित रखा, इस पर तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या सोचते हो?
प्रभु: जब ये दो भाई किसी चीज में शामिल हों तो देश तो अपने आप ही शामिल हो जाता है. समस्या यह है कि दोनों भाई आपस में बात नहीं करते और कोई ऐसा नहीं है, जो उनमें बात करा सके. मैंने भी कोशिश की थी, मगर कुछ हुआ नहीं. कभी अनिल पकड़ में नहीं आता तो कभी मुकेश लापता हो जाते. वैसे ग़लती मुकेश की ज़्यादा है.
राडिया: मेरी आज ही सुबह मुकेश से बात हुई थी और वह कह रहा था कि अनिल को लगता है कि मीडिया ख़रीद कर और दैनिक भास्कर या जागरण या बिजनेस स्टैंडर्ड में लेख छपवा कर कंपनी चला लेगा तो मुझे अफसोस होता है.
प्रभु: असल में मुकेश अपनी बीवी के कहने पर चलता है. अनिल से मेरी अच्छी दोस्ती है और उसकी बीवी कहीं टांग नहीं अड़ाती. अनिल तो राजनीति, मीडिया, नेता सबका इस्तेमाल कर लेता है मुकेश कहीं बाहर गए थे, वापस आ गए क्या?
राडिया: वह तो एक हफ्ते से भारत में ही हैं और दिल्ली में ही हैं. कभी-कभी शाम को बॉम्बे चले जाते हैं. तुम्हारी बात नहीं हो पा रही?
प्रभु: मैं दो-तीन बार बॉम्बे गया. मुकेश ने मुझे खाने पर बुलाया था, मगर अचानक ग़ायब हो गया. कल भी बॉम्बे जा रहा हूं. कोशिश करूंगा. मैं तो दोनों का भला चाहता हूं. मुकेश की दिक्कत यह है कि धीरू भाई ने जो चमचे पाले थे, वे अब किसी काम के नहीं रहे. जमाना बदल गया है, मगर मुकेश ने अपने लोग नहीं बदले.
राडिया: मुकेश को तो तुम्हारे जैसे लोग चाहिए.
प्रभु: मैं तो सेवा करने को हमेशा तैयार हूं, मगर मुकेश पूरा विश्वास किसी पर नहीं करता. मैंने दो-तीन एसएमएस डाले, उनका भी जवाब नहीं आया. मैंने तो उसे यह बताना चाहा था कि सुप्रीमकोर्ट का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ रहा है, मगर वह तो इतना घमंडी है कि मैं क्या कहूं. अब भुगतेगा. इस देश में सब कुछ फिक्स होता है और सुप्रीमकोर्ट का जजमेंट फिक्स करना कोई कठिन काम नहीं है. अनिल घूमता ज़्यादा है, पैसे ख़र्च कम करता है. मुकेश तो धीरू भाई के जमाने से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता. तुम समझ रही हो न, मैं क्या कह रहा हूं? बेचारे मुकेश को तो सही जानकारी तक नहीं मिल पाती. मुझे पता है कि मुकेश सुप्रीमकोर्ट के लिए क्या कर रहा था और जो कर रहा था, वह ग़लत कर रहा था. सबको पता था. आजकल तो सब फिक्स होता है. अब सुप्रीमकोर्ट के फ़ैसले ने इसे ख़त्म कर दिया न.
राडिया: अभी तो सुप्रीमकोर्ट का फाइनलाइज़ नहीं हुआ है.
प्रभु: अब तो और बड़ी गड़बड़ होने वाली है. प्राइम मिनिस्टर मुरली देवड़ा के पीछे पड़े हैं. दुनिया में गैस के दाम बढ़ने वाले हैं. अगर भारत सरकार अपनी ही गैस नहीं ख़रीद सकती तो उसे अदालत जाना ही पड़ेगा. देश का हित पहले है, देश का नुक़सान नहीं होना चाहिए.
राडिया: यही तो मुकेश ने अनिल से कहा कि तेरा जितना बनता है, तू ले ले, एनटीपीसी अगर नहीं लेता तो वो भी तू ले ले, मगर फ़ैसला तो सरकार को करना है. 328 पेज का एमओयू है और उसमें सब कुछ साफ लिखा है. मुझे तो लगता है कि इसी एमओयू को पेनड्राइव में डालकर सुप्रीमकोर्ट के कंप्यूटर में लगा दिया गया होगा, क्योंकि दोनों की भाषा भी एक जैसी है. एटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने भी खेल किया है.
प्रभु: जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था तो वाहनवती हमारा वकील होता था. नुस्ली वाडिया उसे लेकर आया था. मेरा अच्छा दोस्त है, मगर आज की तारीख़ में अनिल अंबानी का आदमी है. यह बात मुकेश को बता देना और कह देना कि मैंने बताई है. हंसराज भारद्वाज ने तो उसे कभी पसंद नहीं किया. जब अनिल का पावर प्लांट ही शुरू नहीं हुआ तो उसे गैस का क्या करना है? मगर मुकेश भी क्या करेगा? मुकेश भी किसी और को गैस नहीं बेच सकता. आनंद जैन था, उसे हटा दिया गया. मनोज मोदी प्रोफेशनल है.
राडिया: प्रभु, आनंद जैन आज भी वहीं हैं, मगर आज भी इस मामले में मनोज मोदी ज़्यादा काम कर रहा है.
प्रभु: अनिल ने फिर से सुप्रीमकोर्ट में रिट डाली है और उसे यह करना भी चाहिए. मगर मुकेश से कहना कि जो हो रहा है, वह ग़लत हो रहा है. जो तरीक़े वह अपना रहा है, वे ग़लत हैं. जिन पर भरोसा कर रहा है, वे गड़बड़ हैं. लंदन में बैठकर. वैसे दिल्ली में राजनैतिक सिस्टम भी बदल गया है. कमल नाथ फ़ैसला करता है तो प्रणब मुखर्जी और जयराम रमेश या मोंटेक उसे टाल देते हैं. अनिल अंबानी डीएमके के ज़रिए चीफ जस्टिस को पटा रहे हैं. मुझे पता है कि मुकेश को किसको पटाना चाहिए, मगर वह मुझसे बात तो करे.
राडिया: यह लंदन वाला चक्कर क्या है, तुम्हें यह कहां से पता लगता है?
प्रभु: लीगल सोर्सेज से. अनिल ने तो मेरे बेटे अंकुर चावला को यानी उसकी कंपनी को रिटेनर रखा है, मगर इस मामले में मेरा बेटा नहीं है. अब दोनों भाइयों से मेरी दोस्ती होने का नुक़सान मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है. छोटा भाई बड़ा हरामी है...
राडिया: हरामी तो है, लेकिन हर रोज हरामीपना लास्ट नहीं करता न...

नीरा राडिया और प्रसिद्ध पत्रकार वीर सांघवी के बीच हुई बातचीत

वीर सांघवी: हाय नीरा
राडिया: हाय वीर, तुम कहां हो? दिल्ली में या कहीं और?
वीर: जयपुर में हूं, शाम को आ रहा हूं.
राडिया: ओ के. मैं कुछ कहना चाह रही थी. असल में मैं तमिलनाडु वाले दोस्तों से बात कर रही थी. वह ज़रूरी भी था. मुझे नहीं मालूम कि तुम कांग्रेस में किसी से बात करने की हालत में हो या नहीं, लेकिन मैंने अभी कनिमोझी से बात की. मैं उससे मिली थी.
वीर: अच्छा?
राडिया: आज शाम को या रात को हम लोग बैठेंगे तब मैं बताऊंगी. असल में समस्याएं बहुत हैं.
वीर: मुझे आज सोनिया से मिलना था. मैं यहां जयपुर में अटक गया हूं. अब कल ही मुलाक़ात होगी. मैं जब चाहता हूं, मिल लेता हूं. वैसे भी राहुल से तो चाहे जब मुलाक़ात होती रहती है. तुम मुझे बताओ, क्या करना है?
राडिया: मैं क्या बताऊं? कांग्रेस वाले समझ ही नहीं रहे हैं. वे ग़लत आदमी यानी दयानिधि मारन से बात कर रहे हैं. मारन ग़लत आदमी है. करुणानिधि ने भी उसे बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया है, मगर तुम जानते हो कि यहां तो जंगलराज है और आंधी चल रही है.
वीर: जब मारन को सब लोग नफरत करते हैं तो वह बीच में कहां से आ गया?
राडिया: वह कुछ है ही नहीं, यह मुझे पता है, तुम्हें पता है, मगर कांग्रेस वालों की समझ में नहीं आती. प्रधानमंत्री भी मारन से बात कर रहे हैं और डीएमके को कमाई वाले मंत्रालय देने का वायदा कर रहे हैं, मगर मारन ख़ुद अपने लिए टेलीकॉम चाहता है. आफत यह है कि कनि का भाई अलागिरि भी चुनाव जीता है और भारी नेता है.
वीर: मैं जानता हूं. वह स्टालिन से ज़्यादा अक्ल रखता है.
राडिया: अब मारन कांग्रेस से कह चुका है कि अलागिरि को राज्यमंत्री बना दो, स्वतंत्र प्रभार दे दो और बाक़ी मुझ पर छोड़ दो.
वीर: इतनी हिम्मत आ गई दयानिधि में?
राडिया: दयानिधि तो टी आर बालू और राजा को भी गाली देता है. करुणानिधि की बेटी को सिर्फ़ राज्यमंत्री बनवाना चाहता है, जबकि अलागिरि आधे से ज़्यादा तमिलनाडु को काबू में रखता है और करुणानिधि यह बात जानते हैं. वह मारन से पद और कद, दोनों में बड़ा है. उसने तो पिता से कह दिया है कि अगर आप मारन को मंत्री बनाएंगे तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा.
वीर: अच्छा, यह तो बड़ा मजेदार है. क्या कांग्रेस इसे समझ रही है?
राडिया: वही तो समझाना है. कांग्रेस वालों को कनि के ज़रिए सीधे करुणानिधि से बात करनी चाहिए.
वीर: सोनिया ने करुणानिधि से कल बात की थी.
राडिया: नहीं, तुम्हारी जानकारी ग़लत है. मनमोहन ने बात की थी और कनि वहां बैठी हुई थी, इसलिए सारी बात को अनुवाद करके सुना रही थी. यह मामला अपने को सुलझाना पड़ेगा. गुलाम नबी आज़ाद को कनिमोझी से बात करने के लिए कहो.
वीर: ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूं.
राडिया: मैं मज़ाक नहीं कर रही. सिर्फ़ यही एक तरीक़ा है और कनि ही कांग्रेस वालों को करुणानिधि के पास ले जा सकती है.
वीर: मैं अभी सोनिया को इसमें नहीं डालूंगा. उसकी समझ में ज़्यादा आता नहीं है. मैं पहले अहमद पटेल से बात करके देखता हूं. पटेल समझदार भी है और सोनिया उसकी सुनती भी है.
राडिया: कनि को पहले पकड़ना पड़ेगा. करुणानिधि को तीन मंत्रिमंडल सीटों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कबाड़ा किया हुआ है. पता नहीं क्यों, कांग्रेस मारन को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है. अगर मारन को बाहर रखा जाता तो राजा और बालू तक बात आकर टिक जाती और हो सकता है कि राजा, अलागिरि और कनि तीनों राज्यमंत्री पर राजी हो जाते, मगर मारन वाला चक्कर तो कांग्रेस ने डाला.
वीर: और मैं सोच रहा था कि डीएमके ने वाकई मारन को नियुक्त किया है.
राडिया: नहीं नहीं नहीं नहीं और नहीं...डीएमके ने अपनी लिस्ट में पांच मंत्रालय और नाम भेजे थे और मारन का नाम भी उसमें था. उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस राजा के बारे में उनसे बात करेगी. आख़िरकार बात तीन मंत्रालयों पर आकर टिक जाती, मगर बात ही ग़लत आदमी से हो रही है.
वीर: मैं समझ गया. मैं अहमद से बात करूंगा.
राडिया: कनि से बात करना ज़्यादा आसान होता. कनि बेटी है और उसके सामने कोई भी बात की जा सकती है. कांग्रेस को कहना पड़ेगा कि उन्हें मारन नहीं चाहिए. यह इंतज़ाम हर क़ीमत पर तुम्हें करना पड़ेगा.
वीर: ठीक है, अभी से लगता हूं इसमें. अहमद से, राहुल से या सीधे सोनिया से कुछ न कुछ तो रास्ता निकालूंगा. वैसे कनि अभी कहां है?
राडिया: साउथ एवेन्यू वाले अपने घर पर.
वीर: कोई मोबाइल भी तो होगा?
राडिया: मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूं. वहां कुछ तमिलनाडु कांग्रेस के लोग भी थे, जो बाहर बैठे हुए थे. वीर, तुम तो गुलाम को पकड़ो, वही काम का आदमी है.
वीर: नीरा, तुम अभी बात कर सकती हो?
राडिया: बोलो न, तुम्हारे लिए जान हाज़िर है.
वीर: मारन सोनिया से नहीं मिला.
राडिया: मुझे पता है, मगर यह बात सबको पता नहीं लग रही.
वीर: मैंने इंतज़ाम कर लिया है कि मारन सोनिया से कभी नहीं मिल पाए. वह गया था, मगर उसे साफ कह दिया गया कि तुम्हें हम डीएमके का प्रवक्ता नहीं मानते. मेरे पास भी उसका फोन आया था और गुलाम का भी फोन आया था. गुलाम परेशान था कि मारन हर आधे घंटे में उसे फोन कर रहा है. जहां तक अपन लोगों का सवाल है तो दो बीवियां हैं, एक भाई है, एक बहन है, एक भतीजा है और इससे चीजें और ज़्यादा उलझ रही हैं. हमने अपना ऑफर दे दिया. अब करुणानिधि को जवाब देना है कि वह सोनिया गांधी से सीधे बात करना चाहते हैं या नहीं. अभी तक उनकी बात मनमोहन सिंह से हुई है, सोनिया की चाबी तो मेरे पास है. मैं बात करा सकता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं पड़ूंगा. अब मारन को भी मैंने कह दिया है कि आपको हमारे प्रस्ताव का जवाब देना है.
राडिया: तुम्हारी गुलाम नबी से बात हुई?
वीर: मैंने अहमद से बात की. फ़ैसला गुलाम नबी को नहीं, अहमद पटेल को करना है. अहमद ने मुझे बताया कि गुलाम मारन से बात कर रहा है, लेकिन गुलाम भी हमारा प्रवक्ता नहीं है. मारन को भी अहमद ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है. ये डीएमके वाले लोग पागल हो गए हैं. पांच बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं. अब करुणानिधि हमसे बात करें. कनि हमसे आकर मिले, अपने पिता से जो भी बात करे या हमारी बात कराए, मगर मैं मारन से बात नहीं करूंगा और उसको मैंने कह दिया है कि गुलाम को भी परेशान मत करो. मारन चेन्नई चला गया है और वहां से फोन करेगा. चेन्नई भी इसलिए गया है क्योंकि मैंने उससे कहा है कि अब हम करुणानिधि से सीधे बात करेंगे. हम बुड्ढे की इज़्ज़त करते हैं, मारन तो फालतू आदमी है.
राडिया: यह बात मैं सबको बताती हूं.
वीर: मैंने एम के नारायणन से भी कह दिया है कि वह प्रधानमंत्री को ठीक से समझा दें. सोनिया से बात मैं कर लूंगा.

(साभार: भड़ास फॉर मीडिया)

feedback@chauthiduniya.com

शारीरिक या मानसिक अक्षमता कई तरह की होती है. इसमें मानसिक विकलांगता, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, चलने में असमर्थता आदि कई श्रेणियां हैं.

उपेक्षित हैं शारीरिक-मानसिक अक्षमता के शिकार लोग

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

आदित्य पूजन

उन्हें सामान्य इंसान नहीं माना जाता, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं. उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है. आम इंसानों को जो सुविधाएं हासिल हैं, वे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते. कहने को तो शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए तमाम तरह के क़ानून बने हैं, कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के पास उनकी वास्तविक संख्या के बारे में सही आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हैं. जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे सही तस्वीर पेश नहीं करते, क्योंकि अलग-अलग तरह की शारीरिक अक्षमताओं की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है. उनकी बदनसीबी यह है कि भगवान ने उन्हें आम इंसानों से अलग बनाया, लेकिन सामाजिक और सरकारी स्तर पर सहयोग से उन्हें सामान्य रूप से जीने के योग्य ज़रूर बनाया जा सकता है. लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके अभाव में शारीरिक अक्षमताओं का शिकार समाज का यह तबका समाज ही नहीं, बल्कि परिवार में भी अलग-थलग पड़ा हुआ है.

2001 की जनगणना के मुताबिक़, पूरे देश में शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों की कुल संख्या तक़रीबन 1.85 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का क़रीब 1.85 प्रतिशत है. वहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक़, साल 2002 में देश में ऐसे लोगों की अनुमानित संख्या 2.19 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.13 प्रतिशत है. इन आंकड़ों की सच्चाई भी संदेहास्पद है, क्योंकि यूरोपीय देशों में शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों की अनुमानित संख्या कुल जनसंख्या का 7 से 10 प्रतिशत के बीच है. एक ग़ैर सरकारी संस्था के अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की संख्या 6 करोड़ से भी ज़्यादा है. इनमें तक़रीबन 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाक़ों में रहते हैं, जबकि शारीरिक एवं मानसिक कमज़ोरियों के शिकार 49 प्रतिशत से ज़्यादा लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. आंकड़ों से दूर हटकर देखें तो भारतीय समाज में शारीरिक या मानसिक विकलांगता के शिकार लोगों को बोझ की तरह देखा जाता है. एकल परिवार के इस दौर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता. कई बार ऐसा देखा गया है कि माता-पिता भी उनकी परवरिश से मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं. उन्हें आरोग्य केंद्रों या अनाथालयों में भर्ती कराकर अभिभावक अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं. इन केंद्रों में कुव्यवस्था का आलम क्या होता है, यह सभी को मालूम है. इसका नतीजा यह होता है कि शारीरिक अक्षमता के शिकार लोग समाज की मुख्यधारा से ही दूर हो जाते हैं.

शारीरिक या मानसिक अक्षमता कई तरह की होती है. इसमें मानसिक विकलांगता, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, चलने में असमर्थता आदि कई श्रेणियां हैं. भारत में इन श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके चलते ऐसे लोग उन क़ानूनों और योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते, जो उनके फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं. पर्सन्स विद डिसेब्लिटीज (ईक्वल अपॉर्च्युनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 में शारीरिक अक्षमता के शिकार लोगों के लिए समान अधिकार, अवसरों में समानता और उनकी भागीदारी की बात कही गई है. इसके अलावा इसमें समाज के इस वर्ग के सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है. लेकिन इस क़ानून के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें केवल सात तरह की अक्षमताओं की चर्चा है. इसके दायरे से बाहर के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता. इसके अलावा डिसेब्लिटीज एक्ट के प्रावधानों के तहत शारीरिक अक्षमता को चिकित्सकीय आधार पर परिभाषित किया गया है, इसके सामाजिक पहलुओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है. भारत में समस्या यह है कि अधिकांश अभिभावक शारीरिक या मानसिक कमज़ोरी को समय रहते समझ नहीं पाते और चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के अभाव में इस क़ानून का फ़ायदा नहीं उठा पाते. यही वजह है कि समाज के इस वर्ग को हर स्तर पर असमानता का शिकार होना पड़ता है. तमाम योग्यताओं के बावजूद उन्हें सामान्य शिक्षण संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती और ऐसे शिक्षण संस्थानों का देश में नितांत अभाव है, जहां उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था हो. उनके लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. निजी क्षेत्र की नौकरियां इस दायरे में नहीं आतीं, जबकि रोज़गार के ज़्यादा अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं. नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 भी अब तक इनकी हालत में ज़्यादा बदलाव लाने में कारगर साबित नहीं हुआ है.

दरअसल, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर तबके की हालत में सुधार के लिए क़ानूनी पहलुओं के साथ उनके प्रति सामाजिक नज़रिये में भी बदलाव की सख्त आवश्यकता है. उन्हें समाज का कोढ़ या भगवान के अभिशाप के रूप में देखे जाने की परंपरागत सोच बदलनी होगी. हमें यह समझना होगा कि वे भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं और उन्हें भी समाज में समानता के साथ जीने का हक है. इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था हो, उन्हें शिक्षा और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें. इस मामले में ग़ैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. ये संस्थाएं समाज में जागरूकता फैलाने के अलावा शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता के शिकार लोगों के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं. इसके अलावा विकसित देशों की तर्ज पर आरोग्य केंद्रों एवं केयर सेंटरों का पूरे देश में जाल बिछाए जाने की ज़रूरत है. ग़रीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता के शिकार लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाता. इसके साथ-साथ सरकार को इन लोगों के लिए यातायात की ऐसी सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका ये आसानी से इस्तेमाल कर सकें. अभी जो हालत है, उसमें देश में शारीरिक-मानसिक कमज़ोरियों के शिकार लोगों के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों का घोर अभाव है. सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा. इसके साथ-साथ क़ानून में भी बदलाव की ज़रूरत है, इसे ज़्यादा समग्र बनाया जाना चाहिए, जिससे हर श्रेणी के अक्षम लोग लाभांवित हो सकें. निजी क्षेत्रों एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं को भी समाज के इस वर्ग के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा, तभी किसी व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है. शारीरिक और मानसिक कमज़ोरियों के शिकार लोग अपने दम पर ज़िंदगी जीने में समर्थ नहीं होते, बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं. इनकी ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत मानसिक सहयोग की होती है. हम यदि इन्हें यह उपलब्ध कराने में कामयाब हुए तो समाज का यह उपेक्षित वर्ग भी समाज में बराबरी के स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है.

aditya@chauthiduniya.com

प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान एवं सीमैप की मौजूदगी के बावजूद औषधि पौधे लगातार विलुप्त हो रहे हैं.

विलुप्त हो गईं जड़ी-बूटियां

सुरेंद्र अग्निहोत्री

सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुका सोमवल्ली का पौधा एक बार फिर मध्य प्रदेश के रीवा के जंगलों में खोज निकाला गया है. यह पौधा प्राचीन ग्रंथों और वेद पुराणों में चिरायु बनाने के लिए वर्णित है. यद्यपि यह एक उपलब्धि है, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते अनेक दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां विलुप्त होने की कगार पर हैं. तस्कर-व्यापारी इन दुर्लभ पौधों-जड़ी बूटियों को ऊंची क़ीमतों पर हासिल करने में लगे हुए हैं. अभी हाल में तस्करों से बरामद बेशक़ीमती कीड़ा जड़ी में से 13 किलो जड़ी पिथौरागढ़ पुलिस ने ग़ायब कर दी. वजह कीड़ा जड़ी की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बहुत मांग है और इसकी मुंहमांगी क़ीमत मिलती है.

प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान एवं सीमैप की मौजूदगी के बावजूद औषधि पौधे लगातार विलुप्त हो रहे हैं. वनस्पतियों की तीन लाख अस्सी हज़ार प्रजातियों में से हर पांचवी प्रजाति विलुप्त हो रही है. वैज्ञानिकों के मुताबिक़, इसके लिए मानवीय गतिविधियां सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं. ब्रिटेन के क्यूके बोटेनिक गार्डन, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वैज्ञानिकों ने पाया कि अब तक पौधों की क़रीब 22 फ़ीसदी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं. पौधों को अपनी प्राकृतिक वृद्धि के लिए योग्य भूमि नहीं मिल पा रही है. अधिकांश ज़मीन का प्रयोग खेती के लिए होने के कारण 33 फ़ीसदी प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. उत्तर प्रदेश में 24 वन्यजीव एवं पक्षी विहार हैं, लेकिन बढ़ती आबादी और घटती हरियाली के चलते इस जैव संपदा को बचाना एक चुनौती है. अत्यधिक संग्रह के चलते भी कई जड़ी-बूटियां विलुप्त हो गईं पुराने किलों और जर्जर मकानों की दीवारों पर उगने वाली मोर सखी का नामोनिशान मिट गया. हड़जोड़, बालम खीरा, कोदो, कुटकी, फिकार, गुमची, पुआर, किरमिच, भटकटैया, आमीहल्दी, वनकरैला एवं घमरा आदि बड़ी संख्या में खेतों की बाड़ के आसपास पैदा होते थे. विदेशी खर-पतवारों के आक्रमण के कारण भी जैव विविधता को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है. तराई के खैर, शीशम, हल्दू सेमल, कंजू, गुटेल, असना, तेंदू, करघई एवं सलाई के वन प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं. इनके घटने के साथ ही औषधीय जड़ी-बूटियां भी नदारद हो गईं.

बीस करोड़ से अधिक आबादी वाले इस सूबे में हरियाली बढ़ने की रफ़्तार सुस्त है. हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं. उत्तराखंड गठन के बाद प्रदेश के 2,40,928 वर्ग किमी क्षेत्रफल में वन क्षेत्र मात्र 14,118 वर्ग किमी है और वर्ष 1980 से अब तक मात्र 7,715 वर्ग किमी में वृक्षारोपण हुआ. यानी कुल मिलाकर 9.06 भूभाग ही हरा-भरा है. वन नीति के हिसाब से राज्य का एक तिहाई भूभाग हरा-भरा होना चाहिए. सूबे का 79,506 वर्ग किमी क्षेत्र वनाच्छादित होने की ज़रूरत है. आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का औसत 0.01 हेक्टेयर है, जो देश में सबसे कम है. पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति 0.04 हेक्टेयर हरियाली है. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए न तो कोई नया वन स्थापित हुआ और न पहले की तरह सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष नज़र आते हैं. उल्टे अब तक 9,775 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास की भेंट चढ़ चुका है. वहीं 28,859 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 24,965 हेक्टेयर पर अवैध क़ब्ज़े हैं. जंगलों पर क़ब्ज़े के 4,300 मामले पिछले 15-20 वर्षों से न्यायालय में लंबित पड़े हैं.

इटावा, कानपुर, आगरा, झांसी, उरई और मथुरा के जंगलों में बेहिसाब होने वाली मिसवाक (जो दांतों को मज़बूती देती है) अब नहीं दिखती. जंगलों-पोखरों के किनारे उगने वाली शंखपुष्पी और वन प्याज भी नहीं मिलती हैं. हंसराज, कामराज, हरजोड़, वच, आंबा, चित्रक एवं कलिहारी सरीखे औषधीय गुणों वाले पौधे ग़ायब हो चुके हैं. 1859 के आसपास लखनऊ में औषधीय पौधों की एक हज़ार प्रजातियां पाई जाती थीं, जो अब घटकर 400 रह गई हैं. वच की जड़ का इस्तेमाल गुर्दा रोग में होता है, जबकि हंसराज सांप का विष उतारने में काम आता है. कामराज का प्रयोग मुंह के छाले और डायरिया की रोकथाम के लिए होता है. चित्रक का सेवन टीबी के मरीजों को कराया जाता है. गोमती के किनारे मिलने वाली कलिहारी भी ख़त्म हो गई है, यह ज्वर के इलाज में काम आती थी. उत्तर प्रदेश में औषधीय गुणों वाले पौधों की संख्या पांच सौ से ऊपर है, जो विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाते हैं. गोरखपुर के कैपियर गंज इलाक़े में पाया जाने वाला दुधई, दूधिया या दुद्धी वह पौधा है, जो कमर दर्द या कमर में चिलक समा जाने के समय इस्तेमाल होता है. इसी इलाक़े में पाई जाने वाली चकवाड़ भी शायद अब न दिखाई दे, जिसका प्रयोग फोड़े-फुंसियों के इलाज में किया जाता है. खांसी, दमा और प्रसूति संबंधी रोगों में इस्तेमाल किया जाने वाला अडूसा, जिसे रूसा और बासा के नाम से भी जाना जाता है, के साथ-साथ बुखार, हैजा, दांत और पेट दर्द में लाभदायक तिमुरू भी ख़त्म होने की कगार पर है. गेहूं के खेतों में स्वत: उगने वाला बथुआ भी दुर्लभ हो गया है. उदर रोग और ज्वर में इस्तेमाल होने वाली सर्पगंधा, जिसे धवल वरुआ और चंद्रमखा के नाम से भी जाना जाता है, भी दिखनी बंद हो गई है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले और फोड़े-फुंसियों के इलाज में कारगर पत्थरचटा एवं बड़ी चड़ीद भी विलुप्त प्राय: हैं. पायरिया और मूत्र विकार में दवा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली चिरचिराह और चकवा भी ग़ायब है. ममीरी और चवत्री घास भी जल्दी ही दिखना बंद हो सकती है. रक्त शोधक औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाली वाही या गेठा समाप्त हो रही है. दांत एवं मूत्र संबंधी विकारों से छुटकारा दिलाने वाली कटकारी या भटकटैय्या, मदार, आक मदार एवं अकवा के पौधे खोजने के लिए काफी समय गंवाना पड़ सकता है.

कानपुर में पाया जाने वाला पुनर्नवा, जो आंत की बीमारी और मुंह के छाले में लाभदायक होता है, भी दुर्लभ है. स्वप्नदोष की बीमारी में लाभदायक धतूरा और आंख की बीमारी में उपयोगी सत्यानाशी का दूध भी खोजे नहीं मिल रहा. इसका उपयोग दाद-खाज की दवा के रूप में भी किया जाता है. धान के खेतों में स्वत: उगने वाली

इटावा, कानपुर, आगरा, झांसी, उरई और मथुरा के जंगलों में बेहिसाब होने वाली मिसवाक (जो दांतों को मज़बूती देती है) अब नहीं दिखती. जंगलों-पोखरों के किनारे उगने वाली शंखपुष्पी और वन प्याज़ भी नहीं मिलती हैं.

गोरखमुंडी ही नहीं, पीलिया की अचूक दवा अमरबेल या आकाशबेल को भी हम सहेज कर नहीं रख पाए. हर जगह मिलने वाली मकोई रसभरी अब खोजे नहीं मिलती. चोपन के जंगलों में पाई जाने वाली वनकवाच या काली कांच की जड़ भी अब हमारे लिए बीते दिनों की बात होती जा रही है. वनकवाच की जड़ पीस कर पीने से स्वप्नदोष और नपुंसकता की बीमारी दूर होती है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाईं एवं मेड़ों पर उगने वाली और कमर दर्द, गठिया एवं बाई में लाभदायक सिंदवार अब नदारद है. शिवालिक वन प्रभाग में पाया जाने वाला अमलताश, हरसिंगार एवं जंगली प्याज अब संरक्षित पौधों की श्रेणी में शुमार है. हरसिंगार का उपयोग पथरी रोग में होता है, जबकि जंगली प्याज नजला, खांसी और उल्टी की दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है. प्रदेश भर में पाई जाने वाली वनतुलसी या तुतरलंग बलतोड़ में लाभकारी है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले कठजामुन की गुठलियों से मधुमेह की दवा बनती है. गिलाय से अम्ल पित्त, रक्त पित्त, एलर्जी एवं ज्वर से निपटा जा सकता है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले हरहर का प्रयोग कान के दर्द और हड्डी की मज़बूती के लिए किया जाता है. गोबर के ढेर पर या दीवारों के किनारे उग आने वाले कुकरोध से घाव ठीक होते हैं, जबकि जंगली इलाक़ों में उगने वाली कंज मलेरिया में लाभदायक है. भगरइया का प्रयोग दांत दर्द और बवासीर में किया जाता है. दांत दर्द में सिहोर भी बेजोड़ माना जाता है. अपर निदेशक वन संरक्षण मोहम्मद एहसान बताते हैं, यह सभी पेड़-पौधे स्वतंत्र रूप से उग आते हैं. उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर पाई जाने वाली जीवनरक्षक जड़ी-बूटियों की कई प्रजातियां ख़त्म होने की कगार पर हैं. यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो इन जड़ी-बूटियों को हम किताबों में ही देख पाएंगे. वनस्पति विज्ञानियों की मानें तो उत्तर प्रदेश में सफेद मूसली, शतावर, पापड़, अगड़ी, बड़ी हंसिया एवं हरसिंगार जैसी महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियां बड़ी संख्या में पाई जाती थीं. वन तुलसी, इंद्रजौ, रोहणी एवं धामिन आदि से पहाड़ समृद्ध थे, लेकिन अब ये धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं. उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लगभग पांच हज़ार प्रजातियों, जिनमें चमेली और गूलर आदि भी शामिल हैं, को इंडेजर्ड प्लांट की श्रेणी में डाल दिया गया है. इनमें मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला डायोस्पाइरास होलियाना एवं जैसमिनम प्रिविपटियोटेस्टिम (चमेली की एक प्रजाति), फाइकस कपुलेटा (गूलर की एक प्रजाति) और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली इंडो पिप्टाडेनिया शामिल हैं. इसमें डायोस्पाइरास होलियाना को अंतिम बार 1922 में देखा गया था, जबकि जैसमिनम प्रिविपटियोटेस्टिम 1859 के बाद देखा ही नहीं गया.

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार, ऐसे पौधों की सूची बनाई जा रही है, जिनका अस्तित्व संकट में है, ताकि उन्हें ख़त्म होने से रोका जा सके. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो. जी के पांडेय का कहना है कि भारत में लगभग 45 हज़ार पौधों और 89 हज़ार जंतुओं की प्रजातियां मौजूद हैं. पेड़-पौधों की प्रजाति विकसित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं. डॉ. आशीष कहते हैं कि प्रदेश की पहाड़ियों पर औषधीय पौधों का भंडार है. जो जड़ी-बूटियों के जानकार हैं, वे अधिक से अधिक पैसों की चाह में उनका मनमाना दोहन कर रहे हैं. कलिहारी की जड़ पहले जंगलों में ख़ूब पाई जाती थी, जिसका गठिया के इलाज में प्रयोग होता है. फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र के मांझिल गांव में मिलने वाली दुर्लभ बूटी रुद्रवंती पर संकट के बादल छाए हुए हैं. यह बूटी सिर्फ़ हिमालय क्षेत्र में ही मिलती है और पूरे देश में दूसरा स्थान मांझिल का है.

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के निदेशक डॉ. राकेश तुली का कहना है कि हर वर्ष देश की 15 से 30 प्रतिशत पादप प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं. देश में पौधों की 50,000 प्रजातियां हैं. तेजी से कम हो रही जैव विविधता केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है. संस्थान के प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार सिंह के अनुसार, पूरे उत्तरी भारत के औषधीय एवं सगंध पौधों के गुण सूत्रों या डीएनए को सीमैप में एक जीन बैंक में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है. अगर प्राकृतिक रूप से ये सभी नष्ट हो जाएं तो भी जीन बैंक में रखे इनके डीएनए से इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है. यहां अब तक देश के 2000 औषधीय एवं सगंध पौधों के डीएनए हैं. वहीं दूसरी ओर अपनी स्थापना के चार वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड अभी काग़ज़ों में ही सिमटा है. जैव विविधता के संरक्षण के लिए पार्क बनाए जाने की योजना भी अभी साकार नहीं हो सकी है. गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा एवं बेतवा के कछार में बालू और सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में ग्रेनाइट-सेंड स्टोन खनन में मानकों की अनदेखी से विभिन्न जड़ी-बूटियों का अस्तित्व संकट में है.

feedback@chauthiduniya.com

लंबित मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है. अधीनस्थ अदालतों में 2 करोड़ 17 लाख और विभिन्न हाईकोर्ट में 40 लाख 17 हज़ार से ज़्यादा मुक़दमे लंबित हैं.

सत्ता के बावजूद शक्तिहीन

मेघनाद देसाई

आधुनिक भारत के निर्माण का आधार अंग्रेजों के उस कुतर्क में ढूंढा जा सकता है, जिसमें उन्होंने भारत को एक राष्ट्र मानने से इंकार कर दिया था. अंग्रेजों का दावा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि अलग-अलग प्रांतों, धर्मों, भाषाओं एवं जातियों का एक समूह है. पहले गोलमेज सम्मेलन में यह फ़ैसला ले लिया गया कि भारत एक कमज़ोर केंद्र और ताक़तवर प्रांतों वाला राष्ट्र होगा. मौजूदा दौर में देश की राजनीति में जो नाटकीयता हम देख रहे हैं, वह उन्हीं पुराने दिनों की याद दिलाती है. जब स्वतंत्र भारत के नए संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें केंद्र को ताक़तवर बना दिया गया और प्रांत उसके अधीन हो गए. सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित थीं, जहां कांग्रेस के बहुमत का शासन था. सत्ता की लगाम प्रधानमंत्री के हाथों में थी, जो सर्वशक्तिमान था.

इसकी तुलना मौजूदा दौर की राजनीतिक व्यवस्था से करें तो आज केंद्र में द्विस्तरीय सरकार है. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथों में है. यह कैबिनेट की तरह काम करता है, जिसमें गठबंधन के साझीदार दलों के बीच सारे फ़ैसले लिए जाते हैं. वास्तविक कैबिनेट की हैसियत इससे नीचे है, क्योंकि इसमें शामिल गठबंधन के साझीदार दलों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से आदेश नहीं लेते हैं, बल्कि अपने दल के नेता की बात मानते हैं. इतना ही नहीं, अपने प्रभाव क्षेत्र में मज़बूत आधार वाली पार्टियां किसी की नहीं सुनतीं, वे ख़ुद अपनी मालिक हैं. उदाहरण के लिए तमिलनाडु को लें तो वह एक स्वायत्त प्रांत की तरह व्यवहार करता है. ए राजा को कैबिनेट से हटाए जाने के मामले में गठबंधन की नेता सोनिया गांधी को डीएमके प्रमुख करुणानिधि से ऐसे बात करनी पड़ी, मानो यह कोई अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो. प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी होकर रह गई है कि वह न यहां के हैं और न वहां के. वह सरकार चलाते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं.

वर्ष 1989 तक केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य बना रहा, लेकिन इसके बाद कमज़ोर गठबंधन सरकारों के चलते केंद्र की शक्तियों में लगातार कमी आती गई. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनकी हालत इतनी कमज़ोर थी कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री की आलोचना भी नहीं कर सकते थे. समस्या यह है कि देश के संविधान में मज़बूत केंद्र को आधार बनाया गया है. इसकी वजह यह है कि संविधान निर्माता प्रांतीय आधार पर देश के विभाजन की आशंका से सहमे हुए थे. अब जो हालत है, उसमें देश के टूटने का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसे उस अंदाज़ में चलाया भी नहीं जा सकता, जिस तरह नेहरू या इंदिरा गांधी चलाते थे. इसकी सारी संभावनाएं तभी ख़त्म हो गईं, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी. हालांकि इसके बाद 1980 से 1989 तक कांग्रेस फिर से सत्ता में रही, लेकिन स्थितियां हमेशा के लिए बदल चुकी थीं. आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई, जिसमें केंद्र की सरकार लगातार कमज़ोर पड़ती गई, लेकिन भारत ने इस नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ जीना नहीं सीखा है. कमज़ोर केंद्र वाली संघीय व्यवस्था तभी बिना किसी समस्या के चल सकती है, जब प्रांतों और केंद्र के बीच लगातार बातचीत होती रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में अब तक इसके लिए कोई उपाय ईजाद नहीं किया गया है.

यह सोनिया गांधी की राजनीतिक बाजीगरी का ही कमाल था कि वह सत्ता के शीर्ष का बंटवारा करने में कामयाब रहीं. गठबंधन की नेता के रूप में उसे बनाए रखने और साझीदार दलों एवं राज्यों के साथ बातचीत का काम उन्होंने अपने पास रखा, जबकि सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कंधों पर है. पिछले छह सालों से यह व्यवस्था बख़ूबी चलती रही, लेकिन अब इसमें समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि नैतिकता में विश्वास न करने वाली ताक़तवर सहयोगी पार्टियों पर नैतिक आचरण थोपा नहीं जा सकता. यही वजह है कि राजा के इस्तीफ़े के लिए सरकार को इतने पापड़ बेलने पड़े और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कैबिनेट में अपने हिस्से का मंत्रालय दोबारा पाने के बाद डीएमके इसकी क़ीमत ज़रूर वसूल करेगा. फिर यह भी सत्य है कि केंद्र की ताक़त में कमी भले आई हो, लेकिन विधायिका के मुक़ाबले कार्यपालिका अभी भी काफी मज़बूत है. विपक्ष चाहकर भी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरकार हमेशा ही अपनी मर्जी के बिलों को संसद की मंजूरी दिलाने में कामयाब रहती है. विपक्ष के पास एक ही हथियार बचा है कि वह हंगामा कर संसद की कार्यवाही में रुकावट पैदा करे और तभी ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं.

लेकिन यह भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि आपातकाल से पहले तक संसद में होने वाली बहसों को सरकार काफी अहमियत देती थी, लेकिन अब संसद के सत्र छोटे होते हैं और सरकार उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से आयोजित करती है. विपक्ष सरकार की इस चालाकी को अच्छी तरह समझता है, लेकिन गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. कार्यपालिका पर नकेल कसने का काम न्यायपालिका भी कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय के पास कार्यपालिका को घुड़की देने का नैतिक अधिकार है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं. गोदामों में सड़ते अनाज वाले मामले में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ख़िलाफ़ कड़ाई से पेश आ सकता है, लेकिन संबंधित मंत्रालय यदि ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो, जो गठबंधन में शामिल किसी ताक़तवर पार्टी का नेता हो तो प्रधानमंत्री भी कुछ खास नहीं कर सकते. शरद पवार किसी से आदेश नहीं लेते, किसी की बात नहीं सुनते. प्रधानमंत्री चाहकर भी सर्वोच्च न्यायालय को अपने सहयोगियों से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा देश प्रधानमंत्री को उतनी ही इज़्ज़त देता रहेगा, जितनी उन्हें अब तक मिलती रही है?

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली हाईकोर्ट की अनोखी पहल

ज़ाहिद खान

हमारे देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुक़दमों के शीघ्र निपटारे को लेकर न्यायविदों की तरफ़ से समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है. यहां तक कि पिछले दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में ख़ुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मुक़दमों के निस्तारण में लगने वाले लंबे समय पर चिंता जताई थी. एक तरफ़ अदालतों में मुक़दमों की सुनवाई धीमी रफ़्तार से आगे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ़ नए मुक़दमों का अंबार लगता चला जा रहा है, जिसके चलते अदालतों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या से निबटने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है. कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समस्या के विकराल रूप को देखते हुए वे काफी कम हैं. लंबित मुक़दमों को तेजी से निपटाने की दिशा में ऐसी ही एक अच्छी कोशिश अभी हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने की.

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने एक अनोखी पहल करके महज़ एक दिन में एक लाख से ज़्यादा मुक़दमों का निपटारा कर दिखाया. हाईकोर्ट की ओर से पहली बार आयोजित इस मेगा लोक अदालत में 250 से ज़्यादा न्यायाधीशों ने सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे औसतन 10 हज़ार मुक़दमों में, जिनमें भी त्वरित फ़ैसले के लिए सबूत मौजूद थे, तुरंत फ़ैसला दिया. हालांकि इनमें 80 हज़ार मुक़दमे यातायात से संबंधित अपराधों और बाक़ी वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, अन्य सिविल एवं मामूली शिक़ायतों के थे, लेकिन फिर भी यह उपलब्धि छोटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां छोटे से छोटे मामले भी अदालतों में बेवजह खिंचते रहते हैं.

दरअसल बड़ी तादाद में न्यायाधीशों के ख़ाली पड़े पद लंबित मामलों के निपटारे में देरी की अहम वजह हैं. अदालतों में न्यायाधीशों की यह कमी अर्से से महसूस की जा रही है. आलम यह है कि तक़रीबन 17 फ़ीसदी पद ख़ाली पड़े हैं. जानकारी के मुताबिक, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 16,946 स्वीकृत पदों में 2,783 पद रिक्त हैं. ज़ाहिर है कि इन रिक्त पदों के भरने से बहुत कुछ सुधार हो सकता है. न्यायिक प्रणाली का विस्तार होगा तो मुक़दमे भी जल्दी निपटेंगे. अदालतों में मुक़दमों के अंबार को देखते हुए 12 साल पहले आई विधि आयोग की 124वीं रिपोर्ट में खास तौर पर यह सिफ़ारिश की गई थी कि न्यायाधीश और आबादी के अनुपात में न्यायिक प्रणाली में पांच गुना विस्तार किया जाए, लेकिन सरकार ने इस सिफ़ारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की. सस्ता और त्वरित न्याय हमारी सरकारों की प्राथमिकता में कभी नहीं रहा. सरकारें न्यायिक व्यवस्था के प्रति कितनी गंभीर हैं, इस बात का अंदाज़ा

न्यायिक ढांचे पर उसके ख़र्च से होता है. दुनिया में भारत की गिनती उन देशों में होती है, जो अपने न्यायिक ढांचे पर बहुत कम ख़र्च करते हैं.

हमारे यहां देश की आबादी के अनुपात में यदि न्यायाधीशों की संख्या को देखें तो यह बेहद निराशाजनक है. हमारे यहां तक़रीबन नौ लाख लोगों पर महज़ एक न्यायाधीश नियुक्त है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में 10 हज़ार लोगों पर एक न्यायाधीश नियुक्त है. दोनों देशों के तुलनात्मक अध्ययन से यह सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसाफ के प्रति कौन कितना संजीदा है? हर तरह से सक्षम न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य तकाजा है. लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों कार्यपालिका एवं विधायिका से नाउम्मीदी के बाद ही जनता न्यायपालिका की ओर देखती है, वहीं उसे आख़िरी उम्मीद दिखती है. इंसाफ की गति बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर नियुक्तियों के अलावा न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़नी चाहिए. सुप्रीमकोर्ट ने अपनी ओर से न्याय प्रणाली में तेजी लाने की कोशिश की है. दो पाली में अदालतें लगाने का उसका फ़ैसला इसी दिशा में एक अहम कड़ी है, लेकिन फ़िलहाल यह व्यवस्था केवल दिल्ली और अहमदाबाद में ही लागू हो सकी है. लंबित मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है. अधीनस्थ अदालतों में 2 करोड़ 17 लाख और विभिन्न हाईकोर्ट में 40 लाख 17 हज़ार से ज़्यादा मुक़दमे लंबित हैं. यही नहीं, सुप्रीमकोर्ट में भी 52 हज़ार से ज़्यादा मामले इंसाफ की बाट जोह रहे हैं. ज़ाहिर है, स्थितियां ख़राब हैं और यदि अब भी इनका गंभीरता से मुक़ाबला नहीं किया गया तो न्यायिक व्यवस्था के चरमराने का ख़तरा है. ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों से हमारे देश का सर्वोच्च नेतृत्व अंजान हो. विधि आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सरकारों को इस बारे में लगातार आगाह करता रहा है. न्यायिक सुधारों के लिए अनेक सिफ़ारिशें भी की गईं, लेकिन चेतावनियां सुनकर भी अनसुनी की जाती रही और सुझाव ठंडे बस्ते में डाले जाते रहे. जब पानी सिर से ऊपर हो गया, तब जाकर नेतृत्व को इस बात का ख्याल आया. सरकार ने हालात से निपटने के लिए अब लंबित मुक़दमों के जल्द निपटारे पर जोर देना शुरू किया है. जनता को जल्द न्याय दिलाने की दिशा में क़दम उठाते हुए सरकार ने न सिर्फ़ न्यायाधीशों के ख़ाली पदों को जल्द भरने, सीबीआई की 71 अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का फ़ैसला किया है, बल्कि पिछले दिनों विभिन्न अदालतों में अनुबंध के आधार पर 15 हज़ार से ऊपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी अहम फ़ैसला लिया गया है. यही नहीं, गांव-गांव न्याय की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में ग्राम न्यायालय क़ानून पारित करना भी एक अच्छा क़दम है. ग्राम न्यायालय परियोजना के अस्तित्व में आने के बाद स्वाभाविक रूप से जहां ज़िला अदालतों पर काम का बोझ कम होगा, वहीं जनता को जल्दी न्याय भी मिलेगा.

इन सुधारों के अलावा मुक़दमा निपटारे की समय सीमा क्या हो? इस बिंदु पर भी विधि आयोग को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है. हमारे यहां छोटे से छोटे मामले के निपटारे में बरसों लग जाते हैं, जबकि यदि सही तरीक़े से इनकी सुनवाई हो तो ये महज़ कुछ महीनों में सुलझाए जा सकते हैं. इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी अदालतों की कार्य प्रणाली भी ज़िम्मेदार है. गवाहों का उपस्थित न होना, सम्मन तामीली न होना, अभियोजन पक्ष द्वारा समय पर चालान न पेश करना और गवाही न कराना जैसी लापरवाहियों के चलते कई बार न्यायाधीश चाहकर भी सुनवाई और जल्दी न्याय नहीं कर पाते. होना यह चाहिए कि कानून का पालन कराने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं, अभियोजन पक्ष और वकील अपना-अपना काम ईमानदारी से करें. बार-बार स्थगन की प्रवृत्ति पर रोक लगे, अभियोजन पक्ष को सक्षम और मुस्तैद बनाया जाए, न्यायाधीशों के लिए इन्सेंटिव सिस्टम लाया जाए और इंवेस्टीगेशन विंग को पुलिस से अलग किया जाए. एक अच्छी कोशिश तो यह होगी कि प्री कोर्ट प्रोसिडिंग सिस्टम लाकर मामले को अदालत में जाने से पहले ही निपटा दिया जाए.

बहरहाल, जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में दिल्ली हाईकोर्ट की इस बेजोड़ पहल का देश भर में स्वागत किया गया तो कई जगह विरोध भी हुआ. विरोध करने वालों ने क्वालिटी ऑफ जस्टिस की दुहाई देते हुए कहा कि जज टारगेट का बोझ लेकर जब मुक़दमे सुनेंगे तो सिर्फ़ केस निपटेंगे, लेकिन मुवक्किलों को इंसाफ भी मिलेगा, इसमें शक है. ज़ाहिर है, वकीलों की इस दलील के पीछे मुवक्किलों को इंसाफ के दर्द से ज़्यादा अपने रोज़गार की चिंता ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जितनी जल्दी मामले निपटेंगे, उनका आर्थिक नुक़सान होगा. पीड़ित शख्स हमेशा चाहता है कि उसे इंसाफ जल्द मिले, लेकिन दोषी इसके उलट मामले को लंबा खींचना चाहता है. इस काम में उसकी मदद करते हैं वकील. लिहाज़ा अदालतों में लंबित मुक़दमे बढ़ते चले जाते हैं. कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार से ही मौजूदा न्याय व्यवस्था सुधारी जा सकती है. सुधारों की दिशा में जहां-जहां भी कोशिशें हो रही हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, न कि विरोध. आम जनता का क़ानून व्यवस्था में विश्वास बना रहे, उसके लिए भविष्य में इस तरह के और भी क़दम बेहद ज़रूरी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ओबामा का भारत दौरा

22-28 नवंबर के अंक में यह दोस्ती ख़तरनाक है, शीर्षक से प्रकाशित आलेख के तहत लेखक ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे का बेबाकी से विश्लेषण किया है. वाकई ओबामा हमें कुछ दे नहीं गए, बल्कि बहुत कुछ मांग-झपट ले गए. हर समझौते के ज़रिए उन्होंने वह सब कुछ पा लिया, जिसकी वह उम्मीद लगाकर या फिर कहें कि योजना बनाकर आए थे.

–आदित्य सिंह, छपरा, बिहार.

रक्षा मंत्रालय ध्यान दे

आवरण कथा-सेना की मध्य कमान में आदर्श सोसाइटी से बड़ा घोटाला पढ़ी. जानकर आश्चर्य हुआ कि बड़े एवं ज़िम्मेदार अफसर सेना का नाम डुबो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में सेना के पास बड़ी संख्या में बेशक़ीमती ज़मीनें हैं, जिनके संरक्षण के बजाय उन्हें मटियामेट करने का काम हो रहा है. रक्षा मंत्रालय को इस ओर शीघ्र ही कठोरतम क़दम उठाने चाहिए, क्योंकि सैनिक क्षेत्रों में असैनिक लोगों की घुसपैठ बहुत चिंतनीय है.

–राम कुमार पांडेय, *मेरठ, उत्तर प्रदेश.*

बेरोज़गारी का दंश

आलेख-रोज़गार की तलाश में पलायन जारी पढ़ा. यह उस कड़वी हक़ीक़त को आईना करता है, जिसने सिर्फ़ मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ को नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों को अपनी गिरफ़्त में ले रखा है. अपने गांव-शहर में अगर लोगों को रोज़गार मिलने लगे तो उन्हें क्या पड़ी है कि वे दूसरों शहरों-प्रदेशों की शरण लें. सरकार यदि इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करे तो पलायन का यह सिलसिला रुक सकता है.

–गिरधारी लाल, *जनकपुरी, नई दिल्ली.*

परदेस का कड़वा सच

कुमार सुशांत की रिपोर्ट न जइयो परदेस दिल को छू गई. नोएडा और दिल्ली के कई इलाक़ों का यही सच है, जहां दो वक़्त की रोटी जुटाने के लिए बाहर से आए युवाओं को स्थानीय दबंग बहला-फुसला और धमका कर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में चल रहे जुआड़खानों एवं अवैध सिनेमाघरों की जानकारी इलाकाई पुलिस को न हो, बल्कि वह भी काली कमाई के मोह में चुप्पी साधे हुए है.

–वीरपाल, *सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

बुनकरों की बदहाली

चंदेरी साड़ी उद्योग के बदहाल वर्तमान के बारे में पढ़कर दु:ख हुआ. बुनकर दिन-रात काम करके भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, यह केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म का विषय है. कुछ लोग बुनकरों की कला की बदौलत मालामाल हो रहे हैं और बुनकर कल की चिंता में घुल रहे हैं. अगर समय रहते इस दिशा में ठोस क़दम न उठाए गए तो यह कला एक दिन विलुप्त हो जाएगी.

–सत्येंद्र सक्सेना, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

करियर पर विशेष पृष्ठ

चौथी दुनिया में अगर करियर एवं एजूकेशन से संबंधित एक पृष्ठ शामिल कर दिया जाए तो अच्छा होगा. इससे हम युवाओं को नई-नई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय जानकारियों के साथ-साथ मार्गदर्शन भी मिलेगा. युवा वर्ग के लिए यह पृष्ठ काफी लाभदायक साबित हो सकता है.

–समीर, *गया, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के उपरोक्त उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि कोई किसी से कम नहीं है.

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह बिहार और विकास की जीत है

संतोष भारतीय

दो कहावतें हैं. एक लालू यादव और राम विलास पासवान पर तथा एक कांग्रेस पर लागू होती है. कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी हम सबने बचपन में पढ़ी भी है और जीवन में कई बार सुनी भी है. खरगोश सोचता था कि कछुआ कहां उसके सामने दौड़ पाएगा, इसलिए आराम कर लो, बाद में दौड़ कर हरा ही दूंगा. लालू यादव को लगता था कि वह और राम विलास पासवान मिल जाएंगे तो ताक़तवर दो समाजों का गठजोड़ हो जाएगा. यादव और पासवान और फिर मुसलमान उनके साथ रहेगा ही. वह भाजपा के साथ जाएगा नहीं. दोनों ने खरगोश की तरह सोचा और आराम से छह महीने पहले पंद्रह साल पुरानी रणनीति पर अमल करने लगे. नीतीश ने दो साल में ख़ामोश चेतना पैदा कर दी, आशाएं पैदा कर दीं. कछुआ जीत गया और एक बार फिर खरगोश हार गया.

कांग्रेस ने हिसाब लगाया कि यदि वह सभी दो सौ तैंतालिस सीटों पर चुनाव लड़े तो कम से कम चालीस सीटें मिलेंगी. राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया. चुनाव से पहले राहुल गांधी पटना में लड़कियों के कॉलेज में गए. कहा कि नौजवानों को टिकट देंगे. पर टिकट बंटे तो, लेकिन मिले उन्हें, जिन्होंने टिकटों के लिए पैसा दिया. पांच या सात बड़े लोगों की सिफारिशों से टिकट बंटे, जिनमें ठेकेदारों ने पैसे लिए. पार्टी की कोई रणनीति थी ही नहीं. सारा हिसाब-किताब सही था कि दो सौ तैंतालिस में चालीस सीटें आ जाएंगी और कांग्रेस बैलेंसिंग स्थिति में आ जाएगी. कांग्रेस का यह हिसाब नदी के किनारे खड़े उस आदमी की तरह था, जिसने नदी की गहराई का औसत निकाला और नदी पार करने लगा. नदी पार करने के बाद देखा कि उसका लड़का है ही नहीं. वह डूब गया था. वह सोचने लगा कि औसत तो ठीक था, फिर लड़का डूबा क्यों. बिहार की चुनावी नदी में कांग्रेस का लड़का डूब गया, अब कांग्रेस हिसाब-किताब कर रही है.

इस बार बिहार चुनाव की ख़ासियत यह भी रही है कि राज्य की जनता ने धर्म के नाम पर वोट को बंटने नहीं दिया. बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया है. पहली बार बिहार के मुसलमानों ने भावनात्मक मुद्दों को दरकिनार कर वोटिंग की है. पहली बार बिहार के मुसलमानों ने पूरे राज्य की समस्याओं, विकास और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से ख़ुद को जोड़कर वोटिंग की है. पहली बार बिहार के मुसलमानों ने राजनीति की मुख्यधारा में हिस्सा लिया और चुनाव नतीजों की रंगत ही बदल दी. बिहार में 16.5 फ़ीसदी आबादी मुसलमानों की है. राज्य के 87 फ़ीसदी मुसलमान गांवों में रहते हैं, सिर्फ़ 13 फ़ीसदी शहर में. बिहार में मुसलमान सबसे पिछड़ा समुदाय है. गांवों की हालत ख़राब है. मुसलमान ग़रीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोज़गार हैं. ज़्यादातर मुसलमान भूमिहीन या छोटे किसान हैं. चुनाव के वक़्त हर दल ख़ुद को उनका मसीहा साबित करने में लग जाता है. कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा देता है तो कोई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का आश्वासन देता है. आज़ादी हासिल हुए 63 साल हो गए. बिहार में हर रंग की सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मुसलमानों की हालत साल दर साल ख़राब होती गई. समस्या यह है कि मुसलमानों का वोट पाने वाली पार्टियां उनकी समस्याओं को ख़त्म करना तो दूर, चुनाव के बाद उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाती हैं. कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों को लगता है कि मुसलमानों को भावनात्मक विषयों में उलझा कर वोट पाया जा सकता है. इस बार ऐसे दलों और नेताओं को बिहार के मुसलमानों ने नकार दिया. यही वजह है कि अब तक लालू यादव और राम विलास पासवान को समर्थन देते आए बिहार के अल्पसंख्यकों ने उनका दामन छोड़ दिया. कांग्रेस पार्टी ने क़रीब पचास मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और चुनाव से कुछ वक़्त पहले एक मुसलमान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन इस रणनीति से कांग्रेस को फ़ायदा नहीं पहुंचा और पार्टी सिर्फ़ चार सीटों पर ही सिमट कर रह गई. बिहार में करीब 54 सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या बीस फ़ीसदी से ज़्यादा है. इन चुनाव क्षेत्रों में मुसलमानों का समर्थन निर्णायक है. हैरानी की बात यह है कि इन 54 सीटों में से चालीस से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है. इन सीटों पर भाजपा या जदयू की जीत का मतलब तो यही है कि बिहार के मुसलमान और दूसरे समुदाय के लोग एक ही तरह से सोच रहे थे. उर्दू टीचरों की बहाली, बिहार में सड़कों का बनना, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी और कानून व्यवस्था का बेहतर होना बिहार के मुसलमानों को भी पसंद आया. चुनाव के नतीजे इस बात को साबित करते हैं कि दूसरे समुदायों की तरह बिहार के मुसलमानों ने भी एक बेहतर सरकार और विकास के पक्ष में वोट दिया. यह कहा जा सकता है कि भारत की चुनावी राजनीति में यह चुनाव मील का पत्थर साबित होगा.

बिहार चुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं. सबसे पहली वजह यह है कि बिहार की जनता ने चुनाव को जातिपात के बंधन से मुक्त कर दिया है. बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने विकास के रथ पर सवार होकर जो तीर छोड़ा, वह बिल्कुल निशाने पर लगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव की लालटेन बुझ गई तो राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की झोपड़ी भी उड़ गई. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ बिहार की राजनीति में ओझल हो गए. काफ़ी सालों बाद एक अच्छी सरकार का स्वाद चखने वाली जनता ने नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है. राज्य को आगे ले जाने की फिर से उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी है. एनडीए गठबंधन को तीन चौथाई बहुमत हासिल हुआ है. नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटें मिलीं, जबकि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिलीं. दोनों दलों को कुल मिलाकर 206 सीटों पर जीत मिली है, जबकि राजद और लोजपा गठबंधन 25 सीटों पर सिमट कर रह गया. लालू यादव का मुस्लिम और यादव वोट बैंक और राम विलास पासवान का दलित वोट बैंक किसी भी ताकतवर विरोधी को चुनाव में हराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन चुनाव के नतीजों से यह साबित होता है कि बिहार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया.

दरअसल यह बिहार के लोगों की जीत है. बिहार की जनता बिहार को तरक़्क़ी के रास्ते पर देखना चाहती है. बिहार की राजनीति में अब तक जातिपात की रोटी सेंक कर राज करने वाले राजा होते थे. राजनीतिक दलों ने यह मान लिया था कि बिहार की जनता सिर्फ़ जाति के आधार पर वोट डालती है, लेकिन लोगों ने इस बार मतदान में जो उत्साह दिखाया, युवाओं और ख़ासकर महिलाओं ने जिस प्रकार आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में जातिपात की दीवार को गिरा दिया. वोट बैंक की राजनीति को एक सिरे से नकार दिया. बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. अंधकार के उस दौर में फिर से नहीं जाना चाहते, जहां ख़ौफ़ और निराशा जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था. यही वजह है कि लालू यादव और राम विलास पासवान की पार्टियों के परंपरागत समर्थकों ने उन्हें छोड़ दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हार गईं. अगर लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया होता तो राबड़ी देवी अपने ही घर की सीट राघोपुर से कभी नहीं हारतीं. राम विलास पासवान के भाइयों को हार का सामना नहीं करना पड़ता. कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में काफी कन्फ्यूजन फैलाया, लेकिन पार्टी को महज चार सीटें मिली हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महबूब अली कैसर और साधु यादव को भी चुनाव में हार झेलनी पड़ी है. विश्लेषक यह कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी अगड़ी जाति का समर्थन पाएगी, जिसका नुक़सान नीतीश कुमार को होगा, लेकिन बिहार की जनता जातिपात की राजनीति से आगे निकल चुकी थी. नीतीश कुमार ने जनता की नब्ज़ को समझा. भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा कर उसका समर्थन हासिल किया. नीतीश विकास के मुद्दे पर डटे रहे. जातिपात की राजनीति और विकास की इस लड़ाई में वोटरों ने विकास को चुना. बिहार की जनता ने एक ऐसा फ़ैसला दिया, जिसकी उम्मीद ख़ुद नीतीश कुमार को भी नहीं थी.

दरअसल यह बिहार के लोगों की जीत है. बिहार की जनता बिहार को तरक़्क़ी के रास्ते पर देखना चाहती है. बिहार की राजनीति में अब तक जातिपात की रोटी सेंक कर राज करने वाले राजा होते थे. राजनीतिक दलों ने यह मान लिया था कि बिहार की जनता सिर्फ़ जाति के आधार पर वोट डालती है, लेकिन लोगों ने इस बार मतदान में जो उत्साह दिखाया, युवाओं और ख़ासकर महिलाओं ने जिस प्रकार आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में जातिपात की दीवार को गिरा दिया.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

नार्वे नहीं, सोमालिया की राह पर

राजीव रंजन तिवारी

दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया और सबसे अमीर देश नार्वे है. पिछले वर्ष भारत अमीरी के मामले में 78वें स्थान पर था, इस वर्ष 88वें पर है. यानी अमीरी के मामले में हम दस पायदान पीछे खिसके हैं. भ्रष्ट देशों के मामले में पिछले वर्ष भारत 85वें पायदान पर था, इस वर्ष 87वें स्थान पर है. यानी भारत सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया का अनुकरण कर रहा है, अमीर देश नार्वे का नहीं. हाल में लंदन के लेगाटुम इंस्टीट्यूट ने दुनिया के 110 सबसे अमीर देशों की एक सूची जारी की है, जिसमें नार्वे का नाम दुनिया के सबसे संपन्न मुल्क के तौर पर सामने आया है, जबकि दुनिया के सबसे भ्रष्ट 178 देशों की सूची में सोमालिया का स्थान सबसे ऊंचा है. वह 178वें स्थान पर है. भारत का स्थान पहले 85 था, अब 87 है. बताते हैं कि देश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामलों से इसकी रैंकिंग बिगड़ी है.

भारत में आज हर ओर भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार गूंज रहा है. भ्रष्टाचार करने वाले, भ्रष्टाचार रोकने वाले, भ्रष्टाचार पर हल्ला मचाने वाले और भ्रष्टाचार पर चुप रहने वाले सबकी दशा एक जैसी लग रही है. केंद्र से लेकर राज्यों तक और ब्लॉक से लेकर गांवों तक भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई से पसरी हुई हैं, जिसे ख़त्म करना आसान नहीं लगता. भ्रष्टाचार के सवाल पर कॉमनवेल्थ गेम्स के कर्ताधर्ता सुरेश कलमाड़ी की कथित करतूत से लेकर प्रसिद्ध उद्योगपति रतन नवल टाटा द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच का फ़ासला इतना भयावह है कि हर कोई सिहर उठे. रोज नए-नए घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं. इससे प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार अब संस्कृति का स्वरूप लेता जा रहा है. साथ ही भ्रष्टाचार संबंधी नए-पुराने मुद्दों का उठना नित नए कीर्तिमानों को भी बढ़ा रहा है.

कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में हुए घपले की जांच चल रही है. इस जांच की आंच के लपेटे में सुरेश कलमाड़ी हैं. उन पर जांच एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. इससे लगता है कि ख़ुद को पाक-साफ़ बताने वाले कलमाड़ी का दामन दागदार है और उन्होंने नियम-क़ायदों को ताक पर रखकर आर्थिक अनियमितताएं बरती हैं. जहां कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वहीं कलमाड़ी जैसों की वजह उसके दामन पर दाग भी लगा है. महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदर्श आवासीय सोसाइटी घोटाले में इस कदर फंसे कि उन्हें अपनी कुर्सी तक से हाथ धोना पड़ गया. अब उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है. आदर्श आवासीय सोसाइटी के 103 सदस्यों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ संभव है. चव्हाण ने करगिल युद्ध के नायकों और शहीदों की विधवाओं के लिए बनाई गई आदर्श आवासीय सोसाइटी में आम नागरिकों को रहने देने की सिफ़ारिश कर दी. यह करते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आई, यह समझ से परे है. दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित इस 31 मंजिला इमारत में चव्हाण के तीन परिजनों के अपने फ्लैट भी हैं. स्पेक्ट्रम घोटाले में लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये का चूना लगाकर फंसने के बाद केंद्रीय मंत्री ए राजा ने इस्तीफ़ा दिया. हालांकि उनसे इस्तीफ़ा लेने के लिए कांग्रेस थोड़ी सी प्रशंसा की हकदार है, लेकिन इसे किसी भी रूप में सजा नहीं माना जा सकता. यह महज़ एक अच्छा पहला क़दम है.

इन इस्तीफ़ों के साथ नैतिकता और शुचिता के ऊंचे दावे किए जा रहे हैं, जो नितांत झूठे हैं. इस्तीफ़े इस बात की स्वीकारोक्ति हैं कि वास्तव में कुछ ग़लत हुआ है. ए राजा जैसों से इस्तीफ़ा लेने का यह मतलब भी है कि सत्तारूढ़ पार्टी मानती है कि अपने भविष्य की ख़ातिर वह मीडिया के दबाव और जनाक्रोश से उदासीन नहीं रह सकती. टाटा समूह के प्रमुख रतन नवल टाटा द्वारा किए गए खुलासे से पता चलता है कि सिर्फ़ कांग्रेस ही नहीं, बाक़ी पार्टियों में भी भ्रष्टाचार का यह महारोग लगा हुआ है. कई वर्ष पूर्व टाटा से एयर लाइंस शुरू कराने के लिए एक मंत्री ने 15 करोड़ रुपये की रिश्वत मांग ली. टाटा ने समूह की कमान संभालने के बाद तीन बार 1995, 1997 और 2001 में एयर लाइंस कारोबार में क़दम रखने की कोशिश की थी. तीन-तीन प्रधानमंत्रियों से मिलने के बाद भी उनका काम नहीं हो सका. भ्रष्टाचार विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है. बेहतर होगा कि हमारे शासक समय रहते चेत जाएं, वरना यह घुन एक दिन पूरी व्यवस्था को ही चट कर जाएगा.

प्रख्यात उद्योगपति एवं सांसद राहुल बजाज ने टाटा से एक क़दम आगे बढ़ते हुए कहा कि कई औद्योगिक घराने काम निकालने के लिए रिश्वत देते रहते हैं. कर्नाटक के भाजपाई मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा पर भी आरोप लग गया कि उन्होंने राज्य में भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत वितरित करने के उद्देश्य से गुजरात के सूरत शहर की एक फर्म से अधिक मूल्य पर साड़ियां ख़रीदीं. इसके लिए करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए. येदियुरप्पा ने बंगलुरू विकास प्राधिकरण का चेयरमैन रहते हुए अपने बेटे-बेटियों को उपहार में ज़मीन दी. उन्होंने ज़मीन को अवैध रूप से डिनोटिफाई करने की स्वीकारोक्ति भी कर ली है. विपक्ष के दबाव से परेशान होकर उन्होंने अपनी ग़लतियां मानी हैं. उन्होंने संकल्प लिया है कि भविष्य में वह नियम-क़ायदों को दरकिनार कर कोई काम नहीं करेंगे. भाजपा को भी चाहिए कि वह येदियुरप्पा से इस्तीफ़ा ले, लेकिन भाजपा ने यह करने से न सिर्फ़ मना किया है, बल्कि यहां तक कह दिया कि वह अपने पद पर बने रहेंगे.

भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के उपरोक्त उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि कोई किसी से कम नहीं है. भ्रष्टाचार करने की जब भी बारी आती है अथवा मौक़ा मिलता है, सभी दिल खोलकर यह काम करते हैं. जिस तरह भारत के राजनेता-नौकरशाह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया को हम अपना रोल मॉडल मान रहे हैं. अंत में सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि हम अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत छोड़ें, ताकि वह कह सके कि हां, घोटाला कोई ऐसी चीज थी, जिसके बारे में हमारे पितामह बात किया करते थे.

प्रख्यात उद्योगपति एवं सांसद राहुल बजाज ने टाटा से एक क़दम आगे बढ़ते हुए कहा कि कई औद्योगिक घराने काम निकालने के लिए रिश्वत देते रहते हैं. कर्नाटक के भाजपाई मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा पर भी आरोप लग गया कि उन्होंने राज्य में भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत वितरित करने के उद्देश्य से गुजरात के सूरत शहर की एक फर्म से अधिक मूल्य पर साड़ियां ख़रीदीं. इसके लिए करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए.

feedback@chauthiduniya.com

फुल बॉडी स्कैनर को हवाई अड्डों पर इसलिए लगाया गया है, ताकि आतंकवादी हमलों पर काबू पाया जा सके.

राष्ट्रमंडल खेल का हिसाब मांगें

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

राष्ट्रमंडल खेल खत्म हो गए हैं. इन खेलों पर जो पैसा ख़र्च हुआ है, वह हमारा-आपका पैसा था. अगर यह पैसा करों के रूप में न वसूला गया होता तो हम-आप इसे अपने परिवार के लिए कई तरह की सुविधाएं और सामान जुटाने पर ख़र्च कर सकते थे, इसे अपने क्षेत्र, अपने गांव या शहर की बेहतरी पर ख़र्च कर सकते थे. सरकार ने देश का विकास करने के नाम पर हमसे वह पैसा करों के रूप में लिया और हुआ क्या? हम लोग सब्ज़ी वाले, दूध वाले और रिक्शे वाले को दिए गए एक-एक रुपये का हिसाब-किताब करते हैं. यहां तक कि अपने बच्चों को पैसा देते हैं तो उनसे भी हिसाब पूछते हैं. ऐसे में क्या अपनी मेहनत के अरबों रुपये की चोरी पर सवाल नहीं उठाएंगे? क्या सिर्फ़ जांच समिति, सीवीसी और सीबीआई के सहारे बैठे रहेंगे? इन खेलों में हुए घपलों की जांच सरकार के स्तर पर की जा रही है, लेकिन एक जांच देश की जनता को भी करनी चाहिए. सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम सबको यानी देश के अधिक से अधिक लोगों को सवाल उठाने होंगे. यहां हम कुछ ऐसे ही सवाल प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि आप इस मुद्दे पर अधिक से अधिक सवाल पूछ सकें.

गाड़ियों पर हुआ ख़र्च

1. 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कॉमनवेल्थ आर्गेनाइज़ेशन कमेटी के पास कुल कितनी गाड़ियां रहीं?
2. इस बारे में निम्न विवरण भी उपलब्ध कराएं:
   (क) उपरोक्त में से कितनी गाड़ियां किराए पर ली गई थीं?
   (ख) कितनी गाड़ियां समिति की अपनी थीं?
   (ग) कितनी गाड़ियां किसी अन्य विभाग या संस्था की ओर से उपलब्ध थीं?
3. उपरोक्त गाड़ियों की सूची निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) वाहन का प्रकार (बस, कार इत्यादि).
   (ख) वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या.
4. 25 सितंबर 2010 से 15 अक्टूबर 2010 के बीच प्रत्येक गाड़ी कितने-कितने किलोमीटर चली?

स्वास्थ्य सेवाएं

1. कॉमनवेल्थ विलेज में कुल कितने चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे?
2. कुल कितने लोगों ने इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लिया?
3. इन केंद्रों के परिचालन पर कुल कितनी राशि ख़र्च की गई?
4. इन केंद्रों पर कुल कितने चिकित्साकर्मी तैनात किए गए?
5. इन केंद्रों से कुल कितने लोगों को आगे इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित किया गया?

उद्घाटन समारोह के टिकट

1. कॉमनवेल्थ खेलों के उद्घाटन समारोह में टिकटों की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?
2. उद्घाटन समारोह के लिए मूल्य के आधार पर कुल कितने प्रकार की टिकट श्रेणियां (स्लैब) बनाई गईं?
3. इनमें से प्रत्येक श्रेणी का विवरण निम्न जानकारी के साथ दें:
   (क)टिकट दर.
   (ख) प्रत्येक श्रेणी में बिक्री के लिए उपलब्ध कुल टिकटों की संख्या.
   (ग) प्रत्येक श्रेणी में बिके कुल टिकटों की संख्या.
   (घ) प्रत्येक श्रेणी में टिकटों की बिक्री से अर्जित राशि.
4. उद्घाटन समारोह के दौरान स्टेडियम में कुल कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था थी?
5. उपरोक्त में से कुल कितनी सीटें टिकट बिक्री के ज़रिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी?

इसी प्रकार समापन समारोह के टिकटों के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं.

विज्ञापनों पर हुआ ख़र्च

कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति द्वारा एक अप्रैल 2010 से लेकर इस पत्र का जवाब दिए जाने तक विभिन्न समाचारपत्रों, पत्रिकाओं एवं समाचार चैनलों को दिए गए विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. इस दौरान समिति द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि ख़र्च की गई?
2. समिति द्वारा विज्ञापन देने का कार्य किन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया? उनके संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दें:
   (क) एजेंसी का नाम.
   (ख) एजेंसी को भुगतान की गई राशि.
3. आयोजन समिति ने बगैर विज्ञापन एजेंसी के कितनी राशि के विज्ञापन सीधे जारी किए?
4. प्रत्येक एजेंसी अथवा समिति द्वारा सीधे समाचार माध्यमों को जारी किए गए विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएं:
   (क) विज्ञापन का विषय/नाम.
   (ख) विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित होने की तारीख.
   (ग) जिस कंपनी, अख़बार, पत्रिका या टेलीविजन चैनल को विज्ञापन दिया गया, उसका नाम एवं पता.
   (घ) विज्ञापन के लिए भुगतान की गई राशि, भुगतान का माध्यम नकद, चेक या कोई अन्य, विवरण दें. (यदि भुगतान चेक से किया गया हो तो चेक नंबर दें, यदि नकद या किसी अन्य माध्यम से किया गया हो तो प्राप्ति रसीद की प्रति दें.)

(यही सवाल दिल्ली सरकार से भी पूछे जाने हैं)

पत्र व्यवहार

पीएमओ-प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अगस्त से अक्टूबर के बीच कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ किए गए पत्र व्यवहार की छाया प्रति उपलब्ध कराएं. (विषय से संबंधित विभिन्न ईमेल, आदेशों एवं दिशानिर्देशों आदि की छाया प्रतियां भी उपलब्ध कराएं)

सीएमओ-मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अगस्त से अक्टूबर के बीच कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ किए गए पत्र व्यवहार की छाया प्रति उपलब्ध कराएं. (विषय से संबंधित विभिन्न ईमेल, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों आदि की छाया प्रतियां भी उपलब्ध कराएं)

एलजी कार्यालय-उप राज्यपाल कार्यालय द्वारा अगस्त से अक्टूबर के बीच कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ किए गए पत्र व्यवहार की छाया प्रति उपलब्ध कराएं. (विषय से संबंधित विभिन्न ईमेल, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों आदि की छाया प्रतियां भी उपलब्ध कराएं)

ओसी- अगस्त से अक्टूबर के बीच कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय (दिल्ली सरकार) एवं उप राज्यपाल कार्यालय (दिल्ली) के साथ किए गए पत्र व्यवहार की छाया प्रति उपलब्ध कराएं. (विषय से संबंधित विभिन्न ईमेल, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों आदि की छाया प्रतियां भी उपलब्ध कराएं)

उद्घाटन/समापन समारोह पर ख़र्च

1. कॉमनवेल्थ खेलों के उद्घाटन समारोह पर आयोजन समिति की ओर से कुल कितनी राशि ख़र्च की गई?
2. इस ख़र्च का मद वार ब्योरा उपलब्ध कराएं.
3. कॉमनवेल्थ खेलों के समापन समारोह पर आयोजन समिति की ओर से कुल कितनी राशि ख़र्च की गई?
4. इस ख़र्च का मद वार ब्योरा उपलब्ध कराएं.

होटलों पर ख़र्च

1. कॉमनवेल्थ आयोजन समिति के रिकार्ड के मुताबिक़ खेलों में शामिल होने के लिए कुल कितने विदेशी खिलाड़ी एवं अन्य प्रतिनिधि आधिकारिक रूप से भारत आए?
2. इनमें से कितने खिलाड़ी या प्रतिनिधि कॉमनवेल्थ खेल विलेज में रहे?
3. इनमें से कितने लोगों को सरकारी ख़र्चे पर होटल में ठहराया गया?
4. आयोजन समिति के ख़र्चे पर होटलों में ठहराए गए लोगों की सूचना निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) मेहमान का नाम.
   (ख) मेहमान का देश.
   (ग) होटल का नाम.
   (घ) होटल में ठहरने की अवधि (किस तारीख़ से किस तारीख़ तक)
   (च) होटल को अदा की गई राशि.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बॉडी स्कैनर या आतंकवादी हमला

जब आप विमान यात्रा करते हैं तो आप और बाक़ी यात्रियों पर आतंकवादी हमला होने का ख़तरा कितना होता है? एक अनुमान के अनुसार इसकी आशंका 3 करोड़ में 1 होती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी ही आशंका बॉडी स्कैनर से निकलने वाले रेडिएशन से भी होती है. इन दोनों में समानता इसलिए बताई जा रही है, क्योंकि विमान यात्रा में आजकल आतंकवाद और स्कैनर दोनों से ही जानलेवा ख़तरा रहता है. पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि फुल बॉडी स्कैनर आख़िर होता क्या है? दरअसल पश्चिमी देशों के हवाई अड्डों पर अब इस तरह के बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं, जो यात्री के पूरे शरीर की जांच करते हैं. इन स्कैनरों का दो स्तरों पर व्यापक विरोध हो रहा है. कुछ खास तबके, जैसे मुस्लिम इस स्कैनर का इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे यात्रियों की नग्न छवियां जांच अधिकारियों को दिखती हैं. दूसरी ओर वैज्ञानिकों का एक वर्ग इस स्कैनर का इसलिए विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर होने का ख़तरा है.

एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के पीटर रेज़ के अनुसार, फुल बॉडी स्कैनर को हवाई अड्डों पर इसलिए लगाया गया है, ताकि आतंकवादी हमलों पर काबू पाया जा सके, लेकिन इस तरह के स्कैनर से उत्सर्जित रेडिएशन से भी इंसान को ख़तरा ही होता है. आम तौर पर इस तरह के स्कैनर बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि इनसे उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन की मात्रा काफी कम होती है और उनसे इंसान के शरीर को अधिक नुक़सान नहीं पहुंचता, परंतु यदि मशीन में जरा सी भी ख़राबी आ जाए तो नतीजे घातक हो सकते हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर से टकरा कर फैल जाने वाले रेडिएशन से चाहे ख़तरा न हो, परंतु चमड़ी पर इसका असर पड़ सकता है. हमारी चमड़ी रेडिएशन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और इससे चमड़ी के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है. हालांकि इस बारे में अभी और अधिक जांच की आवश्यकता है, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे?

एड्स का इलाज ख़तना

अफ्रीकी देश रवांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वे अगले दो सालों में देश में क़रीब बीस लाख लोगों का ख़तना करने की योजना बना रहे हैं. उनके मुताबिक़, यह पहल देश में एड्स के ख़तरे से निबटने के लिए की जा रही है. रवांडा ने स्वास्थ्य के मामले में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास के प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है. उसकी प्रमुख सफलता है एड्स के वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या में क़रीब 8 प्रतिशत की कमी. अब रवांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दिशा में और आगे क़दम बढ़ाते हुए फ़ैसला किया है कि वे एक अभियान चलाएंगे, जिसके तहत अगले दो सालों में क़रीब बीस लाख पुरुषों का ख़तना किया जाएगा. यह क़दम 2008 में आई उन रिपोर्टों के आधार पर उठाया जा रहा है, जिनमें कहा गया था कि ख़तना किए गए लोग सामान्य लोगों की तुलना में सहवास के दौरान 60 प्रतिशत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं. रवांडा में एड्स आयोग की अध्यक्ष डॉ. अनिता असिम्वे ने बताया कि देश में 2012 तक बीस लाख लोगों का ख़तना करने के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था की जा चुकी है.

डॉ. अनिता ने बताया कि शोधों के आधार पर यह बात साबित हो चुकी है कि पुरुषों का ख़तना उनके एचआईवी वायरस से प्रभावित होने की आशंका को 60 प्रतिशत तक कम कर देता है. यही वह आधार है, जिसने हमें एड्स से लड़ने के लिए इस दिशा में प्रेरित किया है. इसलिए हमारी योजना है कि हम अगले दो सालों में यानी 2012 के अंत तक बीस लाख पुरुषों का ख़तना करा सकें. हालांकि अभी तक रवांडा में आम तौर पर पुरुषों के ख़तने की परंपरा नहीं है. इसलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार अभियान चलाना पड़ेगा. स्वास्थ्य अधिकारियों को इस काम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. योजना की शुरुआत में सबसे पहले सेना एवं पुलिस के जवानों और विश्वविद्यालय के छात्रों के ख़तने का लक्ष्य रखा गया है और इनके लिए यह लगभग अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य विभाग देश के सभी नवजात शिशुओं के ख़तने के लिए प्रचार अभियान चला रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 06 दिसंबर–12 दिसंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आपको लग रहा था कि कोई चीज पीछे खींच रही है, मगर इस हफ्ते स्थिति साफ हो जाएगी. हर चीज पर पर्सनल टच की ज़रूरत है. अपनी योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें. वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
नई चुनौतियों का सामना करने और नई दिशा खोजने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे. आपको लगेगा कि बहुत सी चीजें हैं, जिन पर निर्णय करना है. अपना दिमाग़ और दिल खुला रखने की ज़रूरत है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस हफ्ते कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाज़ी न करें. आपका आत्मविश्वास ही आपकी ताक़त है. चीजों की सत्यता जांच लें. अच्छे ऑफर मिलेंगे, मगर किसी निर्णय लेने से पहले सारी जानकारी हासिल कर लें. काफी समय से लंबित कार्य पूरा होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
किसी नई खोज से प्रभावित होंगे और उसे पूरी दुनिया को बताना चाहेंगे. पर्सनल रिलेशन हो या बिजनेस डील, आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे. लोगों को नए तरीक़े से काम करना सिखाएं और उन्हें साथ लेकर आगे चलें. अपने स्टाइल से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आपको इस सप्ताह अपनी ऊर्जा पर फोकस करना होगा. यह सीखना होगा कि चीजें आपके पास आएं, न कि आप उनके पीछे दौड़ें. किसी भी बात पर सोच-समझ कर निर्णय लें. शांति और चुप्पी को एन्जॉय करने का समय निकालें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह अचानक कहीं दूर यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. घबराएं नहीं, ऐसी यात्रा मंगलमय रहेगी. दूसरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता का आपको अच्छा फल मिलेगा. आपकी भावनात्मक दिक़्क़तों में परिवार वाले मदद करेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
यह हफ्ता व्यापार एवं करियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है. स्थिति पर नियंत्रण के लिए दूसरों के विचार सुनें, तब अपनी रणनीति बनाएं. कभी-कभी आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस हफ्ते ख़ुद को समझना पड़ सकता है. बचाव की मुद्रा से बचें और आशावादी बनें. अपनी योजना को अच्छे वक़्त के इंतज़ार में न टालें. जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनसे ही अपना सुख-दुःख बांटें. अपने विचारों पर दूसरों की राय भी सुनें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस हफ्ते आपके लिए संतुलित होकर चलना ज़रूरी होगा. इस समय जिद्दी होना ग़लत साबित होगा. आपके गुस्से का कारण सामने आ जाएगा, जब आप अपने दिल की सुनेंगे. एक शख्स के रूप में आगे बढ़ने के लिए आपको हरसंभव नए अवसर मिलेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस हफ्ते आपको चीजों को लेकर एक नीति बनाकर चलने की ज़रूरत होगी. हालांकि आपके लिए खुद को फोकस करना मुश्किल होगा. इस हफ्ते आप फालतू कामों में उलझने के बजाय किसी काम को फोकस करना पसंद करेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
ज़िंदगी को वैसे ही चलने दें, जैसे चल रही है. जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, वह हक़ीक़त नहीं है, लेकिन सच जैसी ही ख़ूबसूरत है. इस हफ्ते आप जो लक्ष्य तय करेंगे, उसे पूरा कर पाएंगे. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस हफ्ते आपको अपनी व्यक्तिगत एवं आर्थिक स्थिति संभालने की ज़रूरत है. आपको अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है. व्यवसाय से संबंधित यात्रा सफल रहेगी. अगर आपके पास कोई विचार है तो उसे सामने रखें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

समय की ज़रूरत यही है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को नियमित किया जाए और इसके साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए.

ग़लती से सबक़ लेने की ज़रूरत

इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रदर्शन भी ठीकठाक रहता था, लेकिन उस दौर में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या उसका संकुचित स्वरूप था. सरकारी स्कूलों के नेटवर्क के विस्तार की गति धीमी थी और यह तेजी से बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था. सरकारी शिक्षण संस्थानों की पहुंच समाज के सभी वर्गों तक नहीं थी और निजी क्षेत्र इसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं था.

प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के एक बयान ने देश में एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है. गिलानी ने 1972 में ज़ुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों के राष्ट्रीयकरण के फ़ैसले को ग़लत क़रार दिया तो देश में शिक्षा की मौजूदा हालत से निराश लोगों ने उनकी हां में हां मिलानी शुरू कर दी. वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थक अपने नेता के समर्थन में उतर आए. बयान से शुरू हुए इस विवाद में दोनों पक्ष दो ध्रुवों में बंट चुके हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अधिकांश लोग उन परिस्थितियों से पूरी तरह अंजान हैं, जिनमें शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नीति को अंजाम दिया गया था. उन्हें उन कारणों की भी जानकारी नहीं है, जिनके चलते इस नीति के इतने गंदे परिणाम आज हमारे सामने हैं. मौजूदा दौर में जीवन के हर क्षेत्र में बाज़ारवाद हावी है, राज्य की भूमिका सीमित होती जा रही है. सामाजिक क्षेत्र में इसका असर यह होता है कि ग़रीब और कमज़ोर तबके के लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है और इसके लिए किसी को कोई अफसोस भी नहीं होता. कितने दु:ख की बात है कि गिलानी के बयान के पक्ष-विपक्ष में बोलने वाले लोगों ने भुट्टो की राष्ट्रीयकरण की नीति के ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की, न ही यह समझने का प्रयास किया कि उन्होंने इसे क्यों लागू किया और इसकी असफलता की वजहें क्या रहीं. आज जब इसे एक ग़लती क़रार दिया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह शायद मौजूदा समय में देश में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की ख़राब हालत है.

लेकिन इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण से पहले पाकिस्तान का शिक्षा तंत्र पूरी तरह चाक-चौबंद था. जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षा व्यवस्था में उस समय भी तमाम तरह की खामियां थीं, हालांकि उनका स्वरूप थोड़ा अलग था. इन खामियों का उपाय तलाशना ज़रूरी था, लेकिन ये उपाय तभी प्रभावी हो सकते थे, जब उन्हें ढंग से लागू किया जाता और राष्ट्रीयकरण की नीति के साथ ऐसा नहीं हो सका. 1972 से पहले तक देश में सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र, कम से कम स्कूल स्तर पर, निजी क्षेत्र से कहीं ज़्यादा विस्तृत था. उस समय देश भर में निजी क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था. सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन संतोषजनक ज़रूर थी. इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रदर्शन भी ठीकठाक रहता था, लेकिन उस दौर में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या उसका संकुचित स्वरूप था. सरकारी स्कूलों के नेटवर्क के विस्तार की गति धीमी थी और यह तेजी से बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था. सरकारी शिक्षण संस्थानों की पहुंच समाज के सभी वर्गों तक नहीं थी और निजी क्षेत्र इसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं था. दूसरी समस्या यह थी कि कुछेक अपवादों को छोड़कर निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान कुप्रबंधन के शिकार थे. शिक्षकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और भ्रष्टाचार चरम पर था. 1969 में कराची डिवीज़न के कमिश्नर ने कराची के निजी कॉलेजों की हालत की जांच-पड़ताल के लिए एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी को इन कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था का पता लगाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी और उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी.

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन संस्थानों में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता, कई बार उन्हें कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती. इतना ही नहीं, उन्हें जितना वेतन दिया जाता है, उससे ज़्यादा रकम पर उनके दस्तखत ले लिए जाते हैं. कमेटी ने एक ऐसे कॉलेज का उदाहरण भी दिया था, जहां एक पार्टटाइम शिक्षक प्रिंसिपल का काम कर रहा था. इसके अलावा अयोग्य शिक्षकों की बहाली की प्रथा भी काफी प्रचलित थी. कुछ ऐसी ही रिपोर्ट हमूदूर रहमान कमीशन ने भी दी थी, जिसे अयूब खां के जमाने में विश्वविद्यालयों में व्याप्त अशांति के कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था. उस समय वेस्ट पाकिस्तान कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं अनीता गुलाम अली पुराने दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि साल 1970 में एसोसिएशन ने भुट्टो को अपनी मांगों की एक सूची भेजी थी. अन्य बातों के अलावा इसमें सरकार से यह मांग की गई थी कि निजी कॉलेजों के शिक्षकों को सरकार ख़ुद वेतन दे और इन संस्थानों पर नज़र रखने के लिए एक नियामक संस्था गठित की जाए. राष्ट्रीयकरण व्यवस्था की इन कमज़ोरियों को दूर करने में सफल नहीं रहा. लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि सरकार इसके आर्थिक भार को ढोने में सक्षम नहीं थी, जैसा कि अक्सर लोग मानते हैं. इसका असल कारण इस नीति का कमज़ोर कार्यान्वयन और ख़राब प्रबंधन था, जिसकी आगोश में निजी शिक्षण संस्थान पहले से ही थे. राष्ट्रीयकरण के बाद इन संस्थानों के योग्य और अनुभवी शिक्षकों की जगह सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को भर दिया गया. यह बात पहले से ही स्पष्ट है कि विचारधारात्मक प्रतिबद्धता योग्यता का विकल्प नहीं हो सकती. सही अर्थों में देखा जाए तो स्कूलों के राष्ट्रीयकरण में कोई बुराई नहीं थी, बुराई इसके क्रियान्वयन में थी, जिसने शुरुआत में ही इसे नकारा बना दिया. ऐसा भी नहीं था कि सरकार राष्ट्रीयकरण के चलते बढ़े आर्थिक बोझ को ढोने में अक्षम थी. इससे पहले भी सरकार निजी शिक्षण संस्थानों को सब्सिडी उपलब्ध करा रही थी, ताकि वे समाज के हर तबके तक पहुंच सकें. अब यह बात और है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा इन संस्थानों के मालिकों की जेबों में चला जाता था. राष्ट्रीयकरण के बाद सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद फिर कभी दोबारा लागू नहीं किया गया.

1972 से पहले हो या मौजूदा दौर, समय की ज़रूरत यही है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को नियमित किया जाए और इसके साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए. इसके लिए प्रबंधन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और यही वजह है कि जियाउल हक के जमाने में निजी क्षेत्र को दोबारा पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया वापस लेने की शुरुआत हुई तो भी इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ. आज भी जबकि निजी शिक्षण संस्थानों का तेजी से विकास हो रहा है और देश भर के एक-तिहाई से भी ज़्यादा छात्र इनमें पढ़ रहे हैं, स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है. सच तो यह है कि देश के शिक्षा तंत्र की हालत बहुत ही ख़राब है. निजी क्षेत्र सस्ती दरों पर शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य अपने निवेश पर लाभ कमाना है. न ही वह दूरदराज के कम आय वाले इलाक़ों में अपना विस्तार करेगा. यह काम सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उसके पास ही इसके लिए संसाधन मौजूद हैं और यह सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी है.

राष्ट्रीयकरण की नीति की खामी यह थी कि इसे पेशेवर रूप से लागू नहीं किया गया. गिलानी इस बात को जितनी जल्दी समझ लें, पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा है. उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा रहे बड़े-बड़े निजी शिक्षण संस्थानों के विकास से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. अधिकांश बच्चे, जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, वे कम आय वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जो निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का ख़र्च नहीं उठा सकते. इसके बावजूद सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रही है. पूरी दुनिया में अधिकांश जगहों पर शिक्षा सरकार की ज़िम्मेदारी है और वह अपनी इस ज़िम्मेदारी को भलीभांति निभा भी रही है. भुट्टो की राष्ट्रीयकरण नीति की आलोचना करके गिलानी संभवत: शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ज़िम्मेदारी को कम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं.

ज़ुबैदा मुस्तफ़ा
feedback@chauthiduniya.com

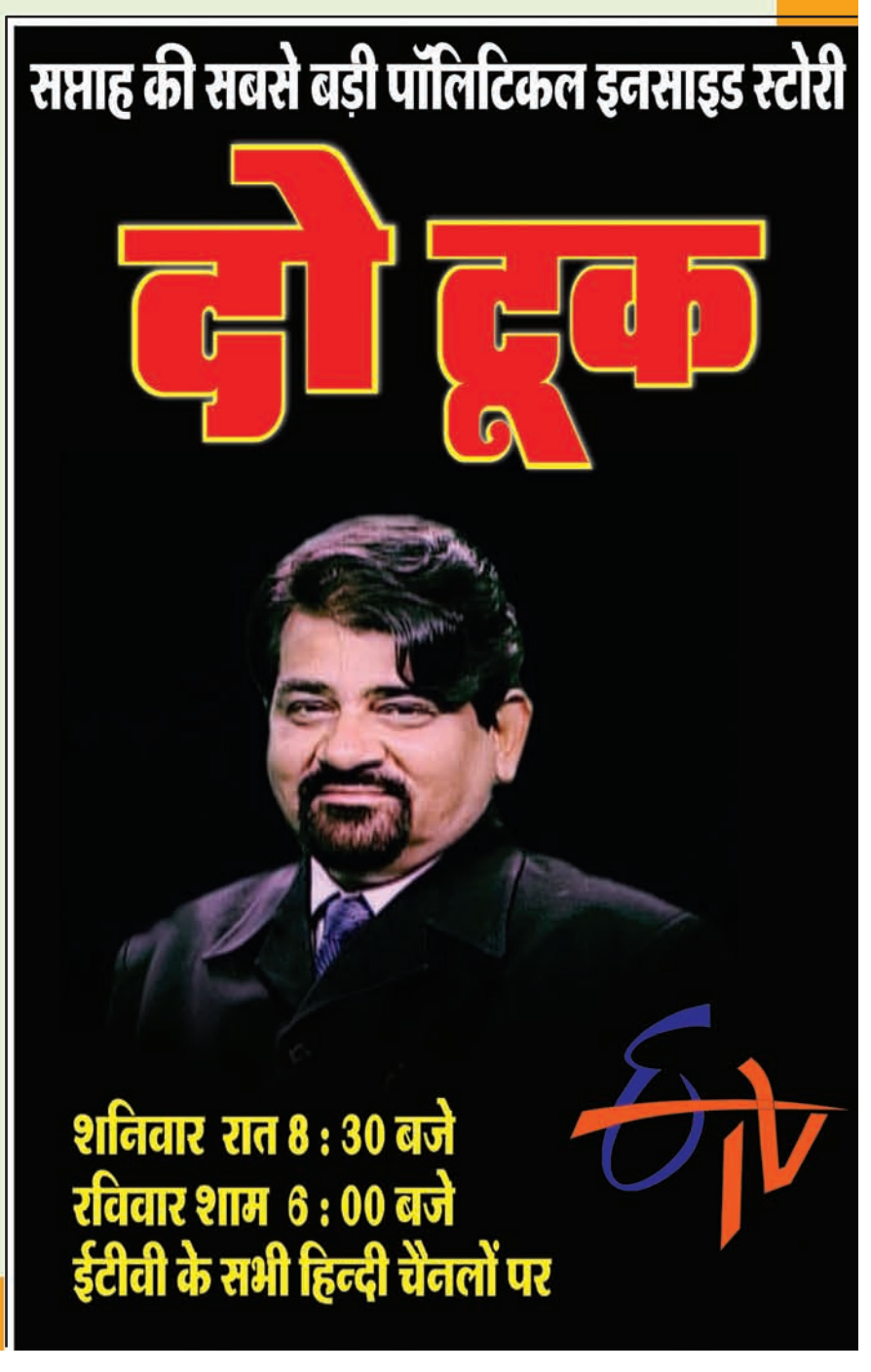

श्री साई का श्रद्धा-सबूरी का मंत्र भी निराशा से आशा और अंधेरे से उजाले की तरफ़ एक यात्रा है.

सबका मालिक एक

हेमाड पंत जी साई सच्चरित्र में लिखते हैं, बाबा अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक. आख़िर इस संदेश का मतलब क्या था? आइए बाबा के इसी संदेश पर कुछ बातें करें. बाबा के विषय में हम जितना मनन करते जाते हैं, उनके संदेशों को समझना उतना ही आसान होता जाता है. बाबा के बारे में लिखना और पढ़ना हम साई भक्तों को इतना प्रिय है कि उनकी एक लेखिका भक्त ने तो अपनी एक किताब में बाबा को ढेर सारे पत्र लिखे हैं. मेरा मानना है कि साई को पतियां लिखूं जो वह होय बिदेस. मन में, तन में, नैन में ताको कहा संदेस. लेकिन साई के विषय में बातें करना जैसे आत्म साक्षात्कार करना है. बाबा ने बहुत सहजता से कहा है, सबका मालिक एक. ऐसा कह पाना शायद बाबा के लिए ही संभव था, क्योंकि समस्त आसक्तियों और अनुरागों से मुक्त एक संत ही ऐसा कह सकता है. प्रचलित धर्म चाहे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध हो या कोई अन्य, प्रश्न यह है कि जो ये धर्म सिखा रहे हैं, क्या वह ग़लत है? अगर ग़लत न होता तो बाबा को इस धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता ही न होती.

हमारे उक्त सभी प्रचलित धर्म इतने कट्टर क्यों हैं कि अगर एक हिंदू किसी मुसलमान के साथ बैठता है या उसका छुआ खाता-पीता है तो उसका कथित धर्म भ्रष्ट हो जाता है. आप ख़ुद ही सोचिए कि वह धर्म ही क्या, जो छूने या खाने-पीने से भ्रष्ट हो जाए. एक कथा के अनुसार, परमात्मा ने देवों, दानवों एवं मानवों से जीवन की पहली सीख के रूप में केवल एक अक्षर कहा था, द. इसका अर्थ देवों के लिए था कि उन्हें अपने भोगों-आसक्तियों का दमन करना चाहिए. दानवों के लिए इसका अर्थ था कि उन्हें दया करनी चाहिए और मानव जाति के लिए संदेश था कि उसे दान करना चाहिए. बाबा ने कलयुग में एक बार फिर धरती पर आकर हमें इसी शिक्षा की याद दिलाई. प्रचलित धर्म भी इन तीनों शिक्षाओं पर अमल करने के लिए कहते हैं. सभी धर्मों के अनुसार, हमें अपनी आसक्तियों-भोगों का दमन करना चाहिए, क्योंकि सभी परेशानियां इन्हीं से शुरू होती हैं. इस्लाम में किसी भी प्रकार से ब्याज लेना मना है, जो आसक्ति को दूर करता है. कुरान शरीफ के अनुसार, जो मुसलमान अपने पड़ोसी को भूखा जानकर भी अपना पेट भर लेता है, वह अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनहगार है यानी अपने आसपास के सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना सच्चा मुसलमान कहलाने की ज़रूरी शर्तों में से एक है. ईद के पवित्र मौक़े पर फ़ितरा और ज़कात का लाजिम होना इस्लाम की दान संबंधी शिक्षा का एक रूप है.

श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 25 में वर्णन है कि श्री साई ने दामू अण्णा कसार की रुई और अनाज के सौदे में धनलाभ की आसक्ति को दूर किया. इसी प्रकार दूसरी शिक्षा है दया. बाबा की शिक्षा है कि जो भक्त दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह मेरे हृदय को दु:ख पहुंचाता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है. हमें प्रत्येक प्राणी पर दया करनी चाहिए. तीसरी शिक्षा है दान, जिसका हेमाड पंत जी ने श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 में दक्षिणा का मर्म के रूप में वर्णन किया है. बाबा ने रामनवमी और उर्स एक साथ मनाए, क्योंकि बाबा सिखाना चाहते थे कि सभी धर्म एक ही शिक्षा दे रहे हैं. इसीलिए वह सदैव कहा करते थे कि सबका मालिक एक. यह मालिक ही वह नूर है, वह शिक्षा है, जो हमें हमारे जन्म लेने का कारण बताता है.

अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे,
एक नूर से सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे.

साई अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, यही कामना है.

मानसिक चिकित्सा है श्रद्धा और सबूरी

साई के दिव्य संदेशों में श्रद्धा और सबूरी अपना विशेष स्थान रखते हैं. आज तक बहुत से ज्ञानी जनों ने श्रद्धा-सबूरी को कई विभिन्न दृष्टियों से प्रस्तुत किया. अपनी-अपनी मन:स्थिति के अनुसार सभी का कहना सही भी है, लेकिन मन में एक विचार और उठता है और समझ आता है कि वास्तव में बाबा का श्रद्धा-सबूरी का दिव्य संदेश एक मानसिक चिकित्सा या कहें कि मनोचिकित्सा का एक स्वरूप है. बाबा के पास पहुंचने वालों में ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में आ रही मुश्किलों से परेशान लोग होते हैं. हर कोई यह आशा लेकर पहुंचता है कि बाबा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देंगे. जिस प्रकार कोई परेशान व्यक्ति ज्योतिषी के पास पहुंचता है और ज्योतिषी उसे कोई नग पहनने की सलाह देता है. यही नग उस व्यक्ति के जीवन में आशा और विश्वास का संचार कर देता है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर दयानंद के अनुसार, अधिकतर रोग चिकित्सा से नहीं, बल्कि उस चिकित्सा में विश्वास से अच्छे होते हैं और यही ज्योतिष के साथ होता है. हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी और दु:ख का एक नियत समय होता है. एक समय के बाद रोग, परेशानियां और दु:ख स्वयं दूर हो जाते हैं, लेकिन इस सफ़र को तय करने में ज्योतिषीय उपाय और नग बहुत सहारा देते हैं. नग पहन कर व्यक्ति सदा स्मरण रखता है कि यह उसे उजाले की ओर ले जा रहा है. ठीक इसी प्रकार श्री साई का श्रद्धा-सबूरी का मंत्र भी निराशा से आशा और अंधेरे से उजाले की तरफ़ एक यात्रा है.

बाबा ने कहा, श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, अल्लाह भला करेगा. यह विश्वास और आश्वासन हमेशा भक्तों के लिए उजाले की किरण बनता रहा है. धूपखेड़ा गांव के चांद पाटिल से लेकर आज तक जिसने भी अपने मन में श्री साई के इन दो शब्दों को बसा लिया, उसका पूरी दुनिया तो क्या, स्वयं प्रारब्ध या कहें कि होनी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती. सिर्फ़ एक अटल विश्वास और अडिग यक़ीन आपको सारी मुसीबतों और तकलीफों के पार ले जा सकता है. बहुत से भक्तों को श्रद्धा-सबूरी का मतलब आज भी स्पष्ट नहीं है. वास्तव में बाबा ने कहा था कि अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने मालिक पर श्रद्धा रखो. यह विश्वास रखो कि भवसागर को पार अगर कोई करा सकता है तो वह आपका इष्ट, गुरु और मालिक है. अपने मालिक की बातों को ध्यान से सुनो और उनका अक्षरश: पालन करो. बाबा को पता था कि केवल किसी पर विश्वास रखना ही काफी नहीं है. विश्वास की डूबती-उतराती नाव का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए बाबा ने इस पर सबूरी का लंगर डाल दिया था. किसी पर विश्वास करना है और इस हद तक करना है कि कोई उस विश्वास को डिगा न सके, चाहे कितने ही साल और जन्म लगें. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दु:ख दूर होता है और होगा, लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए एक सहारा चाहिए और वह सहारा है श्रद्धा और सबूरी का.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वह धर्म ही क्या, जो छूने या खाने-पीने से भ्रष्ट हो जाए.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

आईटीओ क्षेत्र के विष्णु दिगंबर मार्ग पर एक पेड़ के नीचे लक्ष्मण राव ने चाय-पान की छोटी सी दुकान लगा ली. उनकी यह दुकान दिल्ली नगर निगम एवं पुलिस द्वारा कई बार उजाड़ी गई.

प्रचारप्रियता की विचारधारा

अनंत विजय

चंडीगढ़ में एक सेमिनार में हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारुख के साथ धक्कामुक्की की गई और उन्हें भाषण देने से रोकने की कोशिश की गई. हंगामा करने वालों का आरोप था कि वह एक भारत विरोधी सेमिनार में हिस्सा लेने आए थे और भारत विरोधी बातें कह रहे थे. इस मानसिकता के पीछे के कारणों को जानने की ज़रूरत है. लंबे समय से शहर दर शहर घूम-घूमकर भारत विरोधी सेमिनार किए जा रहे हैं. इन सेमिनारों में एक किताब लिखकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल कर लेने वाली लेखिका अरुंधति राय, जिन्हें वन बुक वंडर कह सकते हैं, प्रमुखता से शामिल हो रही हैं. पिछले दिनों अरुंधति ने देश की राजधानी में एक सेमिनार में कह डाला कि कश्मीर को भूखे-नंगे भारत से आज़ादी चाहिए. सैय्यद अली शाह गिलानी और कई अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं की मौजूदगी से उत्साहित अरुंधति और आगे चली गईं तथा उन्होंने भारत को खोखला सुपर पॉवर तक बता डाला. दरअसल यह बयान भी एक सोची-समझी रणनीति के तहत दिया गया है, ताकि प्रचुर प्रचार हासिल हो सके. कश्मीर पर अरुंधति के इस बयान को कुछ लोग देशद्रोह कह रहे हैं तो कुछ इसे भारतीय लोकतंत्र की ताक़त और अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं. अरुंधति के बयान को अभिव्यक्ति की आज़ादी क़रार देने वाले यह भूल जाते हैं कि हमारा संविधान बोलने और लिखने की आज़ादी तो देता है, लेकिन यह बेलगाम होने की इजाज़त नहीं देता. अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर अराजकता में बदलती है तो उस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता में कई प्रावधान हैं. लेकिन यहां सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का नहीं है. दिल्ली में हुए सेमिनार में कुछ खास लोगों की उपस्थिति से जो संकेत मिलते हैं, वे बेहद ख़तरनाक हो सकते हैं.

उक्त सेमिनार में कश्मीरी अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त नेता सैयद अली शाह गिलानी के साथ माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले लोगों के अलावा माओवादियों के फ्रंटल संगठनों, जैसे रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता भी मौजूद थे. इस मौजूदगी से क्या किसी गठबंधन की तस्वीर नज़र आती है. एक साथ एक मंच पर जिस तरह से माओवादी नेता, कश्मीरी अलगाववादी नेता और माओवादियों से सहानूभूति रखने वाले नज़र आए, वह महज़ इत्तेफाक नहीं हो सकता. इसके पीछे अवश्य कुछ न कुछ पक रहा है. सवाल यह खड़ा हो सकता है कि क्या इस सेमिनार के पीछे कश्मीरी अलगाववादियों और माओवादियों के बीच किसी तरह के तालमेल की मंशा थी. क्या माओवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों के बीच कुछ नया पक रहा है. यह सर्वविदित तथ्य है कि माओवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों दोनों की राज्य सत्ता में आस्था नहीं है और दोनों ही भारत को अस्थिर करने में जुटे हैं. माओवादियों ने हमेशा से कश्मीर में आज़ादी का समर्थन किया है. दो हज़ार आठ में माओवादियों के प्रवक्ता आज़ाद ने एक बयान जारी करके कहा था, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी कश्मीरी अवाम की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करती है. केंद्रीय कमेटी यह मानती है कि जो लोग कश्मीरी जनता की आज़ादी का समर्थन नहीं करते हैं, वे लोकतांत्रिक नहीं हैं. आज़ाद ने आगे जाकर अपने बयान में जो कहा था, वह और भी ख़तरनाक था. सेंट्रल कमेटी ने माओस्टि गुरिल्ला आर्मी के अलावा अपने सदस्यों से भी कश्मीरी अलगाववादियों की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने को कहा था. दो हज़ार आठ के आज़ाद के उक्त बयान के परिप्रेक्ष्य में इस सेमिनार में उपस्थित लोगों की मौजूदगी को जोड़कर देख सकते हैं. अब भारत सरकार और उसकी ख़ुफ़िया एजेंसियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इन संकेतों को पकड़ें और अगर कोई नापाक गठबंधन कोई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है तो उस पर फ़ौरन काबू पाने की रणनीति तैयार करें.

जहां तक अरुंधति के बयान की बात है तो उसे गंभीरता से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अरुंधति हमेशा से माहौल और मिजाज़ देखकर बयान देकर मजमा लूटती रही हैं, चाहे बयान में तथ्य हों या नहीं. दिल्ली में एक सेमिनार में दिए गए अपने वक्तव्य के बाद अरुंधति ने यह कह डाला कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है. यहां भी अरुंधति ने इस तथ्य की अनदेखी की कि कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के विलय के काग़ज़ातों पर दस्तखत किए थे. दरअसल अरुंधति की न तो भारत में, न इसके संविधान में, न इसके सिस्टम में और न ही लोकतंत्र में आस्था रही है. वह हमेशा से भारतीय लोकतंत्र को कठघरे में रखती आई हैं. भारतीय न्याय व्यवस्था में उन्हें यक़ीन नहीं है. लोगों की हत्या कर राज्य सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के माओवादियों के मंसूबों को वह हमेशा समर्थन देती रही हैं. इतना ही नहीं, वह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मखौल उड़ाकर पश्चिमी देशों की आंख का तारा बनती रही हैं.

एक बार न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाउन हॉल में एक गोष्ठी में अरुंधति ने भारत के लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हुए यह कह डाला कि भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, दरअसल वैसा वहां है नहीं. सही मायने में भारत में कोई लोकतंत्र है ही नहीं, वहां कई ऐसे राज्य हैं, जो सिविल वॉर के मुहाने पर खड़े हैं...इराक में तो डेढ़ लाख फौजी तैनात हैं, जबकि कश्मीर में सात लाख फौजी तैनात हैं. ज़ाहिर सी बात थी, इराक पर हमले के लिए विश्व के कई देशों की आलोचना झेल रहे अमेरिका के लोगों को यह बात बेहद पसंद आई और उन्होंने अरुंधति की इस तकरीर पर जमकर तालियां बजाईं. लेकिन अरुंधति के इस भाषण पर तालियां पीटने वाले अमेरिकियों को कौन समझाए कि यह भारतीय लोकतंत्र की मज़बूती और परिपक्वता का ही प्रमाण है कि यहां का कोई नागरिक विदेश में जाकर अपने ही देश की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है, मखौल तक उड़ा सकता है. अगर भारत में अरुंधति के सपनों का लोकतंत्र होता तो उन्हें अमेरिका में दिए गए इस भाषण के बाद देश लौटते ही गिरफ़्तार कर लिया जाता.

दरअसल इस देश में बौद्धिकता का जामा पहने कुछ अंग्रेजी दां लोगों के बीच यह फैशन प्रचलन में है कि देश को, यहां के सिस्टम को, यहां के संविधान को गाली दो और ख़ुद को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न केवल स्थापित करो, बल्कि उसका लाभ भी उठाओ. अरुंधति इस प्रवृत्ति का नायाब नमूना हैं. उन्हें जहां भी मौक़ा मिलता है, वह सबसे पहला हमला भारतीय लोकतंत्र पर करती हैं. उसके बाद भारतीय सिस्टम को निशाने पर लेती हैं. मुंबई हमले के बाद जिस तरह अरुंधति ने कहा कि नवंबर और सितंबर में फ़र्क़ है, दो हज़ार एक और दो हज़ार आठ में फ़र्क़ है. भारत और अमेरिका में फ़र्क़ है. फिर जिस तरह लंदन के गार्डियन अख़बार में उन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका को नकारने या फिर कमतर करके आंकने की कोशिश की, उसका निहितार्थ एक ही है, वह है भारतीय सिस्टम पर सवाल. ठीक इसी तरह वह भारतीय न्याय पालिका को भी कठघरे में खड़ा करती हैं. संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी की सजा को अरुंधति देश की जनभावना को संतुष्ट करने वाला बताकर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं. ज़ाहिर है, इस तरह की बातों से देश-विदेश में भरपूर प्रचार हासिल होता है. अरुंधति की प्रचारप्रियता का एक और उदाहरण नर्मदा बचाओ आंदोलन है. जब यह आंदोलन अपने चरम पर था तो मेधा पाटेकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने ख़ूब वाहवाही लूटी और एक वक़्त तो ऐसा आया कि मेधा पाटेकर ही नेपथ्य में चली गईं.

दरअसल अगर हम समग्रता में अरुंधति के समय-समय पर दिए गए बयानों को देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस वन बुक वंडर के अपने कुछ नियत और फॉर्मूलाबद्ध जुमले हैं, जिनकी बिना पर वह प्रचार हासिल करती रही हैं. ज़रूरत इस बात की है कि अरुंधति के बयानों को गंभीरता से न लिया जाए. अगर अरुंधति जैसे लोगों को प्रचार मिलना बंद हो जाए तो उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही दुकान बंद हो जाएगी और दुकान बंद होते ही बंद हो जाएगी ऊलजुलूल बयानबाज़ी. अगर इन प्रचार प्रिय लोगों की सक्रियता कम होगी तो मीरवाइज पर जिस तरह कुछ सिरफिरों ने हमला किया, वह भी रुकने की संभावना बढ़ सकती है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

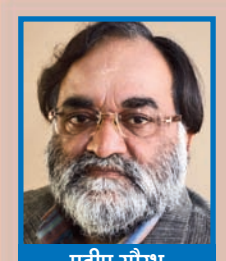

प्रदीप सौरभ

रेखा चिटणीस भी आनंद भारती की बात को बढ़ाते हुए कहती हैं, असल में कार्बन उत्सर्जन के नाम पर कुछ देश ग़रीब देशों को उससे रोकने के नाम पर टेक्नोलॉजी बेचकर अपनी जेब भरना चाहते हैं. अभी तक मौसम विज्ञान कोई भी सही भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं आया है. यदि ऐसा होता तो सुनामी की सूचना पहले से होती और उसमें हज़ारों लोगों को बचाया जा सकता था.

क्रिस सिअर शायद इतने सवाल झेलने के मूड में नहीं थे या फिर उनकी तैयारी नहीं थी. वह बगलें झांकने लगे. उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे. वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इंग्लैंड का जो प्रोजेक्ट था, उसमें दूसरे तर्कों की जगह नहीं थी. इंग्लैंड आने से पहले आनंद भारती दिल्ली में इंग्लैंड के युवा एनवायरमेंट मंत्री डेविड मिलीबैंड से वन टू वन मिल चुके थे. तब भी चर्चा का विषय ग्लोबल वार्मिंग ही था. मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग ही बताई थी. इस पर आनंद भारती ने उनसे साफ-साफ कहा था, हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या भूख है, साफ पानी है, अकाल और सूखा है. इससे हम बचेंगे, तभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे सवाल हमारे एजेंडे में आएंगे. उन्होंने यह कहते हुए उनसे यह भी पूछा था, इंग्लैंड इन मसलों पर हमारी क्या मदद कर सकता है?

इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था. वास्तव में वह शासक के लहज़े में ही बोल रहे थे. वह शायद यह भूल चुके थे कि इंडिया अब एक आज़ाद देश है. उन्हें आनंद भारती का सवाल-जवाब करना अच्छा नहीं लगा था. वह आगे के कार्यक्रम में शामिल होने का बहाना बना बात बीच में छोड़कर उठ गए. असल में मंत्री से लेकर संतरी तक इंग्लैंड में

ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रटे-रटाए सवाल-जवाब रखते हैं. दूसरे तर्कों के लिए उनके पास स्थान नहीं है या फिर वे इसके लिए तैयार नहीं हैं. क्रिस सिअर के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखा. एक साथ इतने सवालों ने उनके ग्लोबल वार्मिंग की हवा निकाल दी थी. बाद में हस्तक्षेप करते हुए तीसा केलगर ने मज़ाक के लहज़े में कहा, बहुत वार्मिंग हो गई, आइए पेट की वार्मिंग भी कर लेते हैं. उनका इशारा लंच की ओर था. बातचीत ख़त्म हो गई थी. सभी लंच के लिए उठ गए. आज की सरकारी यात्रा ख़त्म हो चुकी थी. लंच पर सभी होटल पहुंच चुके थे. जोशी की आज छुट्टी नहीं थी. आनंद भारती ने इंद्राणी मजूमदार से पूछा, लंदन भ्रमण का इरादा रखती हैं?

ज़रूर! वह बोलीं, कहां चलेंगे?

लंदन साइट सीन वाली बस का टिकट कटा लेते हैं, आनंद भारती ने जवाब दिया. वह लंदन को अपनी तरह से समझना चाहते थे.

होटल के रिसेप्शन से बस के बारे में जानकारी लेकर आनंद भारती और इंद्राणी मजूमदार बाहर निकले. बकिंघम पैलेस के सामने से बस मिलनी थी. हर पंद्रह-बीस मिनट पर बस आती रहती है. पैलेस के बाहर के फाउंटेन को अभी दोनों ने निहारना शुरू ही किया था कि सामने से लाल रंग की बस आती दिखी. बस की छत नहीं थी. डबल डेकर थी. दोनों ने ऊपरी हिस्से में बैठने का फ़ैसला किया. छह घंटे के लिए सात पाउंड का टिकट था. भारतीय मुद्रा में क़रीब लगभग पांच सौ साठ रुपये. हर सीट के साथ इयर फोन लगे थे. रिकॉर्डेड कमेंट्री उसमें सुनाई पड़ती थी. कमेंट्री सात भाषाओं में थी. दोनों ने इयर फोन लगाकर अंग्रेजी कमेंट्री सेट कर ली थी. बस में इंग्लैंड के दूसरे हिस्से से आए और अन्य दूसरे देशों के लोग सवार थे. दिलचस्प यह था कि अंग्रेजों के देश में बस में बैठे लोग अंग्रेजी छोड़कर अन्य सभी भाषाओं में बात कर रहे थे. यह इस बात का प्रमाण था कि इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलने वाले धीरे-धीरे कम हो रहे थे. इसीलिए इंग्लैंड इस बात पर भी सोच रहा है कि लंबे समय का वीजा देते वक़्त वह इस बात का भी ध्यान रखेगा कि वीजा पाने वाले को अच्छी-खासी अंग्रेजी आती हो.

अगले अंक में जारी

लक्ष्मण राव चाय वाला लेखक

लिखने, पढ़ने और देश-समाज के बारे में चिंतन-मनन करने के लिए वातानुकूलित घर-कमरा होना ज़रूरी नहीं है. कमोबेश यही साबित किया है दिल्ली के एक फुटपाथ पर चाय बेचने वाले लक्ष्मण राव ने, जो अब तक डेढ़ दर्जन से ज़्यादा कृतियों की रचना कर चुके हैं. मराठीभाषी लक्ष्मण राव का जन्म 22 जुलाई, 1954 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के एक छोटे से गांव तड़ेगांव दशासर में हुआ था. उन्होंने पहले मराठी भाषा में माध्यमिक एवं दिल्ली के तिमारपुर पत्राचार विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद लक्ष्मण राव ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की.

साहित्य के प्रति लक्ष्मण राव का रुझान शुरू से ही था. मराठीभाषी होते हुए भी उन्हें हिंदी भाषा के प्रति विशेष लगाव रहा. उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखने वाले गुलशन नंदा को अपना आदर्श माना. लेखक बनने की प्रेरणा कहां से मिली? यह पूछने पर वह बताते हैं कि एक बार उनके गांव का रामदास नामक एक युवक अपने मामा के घर गया. जब वह लौटने लगा तो रास्ते में एक नदी पड़ी. शीशे की तरह चमकते हुए पानी में अचानक उसने छलांग लगा दी. बाद में गांव वालों ने उसकी लाश नदी से बाहर निकाली. रामदास की मौत ही उनके लिए लेखक बनने की प्रेरणा बन गई. उन्होंने उस घटना पर आधारित एक उपन्यास रच डाला और लेखन का माध्यम बनाया हिंदी को.

इसके बाद लेखन और अध्ययन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक निरंतर जारी है. लक्ष्मण राव ने इलाहाबाद से प्रकाशित चतुर्वेदी एवं प्रसाद शर्मा और व्याकरण वेदांताचार्य पंडित तारिणीश झा के संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ ग्रंथ का अध्ययन किया. यह हिंदी-संस्कृत शब्दकोष था. लक्ष्मण राव उस समय मात्र बीस वर्ष के थे. जब हिंदी भाषा पर उन्हें अपनी पकड़ दिखने लगी, तब उन्होंने पत्राचार माध्यम से मुंबई हिंदी विश्वविद्यापीठ से हिंदी की परीक्षाएं दीं. यह बात 1973 की है. वर्ष 1977 में दिल्ली जैसे महानगर में आईटीओ क्षेत्र के विष्णु दिगंबर मार्ग पर एक पेड़ के नीचे लक्ष्मण राव ने चाय-पान की छोटी सी दुकान लगा ली. उनकी यह दुकान दिल्ली नगर निगम एवं पुलिस द्वारा कई बार उजाड़ी गई, लेकिन परिवार के पालन की ज़िम्मेदारी निभाने और लेखक बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए वह सब कुछ सहते-संघर्ष करते रहे.

लक्ष्मण राव बताते हैं कि वह दरियागंज के रविवारीय पुस्तक बाज़ार में जाकर अध्ययन हेतु किताबें ख़रीद लाते थे. उन्होंने इस दौरान शेक्सपियर, यूनानी नाटककार सोफोक्लीज,

मुंशी प्रेमचंद एवं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विभिन्न पुस्तकों का जमकर अध्ययन किया. लक्ष्मण राव का पहला उपन्यास-नई दुनिया की नई कहानी वर्ष 1979 में प्रकाशित हुआ. इसके बाद तो वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए. चाय और पान बेचने वाला कोई शख्स लेखक भी हो सकता है, इस पर किसी को सहज विश्वास नहीं हो पा रहा था. इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार के संडे रिव्यू में उन पर एक आलेख प्रकाशित हुआ. यह बात फरवरी, 1981 की है. फिर अख़बारों, रेडियो और दूरदर्शन पर उनके बारे में अक्सर कुछ न कुछ प्रकाशित-प्रसारित होने लगा. 27 मई, 1984 को तीन मूर्ति भवन में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का अवसर मिला. उन्होंने श्रीमती गांधी से उनके जीवन पर पुस्तक लिखने की इच्छा व्यक्त की. इस पर इंदिरा जी ने उन्हें अपने प्रधानमंत्रित्व काल के संबंध में पुस्तक लिखने का सुझाव दिया. तब लक्ष्मण राव ने प्रधानमंत्री नामक एक नाटक लिखा. 1982 में उनका उपन्यास रामदास प्रकाशित हो चुका था. 2001 में नर्मदा (उपन्यास) और 2006 में परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ. छठी रचना रेणु 2008 में प्रकाशित हुई. लक्ष्मण राव कहते हैं, यदि मुझे पहले से पता होता कि लेखक बनना आसान नहीं है तो मैं कभी ऐसा प्रयास नहीं करता. अपनी पहली रचना प्रकाशित कराने के लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा. रचना प्रकाशित होने के बाद सुबह साइकिल लेकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकलता तो लोग मेरा मज़ाक तक उड़ाते, लेकिन ईश्वर की कृपा और चालीस वर्षों के परिश्रम ने मुझे बतौर लेखक पहचान दिला दी. लक्ष्मण राव को अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है और अंग्रेजी समाचारपत्र एवं पुस्तकें वह बहुत चाव से पढ़ते हैं.

प्रमुख रचनाएं

नई दुनिया की नई कहानी, प्रधानमंत्री, रामदास, नर्मदा, परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति, रेणु, पत्तियों की सरसराहट, सर्पदंश, साहिल, प्रातःकाल, प्रशासन, राष्ट्रपति (नाटक), संयम, साहित्य व्यासपीठ, दृष्टिकोण, समकालीन संविधान, अहंकार, अभिव्यक्ति, मौलिक पत्रकारिता.

पुरस्कार-सम्मान

भारतीय अनुवाद परिषद, कोच लीडरशिप सेंटर, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, निष्काम सेवा सोसायटी, अग्निपथ, अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच, शिव रजनी कला कुंज, प्रागैतिक सहजीवन संस्थान, यशपाल जैन स्मृति, चिल्ड्रेन वैली स्कूल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद.

त्रिलोक कुमार झा
feedback@chauthiduniya.com

युवाओं की इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए कॉटनवर्ल्ड ब्रांड ने टी-शर्ट्स की एक खास रेंज बाज़ार में उतारी है.

नेटवर्किंग का नया तरीका

टाटा कम्युनिकेशंस ने लोकल एरिया नेटवर्क में तकनीक का एक नया आयाम पेश किया है. कंपनी ने नेक्स्ट जेनरेशन एथरनेट नेटवर्क को विश्व के 24 नोड में उपलब्ध कराते हुए लांच किया है. ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में 802.1 एएच प्रोवाइडर बैकबोन ब्रिजिंग के इस्तेमाल में टाटा ने वैश्विक स्तर पर बाजी मार ली है. नए एथरनेट नेटवर्क कोर में नेटिव एथरनेट ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट के साथ अन्य विशेष सेवाएं दी गई हैं. इस नेक्स्ट जेनरेशन एथरनेट कोर से कस्टमर्स अपने नेटवर्क के जरिए विशेष रूट जैसे डायवर्सिटी, लैटेंसी और कॉस्ट रीजनंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. यह विकल्प अब तक किसी अन्य नेटवर्किंग तकनीक पर उपलब्ध नहीं है. टाटा कम्युनिकेशंस कोर लेयर के एथरनेट नोडल डायवर्सिटी में कट स्ट्रॉफी फेल होने पर प्रोटेक्टेड ट्रैफिक को खुद ही अलग एड्रेस पर दूसरे नोड में डाल देता है. इससे नुकसान की आशंका कम हो जाती है. पीबीबी यानी प्रोवाइडर बैकबोन ब्रिजिंग मल्टी प्वाइंट बेस्ड तकनीक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस के जरिए मल्टी प्वाइंट सर्विसेज को बेहतर क्षमता और सुरक्षा प्रदान करती है. टाटा कम्युनिकेशंस नेटवर्क की एथरनेट सर्विस में बी मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है, जबकि अन्य नेटवर्किंग तकनीक में फ्रेम फार्वर्डिंग के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है. इससे ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस में अटैक की आशंका कम हो जाती है.

टाटा कम्युनिकेशंस के डब्ल्यूएएन एथरनेट पोर्टफोलियो में ग्राहकों को उपयुक्त समाधान और अपनी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क का साइज चुनने का विकल्प उपलब्ध है. टाटा कम्युनिकेशंस की ग्लोबल एथरनेट सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की 50 लोकेशंस के अलावा चीन के चार शहरों में उपलब्ध है. कंपनी आने वाले कुछ महीनों में इस सर्विस को अफ्रीका, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की कुछ और जगहों पर सक्रिय करने पर विचार कर रही है. भारत में यह सर्विस 120 शहरों में उपलब्ध होगी.

ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में 802.1 एएच प्रोवाइडर बैकबोन ब्रिजिंग के इस्तेमाल में टाटा ने वैश्विक स्तर पर बाज़ी मार ली है. नए एथरनेट नेटवर्क कोर में नेटिव एथरनेट ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट के साथ अन्य विशेष सेवाएं दी गई हैं.

मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रिमूवेबल डाटा

भारत में मौजूद इमेशन एवं उसके चैनल पार्टनर्स के किसी भी रिटेल आउटलेट से 320, 500 या 640 जीबी इमेशन अपोलो पॉकेट हार्डड्राइव लेने पर ग्राहक विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

विश्व में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रिमूवेबल डाटा स्टोरेज प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इमेशन ने अपने ग्राहकों को खुश करने का मन बनाया है. इमेशन के चैनल पार्टनर्स मेमोरेक्स, टीडीके एलओआर, एक्सट्रीम मैक, आईबीएम, सन एवं एचपी हैं. अपने पार्टनर्स का आधार विस्तृत करने के लिए कंपनी ने भारतीय बाजार को चुना है. इसी वजह से वह भारतीय ग्राहकों को रिझाने के लिए साल के अंत में नए ऑफर लाई है. उसने 31 दिसंबर तक इमेशन के अपोलो हार्डडिस्क खरीदने पर बेहतरीन रालेज जैसे बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन और आईपॉड का ऑफर दिया है. भारत में मौजूद इमेशन एवं उसके चैनल पार्टनर्स के किसी भी रिटेल आउटलेट से 320, 500 या 640 जीबी इमेशन अपोलो पॉकेट हार्डड्राइव लेने पर ग्राहक विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए क्रेता को हार्डड्राइव का सीरियल नंबर 56677 पर एसएमएस करना होगा. ड्रा द्वारा विजयी ग्राहकों के नामों की घोषणा की जाएगी. स्लिम और स्लीक अपोलो हार्डड्राइव केवल आधा पाउंड वजन का है, जो आसानी से आपकी जेब में आ जाएगा. इसमें किसी और बैट्री पावर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह यूएसबी 2.0 पावर से लैस है. फोटो, म्यूजिक एवं वीडियो के साथ यह हार्डड्राइव 320, 500 और 640 जीबी में उपलब्ध है. अपोलो पॉकेट हार्डड्राइव सभी प्रकार की डिजिटल फाइलों के बैकअप के संरक्षण वाले फीचर्स से युक्त है. पीसी और मैक सिस्टम के लिए बनाए गए इस हार्डड्राइव में बैकअप, संकलन और प्रत्यावर्तन जैसी खूबियां हैं. इसमें क्रोम डिटेलिंग के साथ मिड नाइट ब्लैक ब्रस्ड सर्फेस भी है. टोटल मीडिया बैकअप के स्पेशल फीचर के साथ इस सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल और इस्तेमाल किया जा सकता है.

परिधानों से मानवता का संदेश

बीइंग ह्यूमन नामक यह संस्था सुपर स्टार सलमान खान की है, जिसके ज़रिए वह ग़रीबों एवं असहाय लोगों की मदद करते हैं.

मौसम कोई भी हो, युवाओं का पसंदीदा परिधान वही होता है, जिसमें वे कंफर्टेबल महसूस करते हैं. ज्यादातर युवा, चाहे वे लड़कियां हों या लड़के, टी-शर्ट एवं जींस पहनना पसंद करते हैं. युवाओं की इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए कॉटनवर्ल्ड ब्रांड ने टी-शर्ट्स की एक खास रेंज बाजार में उतारी है. बीइंग ह्यूमन सीरीज की उक्त टी-शर्ट्स दरअसल कुछ मानवीय कारणों से लोगों के बीच उपलब्ध कराई गई हैं. सामाजिक कार्यों से जुड़ी बीइंग ह्यूमन नामक संस्था के साथ मिलकर कॉटनवर्ल्ड ने युवाओं में कुछ नैतिक गुणों का समावेश करने की कोशिश में यह रेंज बाजार में उतारी. यह संस्था सुपर स्टार सलमान खान की है, जिसके जरिए वह गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद करते हैं. बीइंग ह्यूमन रेंज की टी-शर्ट्स की बिक्री से आया सारा पैसा इस संस्था को मिलेगा, जो गरीबों के इलाज में खर्च किया जाएगा. बीइंग ह्यूमन टी-शर्ट्स कॉटनवर्ल्ड के सभी स्टोरों पर आसानी से उपलब्ध हैं. महिलाओं की टी-शर्ट 435 रुपये और पुरुषों की टी-शर्ट 495 रुपये की है. कॉटनवर्ल्ड के पार्टनर लविन लेखराज कहते हैं कि बीइंग ह्यूमन के साथ जुड़कर कंपनी गर्व महसूस करती है. सभी कॉरपोरेट हाउसेस की समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें पूरा होना चाहिए. इसलिए कंपनी बीइंग ह्यूमन के साथ मिलकर गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गेम का मज़ा होगा दोगुना

इंटरनेट गेम्स को और भी मनोरंजक बनाने के लिए कार्टून नेटवर्क ने कुछ नए गेम्स लांच किए हैं. ऑनलाइन गेम्स लवर्स के लिए अब सिर्फ पुराने नहीं, बल्कि नए एक्साइटिंग गेम्स आ गए हैं. बच्चों के लिए बेन टेन मल्टीप्लेयर ऑनलान गेम्स लांच किया गया है. इसमें बेन टेन ओमनीवर्स: राले ऑफ द हीरोज और टून फुटबॉल हैं. बेन टेन ओमनीवर्स: राले ऑफ द हीरोज बेन टेन की दुनिया में एडवेंचर की कहानियों पर आधारित गेम है और टून फुटबॉल सॉकर सीजन में आए फुटबॉल गेम का अपडेटेड वर्जन है. इन एडवेंचर आधारित गेम्स को ज्यादा संवादात्मक बनाने, प्रभाव डालने के लिए कार्टून नेटवर्क ने टून करेंसी डिजाइन की है. बच्चों के लिए लाए गए कार्टून नेटवर्क के सिक्के देश भर के गेमिंग कैफे में उपलब्ध होंगे. इन्हें ऑनलाइन या जैपेक कैफे नेटवर्क और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. बेन टेन ओमनीवर्स: राले ऑफ द हीरोज ग्रुप में एडवेंचर गेम हैं. बेन टेन की ओरिजनल सीरीज के जैसे इन गेम्स में भी गेमर्स और बेन टेन के फैन आकाश गंगा के बीच फंस जाते हैं. प्लेयर्स को एलियन आर्मी से लड़ाई लड़कर अपने ओमनीवर्स को बचाना होता है. टून फुटबॉल के नए वर्जन में गेमर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए नए फीचर्स डाले गए हैं. रीयल प्लेयर्स के साथ इसमें कंप्यूटर के कैरेक्टर भी टीम बना सकेंगे. इसके साथ ही टून हीरो बेन टेन भी गेमर की टीम में शामिल हो पाएगा, जिसके पास सुपर किक का खास पावर होता है. इससे गेम का मजा दोगुना हो जाएगा. ये गेम्स और इनके सिक्के देश के 35 शहरों के 100 जैपेक कैफे और 500 निजी गेमिंग कैफे में आसानी से उपलब्ध हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

टी-20 क्रिकेट के इस दौर में टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता पहले ही लगातार कम होती जा रही है. टेस्ट मैचों को देखने के लिए दर्शक नहीं आते, क्योंकि उन्हें रोमांच देखना अच्छा लगता है.

ख़तरे में टेस्ट क्रिकेट का भविष्य

तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ही ली. इसके साथ ही 2008 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद से टेस्ट सीरीजों में टीम का अपराजेय रिकॉर्ड भी बरक़रार रहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए नाको चने चबवा दिए. सीरीज शुरू होने से पहले तक तमाम लोग कीवी टीम की 3-0 से हार की भविष्यवाणियां कर रहे थे. इसका पहला कारण तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दोनों टीमों के बीच का फासला है. ग़ौरतलब है कि टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया जहां टॉप पर है, वहीं न्यूजीलैंड आठवें नंबर पर है. इसका दूसरा और तात्कालिक कारण यह था कि भारत आने से ठीक पहले यही टीम बांग्लादेश गई थी, जहां उसे वनडे सीरीज में 4-0 की शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी थी, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ अपने प्रदर्शन से कीवी टीम ने तमाम भविष्यवाणियों को ग़लत साबित कर दिया. डेनियल विटोरी की कप्तानी में इस युवा टीम ने जो जुझारूपन और संघर्ष का माद्दा दिखाया, वह वास्तव में काबिलेतारीफ़ है. दूसरी ओर टीम इंडिया अपनी प्रतिष्ठा के मुताबिक़ प्रदर्शन करने में असफल रही. विश्व की नंबर एक टीम की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी में वह पैनापन नहीं दिखा, जिसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश टेस्ट मैचों के लिए बनाई गई पिचों ने किया. अहमदाबाद और हैदराबाद की बेजान पिचों पर किसी भी गेंदबाज के लिए कोई मदद नहीं थी. नागपुर में हालांकि मैच के चौथे दिन ही मुक़ाबले का नतीजा निकल गया, लेकिन इस पिच में भी गेंदबाजों के लिए कुछ खास मदद मौजूद नहीं थी. इसका खामियाजा टीम इंडिया को तो भुगतना ही पड़ा, टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिहाज़ से भी यह अच्छा संकेत नहीं है.

भारत में पिचें परंपरागत रूप से तेज गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मददगार नहीं होतीं. यहां की जलवायु और मिट्टी ही कुछ ऐसी है कि मुक़ाबले के पहले दिन पहले घंटे में तेज गेंदबाजों को थोड़ी-बहुत स्विंग मिलती है और फिर अगले दो दिनों तक पिच बल्लेबाज़ी के लिए आदर्श बनी रहती है. तीसरे-चौथे दिन से पिच का मिजाज़ बदलने लगता है और स्पिन गेंदबाजों को टर्न और बाउंस मिलने लगता है. विदेशी टीमों को भारतीय पिचों के इसी मिजाज़ से परेशानी होती है, जबकि टीम इंडिया का स्पिन आधारित गेंदबाज़ी आक्रमण इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज में बनाई गई पिचों पर किसी भी तरह की गेंदबाज़ी के लिए कोई मदद मौजूद नहीं थी. नागपुर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीतने में कामयाब हुई तो इसकी सबसे बड़ी वजह कीवी बल्लेबाजों का ग़ैर ज़िम्मेदार रवैया था. भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने सीरीज के बीच में ही इसकी शिक़ायत भी की. हैदराबाद की पिच को हरभजन ने नेशनल हाईवे जैसा सपाट घोषित कर दिया तो धोनी ने यहां तक कह डाला कि ऐसी पिचों पर लगातार दस दिनों तक भी मुक़ाबले चलते रहें तो उनका कोई नतीजा नहीं निकल सकता.

टी-20 क्रिकेट के इस दौर में टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता पहले ही लगातार कम होती जा रही है. टेस्ट मैचों को देखने के लिए दर्शक नहीं आते, क्योंकि उन्हें रोमांच देखना अच्छा लगता है. बल्लेबाज चौके-छक्के लगाते रहें और गेंदबाजों को विकेट मिलता रहे, मतलब यह कि गेंद और बल्ले के बीच बराबर का संघर्ष हो तो दर्शकों को भी मज़ा आता है. यही कारण है कि दर्शक टी-20 और वनडे मुक़ाबले देखने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें तय समय के अंदर मुक़ाबले का नतीजा मिलने की गारंटी होती है. टेस्ट मैच में पांच दिन के खेल के बाद भी यदि नतीजा न निकले तो दर्शक उसे देखने भला क्यों जाएंगे. दर्शक नीरस मुक़ाबलों की ओर आकर्षित नहीं होते. न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज के लिए बनी पिचें ऐसी ही थीं. इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पहले मैच के पांचवें दिन हरभजन सिंह, जिन्हें बल्लेबाज़ी से ज़्यादा गेंदबाज़ी के लिए जाना जाता है, ने शतक ठोंक डाला. उन्होंने अगले मैच में एक और शतक लगाया, जबकि पूरी सीरीज में उन्हें केवल 10 विकेट ही मिले. दूसरे टेस्ट में भी न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कुलम ने मुक़ाबले के पांचवें दिन दोहरा शतक लगाया.

सच्चाई यह है कि बेजान और सपाट पिचें टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए ख़तरे का संकेत हैं. क्रिकेट के तमाम नियम-कायदे वैसे ही बल्लेबाजों के अनुकूल होते जा रहे हैं. गेंदबाजों को एकमात्र पिच का ही सहारा होता है. यदि उन्हें पिच से भी कोई मदद न मिले तो उनके हुनर का कोई मतलब नहीं रह जाता. क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव करने की चर्चा हो रही है. ऐसा होना ज़रूरी भी है और इसके लिए आईसीसी को पहल करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि टेस्ट मैचों के लिए स्पोर्टिंग पिचें बनाई जाएं. इसके लिए आईसीसी के साथ-साथ सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को क़दम उठाने होंगे. वरना वह दिन दूर नहीं, जब क्रिकेट का सबसे वास्तविक और विशुद्ध स्वरूप माना जाने वाला टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

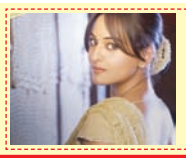

फिल्म किक को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियावाला ने. यह एक एक्शन फिल्म है. सोनाक्षी का करियर इन दिनों बुलंदियों पर है, उन्हें सभी निर्माता-निर्देशक अपनी फिल्मों में लेने को उत्सुक हैं.

आरती छाबड़िया की मशक़्क़त

बॉलीवुड में सुपर फ्लॉप होने के बाद म्यूज़िक वीडियो, मॉडलिंग एवं पब्लिक इवेंट में भी ज़्यादा लोकप्रियता न मिलने के बावजूद आरती छाबड़िया ने एक बार फिर फिल्मों में काम करने की कोशिश की है. अभी हाल में आई उनकी फिल्म दस तोला फिर से दर्शकों को लुभाने में असफल रही है. सशक्त अभिनेता मनोज वाजपेयी के साथ यह फिल्म करने से भी आरती को कोई फ़ायदा नहीं हुआ. हालांकि इस फिल्म में ग्रामीण महिला का किरदार निभाने और उसके अनुसार नज़र आने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत करके अपना वज़न बढ़ाया. इस फिल्म के प्रोमोशन में उन्होंने जी-जान लगा दिया, लेकिन वह दर्शकों को सिनेमाघरों की तरफ़ खींच पाने में सफल नहीं हुईं. हालांकि फिल्में करने की उनकी चाहत अभी ख़त्म नहीं हुई है और वह ख़ुद को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए कुछ और ग्लैमरस रोल की तलाश में हैं. वह कहती हैं कि ग्लैमरस रोल में ही उनकी विशिष्टता निखर कर स्क्रीन पर नज़र आएगी. आरती इससे पहले शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म मिलेंगे-मिलेंगे में भी नज़र आई थीं. इसके अलावा वह कुछ दक्षिण की फिल्में कर रही हैं. अभी हाल में उन्होंने एम्बे वैली फैशन वीक के दौरान रैंप पर उतर कर बॉलीवुड में अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराया था. ये सारी कोशिशें किसलिए आरती? बॉक्स ऑफिस पर तो सिर्फ़ दर्शकों की मर्जी चलती है और उन्होंने तो आपको बहुत पहले ही नकार दिया है.

अंजना बनी शरमन की हीरोइन

अभिनेत्री अंजना सुखानी अक्सर छोटे रोल में ही दिखती हैं, पर दर्शकों के बीच अपनी पहचान छोड़ जाती हैं. वह अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पर लगभग सभी में उनका रोल सह नायिका का था. अंजना ने हालिया रिलीज फिल्म अल्लाह के बंदे में अभिनेता शरमन जोशी के अपोजिट काम किया है. यह फिल्म अंडरवर्ल्ड में बच्चों की बढ़ती भागीदारी पर आधारित है. अंजना जयपुर के एक सिंधी परिवार में पैदा हुईं. उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए किया है. उनका फिल्मों में आना मात्र एक संयोग ही था. हुआ यह कि उनकी बहन मीना सुखानी ने उन्हें फिल्म बचना ए हसीनों में मिनिषा लांबा की दोस्त की भूमिका में लिया. इस तरह उन्हें पहली फिल्म मिली. उन्होंने कई जाने-माने ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की. कैडबरी मिल्क चॉकलेट के विज्ञापन में उन्होंने सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया. कई म्यूज़िक वीडियो भी किए. इसके बाद उनकी फिल्म आई सलामे इश्क, लेकिन फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में दर्शकों ने उनकी भूमिका को सराहा. इसमें उन्होंने अभिनेता तुषार कपूर के अपोजिट काम किया और एक बहरी लड़की की भूमिका अदा की. अंजना को असली पहचान मिली फिल्म संडे से, जिसमें उनके अभिनय ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया. इस फिल्म में उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनर का रोल किया था.

समाजसेवा में श्रिया की रुचि

एक्टिंग को सिर्फ़ अपना प्रोफेशन मानने वाली श्रिया शरण सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखती हैं. बच्चों से जुड़ी संस्थाओं के साथ-साथ वह निजी तौर पर भी ग़रीब बच्चों के बीच अनाथालय आदि में जाती रहती हैं. उनका मानना है कि इंसान सिर्फ़ पैसा कमाने में जीवन की मंजिल नहीं पा सकता, न ही उसे सिर्फ़ बहुत सारा पैसा कमाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए. हर व्यक्ति की एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है, जिसे सबको निभाना चाहिए. फिल्मों के लिए बेहतरीन रेटिंग्स पाने के बाद भी श्रिया को इस बात का मलाल नहीं है कि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई. श्रिया शरण बच्चों के अधिकारों, उनकी शिक्षा, मिड डे मिल, रोज़गार और साफ पानी के प्रति सजग नंदी फाउंडेशन की ब्रांड एंबेसडर हैं. इसके अलावा वह सेव ए चाइल्ड्स हार्ट फाउंडेशन, जो ग़रीब बच्चों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करता है, से भी जुड़ी हैं. इस संस्था से टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा भी जुड़ी हैं. वह एड्स से बचाव के लिए काम करने वाली एक संस्था को भी समय-समय पर आर्थिक मदद पहुंचाती रहती हैं. श्रिया समाज में शिक्षा की रोशनी फैलाना चाहती हैं, इसलिए वह ग़रीब स्कूली बच्चों के बीच पढ़ने-लिखने के लिए स्टेशनरी बांटती हैं और बाल मजदूरी को समाज से ख़त्म करने की कोशिश में चलाए जाने वाले अभियान में समय-समय पर भाग लेती रहती हैं. उन्होंने अंधे लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए एक स्पा खोलने की घोषणा की है. सिर्फ़ ग़रीबों और बच्चों के लिए ही नहीं, श्रिया शरण जानवरों के प्रति भी दया की भावना रखती हैं. वह जानवरों को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था ब्लू क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ी हैं.

सोनाक्षी का नया अवतार

अपनी पहली ही फिल्म में धमाल मचाने वाली अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया. उन्होंने लैक्मे फैशन वीक 2008 और 2009 में कैटवॉक किया. फिर उन्हें फिल्म दबंग का ऑफर मिला, जिसमें उनकी और सलमान की जोड़ी हिट रही. सोनाक्षी उम्र में सलमान से बहुत छोटी हैं, पर पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई. सलमान को भी सोनाक्षी का साथ इस कदर पसंद आया कि अब दोनों कई फिल्मों में साथ-साथ दिखेंगे. फिल्म किक और दबंग-2 में दोनों एक बार फिर साथ-साथ नज़र आने वाले हैं. फिल्म किक को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियावाला ने. यह एक एक्शन फिल्म है. सोनाक्षी का करियर इन दिनों बुलंदियों पर है, उन्हें सभी निर्माता-निर्देशक अपनी फिल्मों में लेने को उत्सुक हैं. हिट फिल्म रेस के सीक्वेल रेस-2 में वह सैफ अली ख़ान के साथ नज़र आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ सैफ के अलावा प्रियंका चोपड़ा एवं जॉन अब्राहम भी हैं. इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसमें सोनाक्षी स्टंट सीन करती नजर आएंगी. देखना यह है कि स्टंट करती सोनाक्षी को दर्शक कितना पसंद करते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विद्या का पैशन

विज्ञापन की दुनिया से फिल्मों में प्रवेश करने वाली विद्या बालन बॉलीवुड की स्थापित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री हासिल करने के बाद कई फिल्मों, वीडियो एवं विज्ञापनों में काम किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म थी परिणीता. इसमें वह संजय दत्त के अपोजिट थीं. इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला. फिर संजय दत्त के साथ उनकी दूसरी फिल्म आई, लगे रहो मुन्ना भाई. इसके बाद हे बेबी, भूलभुलैया जैसी कई फिल्में आईं. फिल्म पा में एक बार फिर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया. इस फिल्म में विद्या अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में थीं. विद्या ने अपना करियर बतौर अभिनेत्री शुरू किया. उन्होंने मलयालम और तमिल फिल्मों में काम किया, पर सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने टीवी विज्ञापनों की तरफ़ रुख़ किया, जहां उन्हें अपार सफलता मिली. उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया, पर उन पर अभिनेत्री बनने का क्रेज हावी रहा. इसी बीच बंगला फिल्मों के डायरेक्टर गौतम ने उनसे अपनी फिल्म भालो थेको में काम करने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत हां कर दी. इस फिल्म में उम्दा अभिनय के लिए उन्हें आनंद लोक पुरस्कार मिला, पर फिल्म परिणीता उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई. इसमें दर्शकों ने विद्या को काफी पसंद किया. इसके बाद विद्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

प्रीव्यू

बैंड बाजा बारात

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म बैंड बाजा बारात के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा और निर्देशक-लेखक हैं मनीष शर्मा. 10 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अनुष्का शर्मा एवं रणवीर सिंह. रणवीर ने जहां इस फिल्म से बतौर अभिनेता अपना करियर शुरू किया है, वहीं मनीष ने भी पहली निर्देशन की ज़िम्मेदारी संभाली है. यह एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी श्रुति कक्कड़ (अनुष्का शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है. श्रुति और बिट्टू शर्मा (रणवीर सिंह) की उम्र बीस साल के आसपास है. दोनों ने कुछ ही समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, श्रुति ने रामजस कॉलेज और बिट्टू ने हंसराज कॉलेज से. श्रुति मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है और अपने करियर को लेकर काफी गंभीर है. जबकि बिट्टू पैसे वाला है और उसे दोस्तों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद है. उसे करियर-भविष्य जैसी बातों से कोई मतलब नहीं है. दोनों साथ मिलकर शादी का बिजनेस शुरू करते हैं. इसके लिए वे दिल्ली के आसपास का इलाक़ा चुनते हैं. दोनों एक-दूसरे से बेहद अलग हैं, अलग-अलग परिवेश से हैं, इसलिए दोनों में अक्सर नोकझोंक होती रहती है, लेकिन अंत में दोनों में प्यार हो जाता है और वे ख़ुशी-ख़ुशी रहने लगते हैं. फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के बाद एक बार फिर अनुष्का यशराज फिल्म्स के बैनर तले काम कर रही हैं. इन दिनों शादी का मौसम चल रहा है और फिल्म की कहानी भी शादी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके गाने शादियों में काफी चल रहे हैं. फिल्म आगामी 10 दिसंबर को रिलीज होगी. काफी समय से यशराज फिल्म्स की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं. अपनी इस नई फिल्म से बैनर को काफी उम्मीदें हैं. देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर यह कितना कमाल कर पाती है.

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 06 दिसंबर–12 दिसंबर 2010 www.chauthiduniya.com

कोई सुरक्षित नहीं

विजय यादव

उत्तर प्रदेश में आम आदमी के साथ मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारी–कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं. आपराधिक घटनाओं के सरकारी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं. एक जनवरी, 2010 से 30 सितंबर, 2010 के दौरान नौ माह में प्रदेश में 3123 लोगों की हत्या कर दी गई. 1000 से अधिक महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं और 50 बच्चों को फिरौती के लिए अपहृत किया गया. क़रीब पौने दो हज़ार लोग लूट और डकैती का शिकार हुए. आंकड़ों की बात छोड़ भी दें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया करमवीर सिंह ख़ुद यह स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के 11 ज़िलों की क़ानून व्यवस्था चिंताजनक है. इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सांस्कृतिक राजधानी बनारस, औद्योगिक राजधानी कानपुर एवं गाजियाबाद और पर्यटन के केंद्र बिंदु आगरा एवं मथुरा का शामिल हैं. डीजीपी ने फिरोजाबाद, जौनपुर, बहराइच, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी की क़ानून व्यवस्था को भी चिंताजनक माना है. अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि वह किसी भी समय घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. राजधानी लखनऊ में अब सुबह की सैर लोगों की जान की दुश्मन बन गई है.

लखनऊ के विकास नगर इलाक़े में सीएमओ (परिवार कल्याण) डॉ. विनोद कुमार आर्य 27 अक्टूबर को सुबह की सैर पर ही निकले थे, तभी घर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया. डॉ. आर्य की हत्या से कुछ ही दिनों पहले लखनऊ के वजीरगंज इलाक़े में पूर्व एमएलसी मुशीर अहमद लारी पर भोर में ही जानलेवा हमला किया गया, उस समय वह अपने घर में पौधों को पानी दे रहे थे. बर्तन व्यापारी शिवराज कुमार अग्रवाल को गोली मारकर लूट की वारदात भी सुबह–सुबह अंजाम दी गई. स्वास्थ्य विभाग के बहुचर्चित डॉ. बच्ची लाल रावत हत्याकांड को भी बदमाशों ने सुबह ही अंजाम दिया था. अपराधी कितने बेख़ौफ हैं, यह मेरठ में कांग्रेस के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह की हत्या से स्पष्ट हो जाता है. कार में मामूली टक्कर से शुरू हुई कहासुनी के दौरान बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में पूर्व सांसद को गोलियों से भून डाला और आराम से चलते बने. बिगड़ती क़ानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश विधानसभा में भी उठ चुका है. विपक्ष के आरोपों के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री लालजी वर्मा ने राज्य की क़ानून व्यवस्था को बहुत बढ़िया करार दिया. उन्होंने यह तक कह डाला कि इस मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के मुक़ाबले बेहतर है.

उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश से बेहतर है. संसदीय कार्य मंत्री के इस दावे को उन्हीं की सरकार में पुलिस विभाग के मुखिया करमवीर सिंह झुठला चुके हैं. डीजीपी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश के 11 ज़िलों में क़ानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने अपराधों पर रोकथाम के सख्त निर्देश भी दिए, लेकिन अपराधों का बढ़ता ग्राफ बताता है कि डीजीपी के आदेशों का कोई असर नहीं है. हत्या, लूट, अपहरण की घटनाओं पर रोक न लगने का एक प्रमुख कारण पुरानी वारदातों का अनसुलझा रह जाना भी है. आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन वे सबूत और जोरदार पैरवी के अभाव में बरी हो गए. नतीजा अपराध जारी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉ. बच्ची लाल रावत हत्याकांड की अदालती पत्रावलियां कुछ ऐसी ही दास्तां बयां करती हैं. अदालत ने आरोपियों को बरी करते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस ने हत्या की मुख्य वजह वाली दिशा में कोई विवेचना ही नहीं की. पुलिस के अपने ही गवाह आरोपियों के बजाय पुलिस के ख़िलाफ़ गवाही में खड़े थे. यह एक बानगी है, जिसमें अदालत ने ऐसी सख्त टिप्पणी की. ऐसे दर्जनों मामले हैं, जिनमें पुलिस की तफ्तीश किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गई. 12 अप्रैल, 1998 को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रनेता धर्मेंद्र कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में दयाशंकर सिंह, बबलू उपाध्याय (मुठभेड़ में मारा गया), चंद्र प्रकाश सिंह (सड़क हादसे में मौत) और गुड्डू सिंह नामजद हुए थे. यह मामला छह दिनों में ही सीबीसीआईडी को स्थानांतरित हो गया था. बाद में दयाशंकर सिंह दोषमुक्त हो गए और गुड्डू पर आरोप तय नहीं हो सके.

ऐसी कई घटनाएं हैं, जिन पर से आज तक पर्दा हट नहीं सका है. सात मार्च, 1997 को हुए लामार्टीनियर कॉलेज का गोम्स हत्याकांड आज भी लखनऊ के लोग नहीं भूले हैं. इस मामले में धनंजय सिंह, राजा भार्गव नामजद हुए और तीन साल तक मुक़दमा चला. फिर तीन अगस्त, 2001 को सभी दोषमुक्त हो गए और फाइल बंद. अभियंता गोपाल शरण श्रीवास्तव की 19 जुलाई, 1997 को लखनऊ के इंदिरा नगर इलाक़े में हत्या की गई. घटना में राजीव सिंह उर्फ राजू पहाड़ी, धनंजय सिंह, रिंकू सिंह उर्फ अरविंद, अजय प्रताप सिंह उर्फ केडी नामजद हुए, जो बाद में दोषमुक्त साबित हुए. जेल अधीक्षक आर के तिवारी हत्याकांड का हाल भी ऐसा ही हुआ. चार फरवरी, 1999 को जेल अधीक्षक आर के तिवारी की हत्या की गई. इसमें अभय सिंह, मुख्तार अंसारी, शोएब उर्फ बॉबी, मनीष सिंह, अकबर हुसैन सज्जू, पवन उपाध्याय, संजीव उर्फ रामू द्विवेदी, बबलू और गुड्डू सिंह पर चार साल तक मुक़दमा चला. गवाहों के न मिलने पर आठ दिसंबर, 2003 को सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए और मुकदमा ख़त्म. छात्रनेता अभिषेक सिंह हत्याकांड और गौतम भट्टाचार्य की हत्या पर से भी पर्दा नहीं उठ सका.

इन दोनों ही मामलों में आरोपी नामजद किए गए, लेकिन रहस्य अभी भी अनसुलझा है. घटनाओं का ख़ुलासा न होने और लगातार वारदातें जारी रहने से पुलिस का इकबाल ही ख़त्म हो चला है. मेरठ में पूर्व सांसद की हत्या के बाद प्रदेश सरकार पर विपक्षी राजनीतिक दलों का हमला एक बार फिर तेज हो गया. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण देने की सरकारी नीति के कारण ही प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ठप्प हो गई है. मायावती सरकार में अराजकता का आलम है. क़ानून का राज ख़त्म हो गया है. मुख्यमंत्री को सिर्फ़ अपनी ही फिक्र है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने आरोप लगाया कि बसपा सरकार में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. आम आदमी ख़ुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है. थानों पर बसपा के लोगों का क़ब्ज़ा है. मेरठ में पूर्व सांसद अमरपाल सिंह की हत्या हो या फिर लखनऊ में डॉ. विनोद आर्य हत्याकांड, हर बार पुलिस की पोल खुल रही है. मेरठ में अमरपाल सिंह की हत्या साबित करती है कि पुलिस का ख़ौफ़ ख़त्म हो चुका है. थाने वसूली के अड्डे बन चुके हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हत्या, हिंसा, लूट और अपहरण की बढ़ती वारदातों से राज्य में सरकार न होने की स्थिति है. इस घोर अराजकता के लिए बसपा सरकार ही जिम्मेदार है. उन्होंने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप तक लगाया. विपक्ष के आरोप एक तरफ और पुलिस की कार्यप्रणाली दूसरी ओर. इन सबके बीच सरकार और उसके मंत्रियों का सुरक्षा चक्रव्यूह है, जिसमें फंसकर रोजाना ही गोलियों का शिकार हो रहे हैं आम आदमी, सरकारी अधिकारी–कर्मचारी एवं घरों में सिमटे बुजुर्ग.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अपराधी कितने बेख़ौफ़ हैं, यह मेरठ में कांग्रेस के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह की हत्या से स्पष्ट हो जाता है. कार में मामूली टक्कर से शुरू हुई कहासुनी के दौरान बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में पूर्व सांसद को गोलियों से भून डाला और आराम से चलते बने. बिगड़ती क़ानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश विधानसभा में भी उठ चुका है. विपक्ष के आरोपों के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री लालजी वर्मा ने राज्य की क़ानून व्यवस्था को बहुत बढ़िया करार दिया. उन्होंने यहां तक कह डाला कि इस मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के मुक़ाबले बेहतर है.

प्रमुख अपराध के त्रिवर्षीय तुलनात्मक आंकड़े (30 सितंबर 2010 तक)

क्र.सं.	अपराध	2010	2009	2008	2009 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2008 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)
1.	डकैती	127	122	86	4.10%	47.67%
2.	लूट	1545	1336	1212	15.64%	27.48%
3.	हत्या	3123	3308	3276	-5.59%	-4.67%
4.	बलवा	2566	3091	3133	-16.98%	-18.10%
5.	गृहभेदन	2913	3271	3337	-10.94%	-12.71%
6.	रोड होल्ड अप	0	1	4	-100.00%	-100.00%
7.	फिरौती के लिए अपहरण	50	40	45	25.00%	11.11%
8.	दहेज हत्या	1619	1735	1751	-6.69%	-7.54%9.
9.	बलात्कार	1025	1207	1304	-15.08%	-21.40%
10.	कुल मामले	119813	123266	120850	-2.80%	-0.86%

अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों के त्रिवर्षीय तुलनात्मक आंकड़े (30 सितंबर 2010 तक)

क्र.सं.	अपराध	2010	2009	2008	2009 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2008 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)
1.	हत्या	168	179	169	-6.15%	-0.59%
2.	आगजनी	20	35	37	-42.86%	-45.95%
3.	बलात्कार	219	218	294	0.46%	-25.51%
4.	गंभीर चोट	211	311	340	-32.15%	-37.94%
5.	अन्य हस्तक्षेपीय अपराध	3368	4608	4689	-26.91%	-28.17%
6.	कुल मामले	3986	5351	5529	-25.51%	-27.91%

महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों के त्रिवर्षीय तुलनात्मक आंकड़े (30 सितंबर 2010 तक)

क्र.सं.	अपराध	2010	2009	2008	2009 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2008 के सापेक्ष 2010 में कमी/वृद्धि (प्रतिशत)
1.	दहेज हत्या	1619	1735	1751	-6.69%	-7.54%
2.	बलात्कार	1025	1207	1304	-15.08%	-21.40%
3.	शीलभंग	2087	2230	2289	-6.41%	-8.82%
4.	अपहरण	3743	3682	3318	1.66%	12.81%
5.	छेड़खानी	1665	1938	2732	-14.09%	-39.06%
6.	महिला उत्पीड़न	5888	6217	6451	-5.29%	-8.73%
	योग	**16027**	**17009**	**17845**	**-5.77%**	**-10.19%**

चौथी दुनिया

संत कबीर के दोहों और उनके संदेश का ही असर रहा कि ख़लीलुर्रहमान ने सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ ख़लीलाबाद नगर बसाया जिसे वर्ष 1997 में ज़िला मुख्यालय का दर्ज़ा मिला.

बसपा विधायक ठाकुर जयवीर सिंह वर्तमान समय में प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं लेकिन बात जब मैनपुरी के विकास की आती है तो इनका आभा मंडल फीका पड़ जाता है.

चौथी दुनिया

दून कोबाड गांधी भी पैदा करता है

सोनिका श्रीवास्तव

दून स्कूल का शीर्ष प्रबंधन इस बात को लेकर चिंता में है कि स्कूल के बच्चों के शिक्षण में कौन सी वर्गीय-खोट है जो कोबाड गांधी को पैदा करती है. दून स्कूल के उच्च वर्गीय चरित्र पर कोबाड गांधी एक सवाल की तरह चस्पा है, जिसने उच्च वर्ग में पैदा होते हुए भी उच्च कुलीन वर्ग का चरित्र नहीं अपनाया और शोषितों-उत्पीड़ितों के हित के संघर्ष के लिए अपना जीवन अति-वामपंथ को न्यौछावर कर दिया. लेकिन दून स्कूल के प्रोडक्ट के रूप में निकले कोबाड गांधी ने स्कूल प्रबंधन के उच्च वर्गीय चरित्र को ज़रूर हिला कर रख दिया है. अब स्कूल के माहौल और छात्रावासों के माहौल को सूक्ष्म निगरानी में रखा जा रहा है कि कहीं अति-वामपंथ का ग्लैमर बच्चों में तो नहीं घर करता जा रहा है. स्कूल प्रबंधन के सूत्र तो यह भी बताते हैं कि स्कूल में नियुक्त होने वाले शिक्षकों व अन्य स्टाफ की पृष्ठभूमि पर भी ग़ौर फरमाया जाने लगा है. दून स्कूल की ग़ौरवशाली पृष्ठभूमि में कोबाड गांधी का नाम भी अवश्य जुड़ता है. भले ही आप कोबाड गांधी के अपनाए हुए रास्ते को लेकर सैद्धांतिक असहमति रखते हों. राजनीतिक सोच, कार्यशैली और व्यक्तित्व परस्पर विरोधी होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रख्यात नक्सली नेता कोबाड गांधी में समानता है. ये सब दून स्कूल के ही पढ़े लिखे हैं. विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह भी दून स्कूल की देन हैं. उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण सिंह, पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय दिनेश सिंह और भी न जाने कितनी विख्यात हस्तियों का नाम इससे जुड़ा हुआ है. लेकिन कोबाड गांधी ने दून स्कूल के इस इतिहास में अपने नाम का अध्याय ही जोड़ दिया. महाकवि रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन... को 1935 में ही अपना गान चुनने वाला दून स्कूल स्थापना के 75वें वर्ष में अब खुद की जय हो... की नए सिरे से तलाश शुरू कर दी है. दून स्कूल की धुन यह भी है कि अब वहां के प्रोडक्ट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैनवास पर अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ रहे. दून स्कूल से निकलने वाले भारतीय राजनीतिज्ञों की अगर लंबी चौड़ी लिस्ट है तो पाकिस्तानियों में भी इसका आकर्षण कम नहीं रहा है.

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ख़ान मोहम्मद अली, स्वात के वली मियांगुल औरंगजेब, पंजाब के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी ने यहीं तालीम हासिल कर ज़िंदगी के मोर्चे पर फतह हासिल की. नौकरशाही में तो दून स्कूल का दबदबा है. इस स्कूल से अनुशासन का पाठ पढ़कर निकलने वालों में प्रमुख रूप से स्वर्णजीत सेन पूर्व डीजीपी आंध्रप्रदेश, पीपी शर्मा मुख्य सचिव झारखंड, विनोद कुमार ग्रोवर, दिलीप मेहता, केपी शंकर मेनन, नागेंद्र नाथ झा, उमा शंकर वाजपेई, महेश्वर दयाल, अशोक बी. गोखले, वजाहत हबीबुल्लाह, इंदरपाल खोसला व रामचंद्र साठे शामिल हैं. देहरादून की हरी-भरी वादियों में स्थित दून स्कूल का नाम शुरू से ही देश के सबसे प्रतिष्ठित निज़ी स्कूलों में लिया जाता रहा है. इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बच्चे के पैदा होने के साथ ही अभिभावक उसका पंजीकरण इस स्कूल के लिए करा देते हैं.

वायसराय ऑफ इंडिया की कार्यपरिषद के सदस्य अधिवक्ता सतीश रंजन दास ने सन 1935 में दून स्कूल की स्थापना की थी. स्कूल के लिए क़रीब 70 एकड़ में फैले चांदबाग एस्टेट को ख़रीदा गया. इसी स्थान पर भव्य दून स्कूल का निर्माण किया गया. सतीश रंजन दास स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास व भारत के मुख्य न्यायाधीश सुधि रंजन दास के भाई थे. इस विद्यालय के पहले प्रधानाध्यापक आर्थर ई फुट बनाए गए. वे ब्रिटेन के एटान स्कूल के विज्ञान शिक्षक थे. वे इससे पहले भारत कभी नहीं नहीं आए थे. उन्होंने सबसे पहले जेके मार्टिन को उप प्रधानाध्यापक नियुक्त किया. छात्रों के सार्वभौमिक विकास के लिए अंग्रेजी पब्लिक स्कूल की तर्ज़ पर इस स्कूल में भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी जाती है.

इससे पहले 1928 में इंडियन कंपनी एक्ट के तहत इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी का गठन किया गया. इसी के अधिकार क्षेत्र में दून स्कूल की स्थापना की गई. यह स्कूल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए संचालित होता है. रवींद्र नाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन... को 1935 में ही विद्यालय ने अपना गान चुन लिया था. बाद में सन 1946 में भारत ने इसे राष्ट्रगान के लिए चुना. इस विद्यालय का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उदारवादी शिक्षा प्रदान करना है जिससे उनमें धर्मनिरपेक्षता, अनुशासन व समानता के सिद्धांतों के प्रति आदर भाव जागृत हो सके. इसी शिक्षा का प्रभाव रहा कि दून स्कूल ने देश को सैन्य अधिकारियों की बड़ी फौज भी दी. पाकिस्तानी नौकरशाही में भी दून स्कूल से शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों का वर्चस्व है. उद्यमियों में कई ऐसी हस्तियां हैं जो दून स्कूल का पूर्व छात्र कहलाने में गौरव महसूस करती हैं. दून स्कूल ने केवल राजनीतिज्ञ, सैन्य अधिकारी, उद्यमी ही देश को दिए हैं तो यह कहना ग़लत होगा. कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय की दखल बहुत गहराई तक है.

वर्ष 2008 में एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में इस विद्यालय को भारत में सबसे सम्मानित आवासीय विद्यालय का दर्ज़ा दिया गया. दून स्कूल में कक्षा सात व आठ में प्रवेश के लिए पंजीकरण होते हैं. पंजीकरण के बाद दाखिले प्रवेश परीक्षा के जरिए होते हैं. बच्चे की जितनी अधिक उम्र होती है उसका पंजीकरण शुल्क बढ़ता जाएगा. पंजीकरण फार्म दून स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ एक हज़ार रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगानी होगी. इसके साथ ही फार्म एक हज़ार रुपये का ड्राफ्ट दून स्कूल के हेडमास्टर के नाम भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है. इसके साथ 50 रुपए पोस्ट ऑफिस शुल्क भी भेजना होगा. स्कूल में प्रत्येक एकेडमिक ईयर में दो टर्म की पढ़ाई होती है. पहला टर्म स्प्रिंग टर्म जो कि एक फरवरी से शुरू होकर 31 मई तक चलता है. इसके बाद दूसरा टर्म ऑटम टर्म पहली अगस्त से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलता है. दून स्कूल में आईसीएसई व आईएससी बोर्ड के साथ ही इंटरनेशनल बैक्यालॉरिएट (आईबी) से पढ़ाई होती है. आईबी डिप्लोमा उन युवाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है जो विदेशों में जाकर आगे की पढ़ाई करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दून स्कूल की फीस

पंजीकरण शुल्क

0-3 वर्ष 11,000
3-5 वर्ष 14,000
5-6 वर्ष 16,500
7-8 वर्ष 21,000
9-11 वर्ष 27,000
11-13 वर्ष 35,000

स्कूल फीस

स्कूल फीस 3.45 लाख प्रति
प्रवेश शुल्क 50 हज़ार
सिक्योरिटी फीस 50 हज़ार
इंसीडेंटल फीस 30 हज़ार

आज भी ऊसर संत कबीर नगर

क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा.
जो कासी तन तजै कबीरा, रामे कौन निहोरा

काशी हो या फिर उजाड़ मगहर मेरे लिए (कबीर) दोनों ही बराबर हैं क्योंकि मेरे हृदय में राम बसे हैं. अगर कबीर की आत्मा काशी में इस तन को त्यागकर मुक्ति प्राप्त कर ले तो इसमें राम का कौन सा एहसान है...

देश 15वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर गया लेकिन संत कबीर की निर्वाण स्थली आज भी उजाड़ है. समय की धारा के साथ संत कबीर नगर ने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे. पहले इसे ख़लीलाबाद कहा जाता था. फिर संत कबीर दास के नाम पर इसे संत कबीर नगर कहा जाने लगा. कबीर का नाम तो मिल गया लेकिन उनके जैसी प्रसिद्धि हासिल न हो सकी. कबीर की निर्वाण स्थली होने के बावजूद यह ज़िला पर्यटन के नक्शे से नदारद है. 11 अगस्त, 2003 की बात है, तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मगहर आए थे. मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने भी उस समय मगहर की दुर्दशा को महसूस किया था. अपनी पीड़ा को उन्होंने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा था कि मगहर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए. कबीर के विचार और संदेश आज के दौर में पहले से अधिक प्रासंगिक हैं. कलाम के प्रयासों से एक लाख रुपया समाधि स्थल और एक लाख रुपया मजार स्थल को विकसित करने के लिए मिला था. वह दिन है और आज का समय, शासन स्तर से कोई मदद मगहर को नहीं मिली. संत कबीर के दोहों और उनके संदेश का ही असर रहा कि खलीलुर्रहमान ने सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ ख़लीलाबाद नगर बसाया जिसे वर्ष 1997 में ज़िला मुख्यालय का दर्ज़ा मिला. ख़लीलुर्रहमान मुगल शासन काल में दिल्ली में रहते थे, जहां उनकी मुलाकात मुगल बादशाह औरंगजेब से हुई. ख़लीलुर्रहमान की बुद्धिमता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें गोरखपुर परिक्षेत्र का चकलेदार एवं काजी नियुक्त कर दिया. खलीलुर्रहमान ने गोरखपुर और बस्ती के बीच ख़लीलाबाद कस्बा बसाया. वर्ष 1737 में उन्होंने शाही किला बनवाया. किले के अंदर मस्जिद का निर्माण भी कराया गया. खलीलुर्रहमान ने अपने पुश्तैनी गांव मगहर स्थित जामा मस्जिद से शाही किले तक आने-जाने के लिए सुरंग मार्ग भी बनवाया जो नौ किलोमीटर लंबा और 15 फीट चौड़ा है. इसी रास्ते से वह अपनी टमटम पर बैठकर किले तक जाते थे और वहां फरियादियों की दिक्कतों को सुनकर इंसाफ़ करते थे. किले और शाही रास्ते की सुरक्षा के लिए हर समय पहरेदारों की तैनाती रहती. गोरखपुर और बस्ती के बीच स्थित शाही किले ख़लीलाबाद को बारी (मुख्यालय) का दर्ज़ा हासिल था. मुगल शासनकाल में गोरखपुर का मुख्यालय ख़लीलाबाद ही था. ख़लीलाबाद जहां का तहां रह गया लेकिन गोरखपुर और बस्ती दोनों ही मंडल मुख्यालय बन चुके हैं. काजी खलीलुर्रहमान की प्रसिद्धि इतनी फैली कि मगहर के एक मोहल्ले का नाम ही काजीपुर पड़ गया. काजी खलीलुर्रहमान के वंशज आज भी अपने नाम के आगे काजी शब्द जोड़ना नहीं भूलते हैं. काजी का मतलब न्यायाधीश, जो उन्हें अपने ग़ौरवशाली अतीत की याद दिलाता है. बताया जाता है कि खलीलुर्रहमान साहब एक बार मथुरा गए जहां उन्होंने कई हिंदू मंदिरों में दर्शन पूजन किया. कबीर का प्रभाव उनके मन-मस्तिष्क पर पहले से ही था, सर्व धर्म समभाव की अलख जगाने के लिए उन्होंने शाही किले में एक मंदिर का निर्माण भी कराया. मुगल शासन काल का अंत होने के साथ ही ख़लीलाबाद का वैभव भी फीका पड़ने लगा. शाही किले पर क़ब्ज़ा करने के मकसद से अंग्रेजों ने आक्रमण किया लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी. इसमें कई लोग शहीद भी हुए जिन पर समूचा ख़लीलाबाद आज भी गर्व करता है. शाही किले के अंदर पूरब दिशा में पहले तहसील कार्यालय हुआ करता था, जो अब डाक बंगला के सामने स्थानांतरित हो चुका है. किले के पश्चिमी हिस्से में स्थापित माता का मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है.

शाही किला वर्तमान समय में पुलिस कोतवाली में तब्दील हो चुका है. किले के पीछे के हिस्से में पूरब दिशा में निकास स्थान का स्वरूप बदलकर इसे कोतवाली में बदल दिया गया है. राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक लापरवाही से यह धरोहर नष्ट होने को है. मगहर से ख़लीलाबाद तक नौ किलोमीटर लंबे शाही मार्ग के अब अवशेष ही बचे हैं. उन्हें डर है कि कहीं सरकार पर्यटन विभाग इसे अपने क़ब्ज़े में न कर ले. शाही किला हाथ से निकल गया और आज वह दुर्दशा का शिकार है. फिर इस सुरंग का भी बुरा हाल होगा. मगहर निवासी काजी अदील अहमद बताते हैं कि 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैले भू-भाग में उनके पूर्वज काजी खलीलुर्रहमान साहब ने शाही किले, मस्जिद, मंदिर और पोखरे का निर्माण कराया था, जो उनकी कौमी एकता की विचारधारा को पुष्ट करता है. वह गर्व से कहते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर काजी खलीलुर्रहमान ने जो कार्य किए, वह इतिहास के पन्नों में उन्हें सदैव के लिए अमर कर गए हैं. काजी अदील जानकारी देते हैं कि शाही किले में वर्ष 1953 में पुलिस थाना बनाया गया. किले के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसके पिछले हिस्से को कोतवाली के मुख्य द्वार के रूप में तब्दील कर दिया गया. खाली भूखंड पर पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनवा दिए गए. काजी अदील अहमद ने 50 एकड़ में फैले इस भू-भाग को अपनी खानदानी संपत्ति बताते हुए शासन से इसे उनके परिवार के सुपुर्द करने की मांग भी की है. वहीं संत कबीर नगर के नागरिकों की मंशा है कि शासन प्रशासन के अधिकारी मगहर से शाही किले तक बनवाई गई सुरंग की साफ़-सफाई कराकर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे और पूरे हिस्से को राष्ट्रीय स्मारक का दर्ज़ा देकर उसका संरक्षण किया जाए. कबीर की निर्वाण स्थली और काजी खलीलुर्रहमान के शाही किले के साथ ही पर्यटन के लिए इस ज़िले में रमणीय स्थलों की कमी नहीं है. यहां ख़लीलाबाद से आठ किलोमीटर की दूरी पर गामा गांव में महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है. यह मंदिर भगवान तामेश्वर नाथ को समर्पित है. मान्यता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति तामा के समीप स्थित जंगल में मिली थी. राजा बंसी ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कराया. प्रत्येक वर्ष यहां शिवरात्रि में बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों भक्त हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा कई अन्य स्थान हैं जो पर्यटकों को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित करते हैं फिर भी पर्यटन के नक्शे पर संत कबीर नगर उपेक्षित है.

शिव कुमार गुप्ता
feedback@chauthiduniya.com

कोई सुरक्षित नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

राजनीति में कत्ल का खेल बहुत पुराना

उत्तर प्रदेश की सियासत खूनी हो चली है. मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर हमले की घटनाएं नई बात नहीं है. अगर यह कहा जाए कि प्रदेश की राजनीति में कत्ल का खेल बहुत पुराना है तो ग़लत नहीं होगा. यही वजह है कि मेरठ में कांग्रेस के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह की हत्या अप्रत्याशित नहीं है. इससे पहले कई राजनीतिक हस्तियां इस खूनी सियासत की भेंट चढ़ चुकी हैं. हाल में जुलाई महीने में प्रदेश सरकार के संस्थागत वित्त मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पर इलाहाबाद में जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए. मुश्किल से उनकी जान बच सकी. इस घटना में नामजद मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्र हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. अब विजय मिश्र लापता हैं और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने संभवत: विजय मिश्र की हत्या करा दी है. इसके पहले जुलाई में ही सपा के पूर्व विधायक कपिलदेव सिंह की हत्या कर दी गई. इस घटना में भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात सामने आई. वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या की गई. इसमें अतीक अहमद नामजद किए गए, जो ख़ुद कई बार विधायक रह चुके हैं. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या भी खूनी सियासत से जुड़ी है. कृष्णानंद राय की हत्या में विधायक मुख्तार अंसारी नामजद किए गए थे. वर्ष 1998 में समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश पासवान की हत्या बम विस्फोट में हुई थी. वर्ष 2000 में सहारनपुर में विधायक निर्भयपाल शर्मा की हत्या भी गोली मारकर की गई थी. विधायक रविंद्र सिंह की हत्या जनता पार्टी के शासनकाल में की गई, वहीं पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की हत्या सुल्तानपुर में की गई. कांग्रेसी नेता लक्ष्मी शंकर यादव की हत्या लखनऊ के जियामऊ इलाक़े में माफिया सूरजपाल ने गोली मारकर की थी. भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और सपा सांसद फूलन देवी की हत्या भी सियासी दुश्मनी का नतीजा थी.

बुज़ुर्गों को शिकार बना रहे लुटेरे

लुटेरों के लिए बुज़ुर्ग आसान शिकार हैं. बढ़ती उम्र के साथ हाथ-पैर ठीक से काम नहीं करते और आंखों से भी साफ़ दिखाई नहीं देता. ऐसे में बुज़ुर्गों के पास घर में सिमटे रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन अब घर भी सुरक्षित नहीं रह गया है. हाल की कई घटनाओं ने परिजनों को अपने बुज़ुर्गों की सुरक्षा के प्रति चिंतित कर दिया है. इन बुज़ुर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की बात तो होती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है. राजधानी पुलिस ने बुज़ुर्गों के लिए सीनियर सिक्योरिटी सेल स्थापित किया था. दूसरी तमाम योजनाओं की तरह यह सेल भी नाक़ाम रहा है. कई घटनाओं में बुज़ुर्गों के सबसे बड़े दुश्मन उनके अपने ही निकले हैं. हाल में लखनऊ के तालकटोरा में मुनेश्वरपुरम में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी जमुना प्रसाद और उनकी रिश्तेदार मधु की हत्या संपत्ति के लालच में उनके रिश्तेदारों ने ही की थी. पुलिस ने मामले का ख़ुलासा करते हुए हत्याकांड में जमुना के दामाद सरजू को गिरफ्तार किया. ऐसे में एक अहम सवाल यह भी है कि पुलिस इन लालची रिश्तेदारों से बुज़ुर्गों की रक्षा कैसे कर सकेगी?

feedback@chauthiduniya.com

प्रमुख घटनाएं

15 नवंबर, 2010 : मेरठ में कांग्रेस के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह की गोली मारकर हत्या.
12 नवंबर, 2010 : तालकटोरा के मुनेश्वरपुरम में दो बुज़ुर्गों की हत्या.
08 नवंबर, 2010 : हापुड़ में बुज़ुर्ग दंपति राम प्रसाद बाना एवं मूर्ति की हत्या और लूटपाट.
08 नवंबर, 2010 : वाराणसी में रिटायर्ड अभियंता प्रियरंजन प्रसाद वर्मा और उनके नौकर को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट.
08 नवंबर, 2010 : लखनऊ की साउथ सिटी में रिटायर्ड मेजर जनरल एवं उनकी पत्नी को घायल कर लाखों की डकैती.
27 अक्टूबर, 2010 : लखनऊ के विकास नगर में सीएमओ (परिवार कल्याण) डॉ. विनोद कुमार आर्य की गोली मारकर हत्या.
11 अक्टूबर, 2010 : लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं उनके परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट.
01 अगस्त, 2010 : मुजफ्फरनगर में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री हुकुम सिंह की पत्नी की गला दबाकर हत्या.
12 जुलाई, 2010 : प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पर जानलेवा हमला.
04 जुलाई, 2010 : सपा के पूर्व विधायक कपिलदेव सिंह की गोली मारकर हत्या.
29 मार्च, 2010 : लखनऊ में अभिनेत्री मोना हार्वी की हत्या और लूट.
19 मार्च, 2010 : लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में प्रोफेसर पी सी जैन एवं उनकी पत्नी शैला जैन को घायल कर लूटपाट, बाद में दंपति की मौत.
27 जनवरी, 2010 : लखनऊ के ठाकुरगंज में बुज़ुर्ग दंपति और उनकी दस वर्षीय पोती की हत्या और लूट.

प्रतिशोध का लोकतंत्र

कालेश्वर सिंह

लोकतंत्र में सरकारें तो आती-जाती रहती हैं लेकिन इसका असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ता. विकास कार्य अपनी गति से चलते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संदर्भ और हालात में यह बात सही नहीं है. उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतरते ही नया मुख्यमंत्री अपने पूर्ववर्ती के पसंदीदा ज़िलों पर ही सबसे पहले सत्ता की चाबुक चलाता है. इस कटुता और प्रतिद्वंद्विता का ख़ामियाजा आम जनता और क्षेत्र विशेष को भुगतना पड़ रहा है. मुलायम सिंह यादव और मायावती की राजनीतिक दुश्मनी के बीच फंसा मैनपुरी इस कटु सच को उजागर करता है. मुगलकालीन भव्य किलों के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी अब राजनीतिक किलेबंदी का शिकार है. यहां के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब पांच दिसंबर, 1989 को मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने शपथ ली. फिर मैनपुरी में विकास का पहिया तेजी से घूमा. शासन प्रशासन के अधिकारियों की प्राथमिकता में इटावा के साथ मैनपुरी भी शामिल हो गया. जून, 1991 में मुलायम सरकार का पतन हो गया. फिर कल्याण सिंह की सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन लगा. कल्याण राज में मैनपुरी शासन की प्राथमिकता में नहीं रहा. दिसंबर, 1993 में मुलायम सिंह ने फिर सरकार की बागडोर संभाली. इस बार उनके साथ सरकार में सहयोगी थी बहुजन समाज पार्टी. बसपा को भी मैनपुरी का विकास भाया, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई. जून, 1995 में भाजपा के सहयोग से बसपा की सरकार बनी और मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस बार मायावती को मैनपुरी के विकास कार्य नहीं भा रहे थे. अधिकारी भी सत्ता का इशारा समझ गए और मैनपुरी में विकास का चक्का रुक गया. उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सच्चाई यही है. मैनपुरी जनपद ने अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विरासत के साथ देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज़ादी के बाद से यह कांग्रेस का गढ़ रहा. यहां से कांग्रेस के टिकट पर संसद और विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है. कांग्रेस के शासन में भी यहां विकास हुए लेकिन वह पर्याप्त नहीं थे. नतीजा जनता में कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ और मैनपुरी समाजवादी रंग में रंगने लगा. यह दौर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया का था. लोहिया जी ने यहां कई कार्यक्रमों व आंदोलनों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया. धीरे-धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और फिर कारवां बन गया. डॉ. लोहिया के नेतृत्व में मैनपुरी से चौधरी नत्थू सिंह यादव, धनगर सिंह, मुलायम सिंह यादव जुड़े. इन लोगों ने कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ नहर आंदोलन चलाया. उस समय मुलायम सिंह यादव 14 वर्ष की आयु में जेल गए, तभी से राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने लगे. इस दौरान ही मुलायम का परिचय किसान नेता चौधरी चरण सिंह से हुआ. लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाया. इसकी लहर पूरे देश में ऐसी चली कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इंदिरा की हार के बाद देश ने आपातकाल का दंश सहा. जनपद मैनपुरी भी इससे अछूता नहीं रहा. इमरजेंसी के बाद वर्ष 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया. नतीजा कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा. केंद्र व राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ. उत्तर प्रदेश में भी रामनरेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी. इस सरकार में मुलायम सिंह यादव प्रदेश के सहकारिता मंत्री बने. मुलायम के मंत्री बनने के बाद क्षेत्र के विकास की तस्वीर पहली बार बदली. समय के साथ मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का कार्य क्षेत्र हो गया. मैनपुरी के लोगों को अगर इसका फ़ायदा मिला तो उनका नुक़सान भी कम नहीं हुआ. 1977 से 1989 के लंबे समय अंतराल तक मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव की निकटता का खामियाजा विकास कार्यों से दूर रहकर भुगतना पड़ा. उस समय की कांग्रेसी सरकारों ने मैनपुरी को ज़िले के तौर पर नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के कार्यक्षेत्र के रूप में देखा. इस दौरान कई मुख्यमंत्री आए और गए जिनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह शामिल रहे. वर्ष 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. उस समय पहली बार मैनपुरी के विकास की रूपरेखा तैयार हुई. मैनपुरी में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था की जाने लगी. गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ने का काम शुरू हुआ. शासन स्तर से इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी गई. आज़ादी के बाद से जिस विकास की आस यहां के किसान और आम जनता लगाए थी, वह पूरी होती दिख रही थी.

लेकिन मुलायम को बहुत दिनों तक सत्ता नहीं मिल सकी. 24 जून, 1991 को उन्हें सत्ता से हटना पड़ा. कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली. कल्याण सिंह के सत्ता में आते ही मैनपूरी का विकास एक बार फिर मंद पड़ गया. मुलायम के शासन में मैनपुरी में नदियों पर पुलों का निर्माण कराया गया तो सड़कों का जाल बिछा. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सालय बनवाए गए. पशु चिकित्सालय भवन बने. बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ. स्कूल भवन बने. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, स्कूलों में मिड-डे-मील, किसानों को सस्ते दर पर बीज, खाद जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया. मुलायम की सरकार का यह फ़ायदा तो मैनपुरी को मिला लेकिन जब-जब मुलायम सत्ता से बेदखल रहे, मैनपुरी पूरी तरह से उपेक्षित रहा. वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव ने बसपा के सहयोग से सरकार बनाई. उस समय बसपा की तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मायावती को मैनपुरी का विकास पसंद आ रहा था. समय का चक्र तेजी से घूमा और स्थितियां बदल गईं. जो मुलायम व मायावती एक दूसरे के दोस्त थे, वह दुश्मन हो चुके थे. मुलायम सत्ता से बाहर थे और मायावती ने तीन जून, 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उनके मुख्यमंत्री बनते ही मैनपुरी विकास की प्राथमिता से बाहर हो गया. मैनपुरी के लिए मुलायम सरकार में लागू की गई योजनाएं और धन दूसरे ज़िलों में स्थानांतरित कर दी गईं. यही नहीं, मैनपुरी की आम जनता को मुलायम सिंह यादव की पार्टी का कार्यकर्ता बताकर उसके साथ उत्पीड़न की पुलिसिया कार्रवाई तक की गई. हालात यह बने कि मैनपुरी आने वाले अधिकारी अपनी भूमिका पहले से ही तय कराकर आते थे. इसके बाद मायावती जब-जब सत्ता में आईं, मैनपुरी के साथ उनकी उपेक्षा बरकरार रही. समाजवादी चिंतक प्रो. केसी यादव कहते हैं कि बसपा सरकार की मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम सिंह यादव की व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण जनपद की घोर उपेक्षा हुई है. मैनपुरी के सारे विकास कार्य बसपा सरकार में रोक दिए गए. बसपा का रवैया बदला लेने वाला है. वह बताते हैं कि सपा के शासनकाल में जनपद की नहरों व रजवहों के द्वारा किसानों की भूमि को सिंचित करने के लिए समय पर पानी दिया जाता था. पर आज किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहें हैं. अधिकारी किसानों की समस्या देखना-सुनना पसंद नहीं करते हैं. इस वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जनपद में वृक्षारोपण का भी सफ़ाया कर दिया गया है. जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है. मैनपुरी की पांच विधानसभा सीटों में से तीन पर सपा के विधायक हैं. इनमें करहल विधानसभा सीट से सपा के सोबरन सिंह यादव, भोगांव से आलोक शाक्य, किसनी से सपा की संध्या कटेरिया विधायक हैं. मैनपुरी सदर से भाजपा के अशोक चौहान, घिरोर से बसपा के ठाकुर जयवीर सिंह विधायक हैं. बसपा विधायक ठाकुर जयवीर सिंह वर्तमान समय में प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं लेकिन बात जब मैनपुरी के विकास की आती है तो इनका आभा मंडल फीका पड़ जाता है. अपने मंत्री होने का कोई फ़ायदा वह मैनपुरी को नहीं दिला सके हैं. राजनीतिक प्रतिशोध के इस माहौल से त्रस्त मैनपुरी की जनता को फिलहाल उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती है. राजनीतिक द्वेष में जातीय और व्यक्तिगत उत्पीड़न का शिकार होना लोगों की नियति बन चुकी है. ऐसे में अब कोई परिवर्तन ही उन्हें इससे निजात दिला सकेगा.

feedback@chauthiduniya.com

ज़िला प्रशासन निरंकुश

सरकार की शह पर ज़िला प्रशासन लगातार निरंकुश होता जा रहा है. एक ओर अधिकारी अपनी हनक के चलते क़ानून को ताक पर रख कर कार्य कर रहे हैं. इन्हे क़ानून से कोई सरोकार नहीं है. आए दिन अधिकारियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं. फिर भी इन पर कोई असर नहीं हो पा रहा है. एक ओर सरकार पिछड़ें वर्ग की कुछ जातियों से प्रतिशोध की भावना के साथ काम कर रही है. वहीं प्रशासन भी सरकार की नीति से दो क़दम आगे चल रहा है. हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे दौर में दीवानी अधिवक्ता की सीओ कुरावली डीके पुरी द्वारा की गई पिटाई ने पूरे जनपद के वकीलों का पारा चढ़ा दिया. इसी को लेकर जनपद के मैनपुरी बार एसोसिएशन दीवानी और ज़िला बार एसोसिएशन कचहरी पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार को वकीलों ने कई बार ज्ञापन सौपकर सीओ डीके पुरी के ख़िलाफ़ अभियोग दर्ज़ कराने की भी मांग की है. अधिवक्ता सुभाष बाबू यादव द्वारा न्यायालय के आदेश पर सीओ डीके पुरी के विरुद्ध सीआरसी की धारा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज़ कराया गया है. कुरावली सीओ द्वारा की गई पिटाई से अधिवक्ता का हाथ टूट गया है. करहल ब्लॉक के कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव भांति निवासी वकील सुभाष बाबू अपने ही ग्राम पंचायत नगरिया के मजरा नगला भांति के बूथ पर सपा के ज़िला पंचायत सदस्य सुमन दिवाकर के एजेंट थे. उसी दौरान ग्राम पंचायत के दो गुटों में नगला भांति मतदान केंद्र पर साढ़े तीन बजे कुछ दूरी पर प्रधान पद के प्रत्याशियों में वोट डालने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई. इसके उपरांत फायरिंग शुरू हो गई. फायरिंग के दौरान पोलिंग पार्टी ने एजेंटों को मतदान केंद्र पर बने दूसरे कमरे में सुरक्षा की दृष्टि से बैठा कर दरवाज़ा बंद करा दिया. इसी दौरान सीओ डीके पुरी कुरावली और कुर्रा थानाध्यक्ष मतदान केंद्र पर पहुंचे. सीओ द्वारा कमरा खुलवाकर बिना पूछे ही एजेंटों को पीटना शुरू कर दिया. जिससे अधिवक्ता सुभाष बाबू के गंभीर चोंटे आई. बाद में पीड़ित ने बताया कि मैं सिविल कोर्ट मैनपुरी में अधिवक्ता हूं. इस पर सीओ ने गालियां देते हुए कहा कि तू बहुत बड़ा अधिवक्ता है. तेरे ख़िलाफ़ गैंगेस्टर की कार्रवाई करूंगा. मारपीट के दौरान अधिवक्ता की सोने की चेन और मोबाइल गुम हो गया. सीओ ने कुर्रा एसओ को मुकदमा दर्ज़ करने के निर्देश दिए. सुभाष के ख़िलाफ़ अपराध संख्या 644/10 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 147, 148, 171ग, 186, 352,353, 336, व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लॉ एवं धारा 131 प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मामला थाना कुर्रा में पंजीकृत किया गया. न्यायालय के आदेश पर वकील का मेडिकल भी कराया गया इसके लिए तीन डाक्टरों का पेनल गठित कर जांच की गई. तीनों चिकित्सकों ने रिपोर्ट में हाथ की हड्डी को टूटा बताया. पंचायत चुनाव में डीके पुरी द्वारा प्रथम चरण में कुरावली ब्लाक के औछा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लपुर पोलिंग बूथ पर एक पार्टी के तमंचा धारियों को संरक्षण देकर बूथ कैपचरिंग का भी मामला प्रकाश में आया है. यहां पर सीओ द्वारा स्थानीय अखबार के प्रतिनिधि द्वारा तमंचा धारियों का फोटो लेने पर पिटाई की गई. इस मामले पर आईजी ने भी सीओ के विरूद्ध मामला दर्ज़ कराने को कहा था. लेकिन इस मामले में भी कार्रवाई न होने से ज़िले के पत्रकारों में रोष व्याप्त है. चुनाव के प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक सीओ डीके पुरी का हिटलर शाही रवैया रहा है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीओ ने बड़े पैमाने पर धाधंली व रिश्वत जैसी घटनाएं सामने आई. मैनपुरी बार एसोसिएशन के सचिव अजय कृष्ण पांडेय का कहना है कि वे मामले को लेकर आगे तक जाएंगे. जब तक सीओ डीके पुरी का तबादला अन्य जनपद में न हो जाए. मामले की जांच सीबीसी आईडी द्वारा कराई जाए.

नदवा में दारुल इफ्ता का कोर्स कराया जाता है. एक साल का यह कोर्स पूरा करने वाले तुलबा (छात्र) को मुफ्ती की डिग्री दी जाती है, जो फतवा जारी करते हैं.

नदवातुल उलेमा

शिक्षा के साथ संस्कार भी

दारुल उलूम नदवातुल उलेमा का जिक्र आते ही जेहन में एक तस्वीर उभर कर आती है. वह यह कि दीनी तालीम की दुनिया में अहम दर्ज़ा रखने वाला एक मदरसा, जहां पाक कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म हासिल करने वालों को मौलवी, मुफ्ती, क़ारी एवं हाफिज की डिग्री प्रदान की जाती है. फतवों पर ग़ौर फरमाया जाता है. नदवा यानी इस्लाम के सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य ज़रूरी पहलुओं का अहम केंद्र. यह इसका एक पक्ष है, जो दुनिया को दिखाई देता है. इसका दूसरा पहलू भी है, जो क़रीब जा कर इसे समझने के बाद ही नज़र आएगा. वह यह कि दीनी इल्म के साथ ही दुनिया की वे तमाम तालीम, जो केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं, नदवा में दी जाती है. पश्चिमी देशों की चकाचौंध से मुस्लिम समुदाय को दूर रखते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन देने का काम भी यहां के उलेमा कर रहे हैं. यही वजह है कि लखनऊ को अगर शाम-ए-अवध, कौमी एकता के लिए शोहरत हासिल है तो दारुल उलूम नदवातुल उलेमा उसे इल्म की दुनिया में फख्र का एहसास कराता है. गोमती के किनारे स्थित नदवा की आलीशान इमारत की तरह ही इसकी उपलब्धियां भी शान में इज़ाफ़ा करने वाली हैं. यहां से निकलने वाले छात्रों ने समूची दुनिया में अपना नाम रोशन किया है. नदवा से तालीम हासिल करने वाले अकरम नदवी इस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और वह कई किताबें लिखकर बुलंदी हासिल कर चुके हैं. मौलाना शफीक अहमद नदवी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. ऐसी नामचीन हस्तियों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है. वक्त के साथ चलते हुए नदवा ने अपने कोर्स में बदलाव किए हैं. अंग्रेजी और कंप्यूटर की अहमियत समझते हुए इसे तहेदिल से अपनाया है. कॉन्वेंट एजूकेटेड बच्चों की तरह नदवा के छात्र भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं. यह बात अलग है कि वे अंग्रेजी दां होने का दिखावा नहीं करते. वे इस बात का अफसोस भी नहीं करते कि लोग उन्हें केवल उर्दू और अरबी का जानकार समझते हैं. नदवा के प्राचार्य डॉ. एस आर आजमी फरमाते हैं कि उनके यहां छात्रों को अंग्रेजी लिखना-बोलना दोनों ही सिखाया जाता है, ताकि जब वे यहां से अपनी तालीम पूरी करके निकलें तो उन्हें भाषा की दिक्कत पेश न आए. ई-गवर्नेंस के इस दौर में नदवा के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है. बकौल उनके, नदवा से पढ़ाई पूरी करने के बाद यहां के छात्र एमबीए समेत अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं. एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्र कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं. उनके करियर की राह में दीनी तालीम कहीं से रोड़ा नहीं बनती, बल्कि वह उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है.

नदवा में इस समय पांच हज़ार से अधिक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. अकेले लखनऊ में इसकी 25 से अधिक शाखाएं हैं. देश और दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से छात्र यहां तालीम हासिल करने आते हैं, जिन्हें नदवा की 120 साल पुरानी विरासत के साये तले दीनी तालीम के साथ दुनियावी इल्म से रूबरू कराया जाता है. वर्ष 1890 का दौर था, दुनिया भर में तमाम तरह की उथल-पुथल मची थी, तब उस समय के मुस्लिम उलेमाओं ने ग़ौर किया कि एक ऐसा मदरसा होना चाहिए, जो मुसलमानों को दीनी तालीम के साथ दुनिया की तमाम तालीम (जो उनके लिए ज़रूरी हैं) दे सके. इस सोच के साथ दारुल उलूम नदवातुल उलेमा की बुनियाद रखी गई, जिसे हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी साहेब और मौलाना सैय्यद मोहम्मद राबे हसन नदवी के अलावा अन्य नामचीन मुस्लिम उलेमाओं की सरपरस्ती मिली. अपनी स्थापना के साथ ही नदवा ने इस्लामी दुनिया में अहम दर्ज़ा हासिल किया. यह न केवल भारत, बल्कि समूची दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित करता है. यह महज एक इस्लामिक संस्था नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, जो अंधविश्वास, कुरीतियों, आडंबरों के ख़िलाफ़ इस्लाम को अपने मूल और पवित्र रूप में प्रसारित करता है. मुस्लिम लड़कों की तालीम के साथ ही नदवा लड़कियों को भी शिक्षित करने की दिशा में काफ़ी गंभीर रहा है. डॉ. आजमी बताते हैं कि लड़कियों को तालीम देने के लिए लखनऊ एवं रायबरेली के मदरसों में ख़ास व्यवस्था है. वैश्विक युग में जनसंचार माध्यमों की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है. यहां मीडिया का दख़ल हर क्षेत्र में बढ़ा है. इसे देखते हुए नदवा ने छात्रों के लिए शहाफ़त का कोर्स भी शुरू किया है, इसमें इच्छुक छात्र दाख़िला लेकर मीडिया में अपनी अलग पहचान बनाने का काम करते हैं. संस्थान में मीडिया रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है, यहां तमाम समाचारपत्र-पत्रिकाएं छात्रों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, ताकि वे दुनिया में हो रही घटनाओं, बदलाव और प्रयोगों से ख़ुद को ज़हीनी तौर पर तैयार कर सकें. इस मीडिया रिसर्च सेंटर की देखरेख की जिम्मेदारी लेक्चरर उबैद-उर-रहमान नदवी को सौंपी गई है. मुस्लिम समाज में फतवों का अहम स्थान है. फतवे कैसे जारी किए जाते हैं, इसके लिए क्या नियम हैं, कौन इन्हें जारी कर सकता है, यह तमाम सवाल मुस्लिमों के साथ ही ग़ैर मुस्लिमों के लिए जिज्ञासा का विषय हैं.

नदवा में दारुल इफ्ता का कोर्स कराया जाता है. एक साल का यह कोर्स पूरा करने वाले तुलबा (छात्र) को मुफ्ती की डिग्री दी जाती है, जो फतवा जारी करते हैं. फतवों के संबंध में किसी भी तरह की जिज्ञासा और सवालों का संतोषजनक जवाब देने के लिए नदवा प्रबंधन ने ऑनलाइन व्यवस्था भी कर रखी है. इसके जरिए दुनिया भर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं. मीडिया रिसर्च सेंटर के लेक्चरर उबैद-उर-रहमान नदवी बताते हैं कि नदवा में रिसर्च वर्क में दिरासत फिल कुरानी वसुन्ना शामिल है, जिसमें छात्र पाक कुरान और हदीस पर रिसर्च करते हैं. इस कोर्स में छात्रों के लिए कम से कम एक थिसिस लिखना ज़रूरी होता है. हिज्ब का कोर्स भी कराया जाता है. इसमें छात्र कुरान को कंठस्थ करते हैं. इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. यह छात्रों की स्मरण शक्ति पर भी निर्भर करता है कि वह कितने वक्त में कुरान को कंठस्थ कर सकते हैं. बकौल रहमान नदवी, हज़ारों की संख्या में छात्र नदवा से तालीम हासिल करके कुरान को कंठस्थ कर चुके हैं. कुरान की आयतों का सही तलफ्फुज (उच्चारण) करने के लिए तजबीद का कोर्स होता है. रहमान नदवी ख़ुद भी कई किताबें लिख चुके हैं. वंदे मातरम पर मुस्लिम समाज का नज़रिया विषय पर भी उन्होंने किताब लिखी है, जिसमें कई गैर मुस्लिम विद्वानों के विचार भी प्रकाशित किए गए हैं. मतलब साफ़ है कि विचारधारा का दायरा काफ़ी बड़ा है. विचारों को थोपने की प्रवृत्ति यहां हावी नहीं है. उर्दू, अरबी एवं अंग्रेजी के साथ ही नदवा में हिंदी भाषियों के लिए प्रकाशन की व्यवस्था है. संस्थान ने हिंदी में कई किताबें प्रकाशित कराई हैं. इनमें मन्सबे पैगंबरी मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी, नबी-ए-रहमत, दस्तूरे हयात (जीवन का पथ प्रदर्शक), सभ्यता और संस्कृति पर इस्लाम की..., भारतीय मुसलमान एक दृष्टि में आदि समेत अन्य शीर्षकों से प्रकाशित किताबों की एक लंबी फेहरिस्त है. नदवा की देश भर में सौ से अधिक शाखाएं हैं. यह नदवा की स्वीकार्यता, उसकी महत्ता और विद्वता को दर्शाता है.

यही वजह है कि दारुल उलूम नदवातुल उलेमा आज इस्लामिक शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन चुका है. यहां न केवल इस्लामिक शिक्षा पर ग़ौर फरमाया जाता है, बल्कि मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर भी इसकी नज़र रहती है. नदवा के साथ एक अच्छाई और भी जुड़ी है, वह यह कि संस्थान आतंकवाद का घोर विरोधी रहा है. याद कीजिए पाकिस्तान में जब दो सिखों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, उस समय नदवा के प्राचार्य डॉ. आजमी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तालिबान इस्लाम के नुमाइंदे नहीं हैं. तालिबान की सारी हरकतें गैर इस्लामी हैं. उन्होंने यह भी फरमाया कि जिस वहशियाना तरीक़े से दो सिखों की हत्या की गई, उसे कोई भी सच्चा मुसलमान मान्यता नहीं दे सकता. डॉ. आजमी के इस कथन और उनकी सोच से भारतीय मूल्यों और मान्यताओं को मजबूती मिलती है. समूचा विश्व जब आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है तो नदवा से निकली यह आवाज़ उन फिरकापरस्त ताकतों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए काफ़ी है, जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर देखने की हिमाकत करते हैं. ऐसे तत्व आज ख़ुद कठघरे में खड़े हैं और सफाई देते फिर रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नदवा से प्रकाशित हिंदी पुस्तकें

1. मन्सबे पैगंबरी
2. नबी-ए-रहमत
3. दस्तूर-ए-हयात (जीवन का पथ प्रदर्शक)
4. सभ्यता और संस्कृति पर इस्लाम की...
5. भारतीय मुसलमान एक दृष्टि में
6. मदीने की डगर
7. मानवता का संदेश
8. मानवता का स्तर
9. जग के मोहसिन
10. अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह के
11. इस्लाम मुकम्मल दीन मुस्तकिल
12. निशाने राह
13. नारी की प्रतिष्ठा और उसके...
14. हिंदुस्तानी मुसलमानों से साफ़
15. इस्लाम एक परिचय
16. नौजवानों के नाम
17. आदर्श शासक
18. तूफ़ान से साहिल तक
19. समान सिविल कोड
20. सुल्तान टीपू शहीद

महिलाओं के राजनीति में आने का विरोध

लड़कियों की तालीम के मामले में दारुल उलूम नदवातुल उलेमा काफ़ी गंभीर दिखाई देता है, लेकिन इसके विपरीत वह महिलाओं के राजनीति में आने का विरोधी भी है. इसी साल मार्च माह में जब महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में हंगामा मचा, उसी दौरान नदवा के प्राचार्य डॉ. आजमी का एक वक्तव्य काफ़ी चर्चा में रहा. डॉ. आजमी ने कहा था कि इस्लाम महिलाओं को पर्दा त्यागने, जनता में भाषण देने (तकरीर) और अपना हक़ मांगने की इजाजत ही नहीं देता है. इस्लाम में महिलाओं को साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि वे बुर्के में घर में रहें और घर की देखभाल करें. उन्होंने उस समय यहां तक कह दिया कि राजनीति में आने की मंशा रखने वाली महिलाओं के पास एक ही विकल्प है कि वे मर्द बन जाएं. मौलाना के इस बयान ने महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का मौक़ा तलाश रहे नेताओं के सामने दिक्कतें खड़ी कर दीं, लेकिन यह सवाल भी उठा कि जब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाएं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति बन सकती हैं तो फिर भारत में उन्हें यह आज़ादी क्यों नहीं? मौलाना के इस बयान को शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का समर्थन भी मिला था. मौलाना का यह बयान इस लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इनका अच्छा दख़ल है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केंद्र बिंदु भी नदवा ही रहता है. ऐसे में मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं. महिलाओं के राजनीति में आने का विरोध करने पर डॉ. आजमी एवं कल्बे जव्वाद को समाज के अंदर ही विरोध का सामना भी करना पड़ा था. पढ़ी-लिखी मुस्लिम महिलाओं ने इस मसले पर अपनी तीखी नाराज़गी जाहिर की. मुस्लिम महिलाओं की इस प्रतिक्रिया के बाद यह तो साफ़ हो गया था कि वे लीडर बनेंगी, लेकिन इसके बीच सवाल यह भी उठा कि क्या महिलाओं को सिर्फ़ तालीम दिला देने भर से उन्हें उनके हक मिल जाएंगे. दीनी एवं दुनियावी तालीम के लिए दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों में अपना अहम स्थान रखने वाले नदवा के प्राचार्य अगर ऐसी सोच रखते हैं तो फिर आम मुस्लिम परिवार के मुखिया की क्या स्थिति होगी, यह विचारणीय है.

फोटो – प्रभात पाण्डेय

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 06 दिसंबर–12 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

उम्मीदों का ताज

पिछले दो सालों में डीजल सब्सिडी की योजना में बहुत सारी शिकायतें आईं. नई सरकार को इस तरफ़ भी व्यवहारिक नज़रिये से देखना होगा.

बिजली के क्षेत्र में तो जितना निवेश होगा, बिहार उतना ही चमकेगा. सर्विस सेक्टर में भी संभावनाएं हैं. बाढ़ नियंत्रण बिहार में विकास के तमाम रास्ते खोल सकता है.

नीतीश कुमार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक साधारण मुख्यमंत्री की हैसियत जितना ही काम किया था, चूंकि उस समय साधारण काम भी बिहार के लिए अंधेरे में रोशनी जैसा था, इसलिए नीतीश स्पेशल बन गए. लेकिन इस बार का मौक़ा उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अफसरशाही और नक्सल जैसी गंभीर चुनौतियां लेकर आया है. इसलिए इस बार उन्हें कुछ स्पेशल करना ही होगा.

सरोज सिंह

बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को छप्पर फाड़ जनादेश देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. ऐसा जनादेश, जिसकी कल्पना ख़ुद नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे थे. लेकिन बिहार की जनता ने लोकतंत्र के महापर्व का पूरा मज़ा लेते हुए जनादेश के साथ नीतीश कुमार को ढेर सारी ज़िम्मेदारियों से भी लबरेज कर दिया. यह ऐसा जनादेश है, जो बिहार की जनता की उम्मीदों से पूरी तरह सराबोर है. नीतीश कुमार की अगली पारी इन्हीं उम्मीदों की कसौटी पर कसी जाएगी. बिजली, स्वास्थ्य, पूंजी निवेश, कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं पलायन आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर बहुत सारा काम होना बाकी है. नीतीश कुमार को भी इस प्रचंड जनादेश के बाद सूबे के लोगों की बढ़ी हुई उम्मीदों का एहसास है, इसलिए उन्होंने जीत के बाद साफ़ किया कि मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन पूरी मेहनत के साथ यह कोशिश ज़रूर करूंगा कि राज्य की जनता की उम्मीदें पूरी कर सकूं.

नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में विकास की झलक दिखाई तो बिहार के लोगों ने अपना दिल खोल दिया. जाति का बंधन टूट गया और सूबे की जनता ने इस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार को चुन लिया कि विकास के अधूरे पड़े काम पूरे होंगे. ख़ासकर बिजली और कल कारखानों को लेकर बिहार की जनता नीतीश कुमार की तरफ़ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है. नीतीश कुमार अपने चुनाव प्रचार में कहते भी रहे कि अगर लोगों ने मौक़ा दिया तो घर-घर में बिजली जलाना उनकी प्राथमिकता होगी. सड़कों का जाल बिछाने का काम तो जारी रहेगा, पर बिना बिजली के पूंजी निवेश का मामला फिर लटका ही रह जाएगा. पिछली बार भी हर ज़िले में छोटे बिजलीघरों के निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन यह काम नहीं हो पाया. इसलिए लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार की पहली प्राथमिकता यही होगी. लोग यह भी चाहते हैं कि कांटी एवं बरौनी थर्मल पावर से बिजली पैदा करने का सपना पूरा हो. निजी क्षेत्र में बिजलीघर लगाने के प्रस्तावों पर भी सरकार को अमल करना होगा. यह काम ऐसा है, जो सूबे के लोगों पर जादुई असर डालेगा. बिहार का हर तबका बिजली संकट से जूझ रहा है. अगर इस संकट से राहत मिली तो नीतीश पर लोगों का भरोसा चार गुना बढ़ जाएगा. कृषि के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि राज्य में कुल खेती योग्य भूमि में से केवल 57 फ़ीसदी में ही सिंचाई के इंतजाम हैं. जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 95 फ़ीसदी है. किसानों के हित में जो नीतियां हैं, उन्हें गांवों तक पहुंचाने की बड़ी ज़िम्मेदारी सरकार के कंधे पर है. सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां 70 फ़ीसदी छोटे किसान हैं, इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएं.

पिछले दो सालों में डीजल सब्सिडी की योजना में बहुत सारी शिकायतें आईं. नई सरकार को इस तरफ़ भी व्यवहारिक नज़रिये से देखना होगा. शिक्षा का मामला भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती है. सिर्फ़ स्कूल भवनों के निर्माण एवं भोजन की व्यवस्था से हालात नहीं बदल सकते. स्कूलों में अच्छे शिक्षक ही निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाट सकते हैं. बिहार में कई बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कभी स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है. महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में भी बिहार काफ़ी पीछे है. लोगों की सेहत के बारे में भी सरकार को काफी गंभीरता से सोचना होगा. ज़िला एवं गांव के स्तर पर कम से कम इतनी सुविधा हो कि ग़रीब आदमी अपना प्रारंभिक इलाज करा सके. डॉक्टरों की भारी कमी के कारण भी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है. गांवों में भी अच्छे डॉक्टर मौजूद रहें, इसका ध्यान भी सरकार को रखना होगा. स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति ख़र्च करने में बिहार काफ़ी पीछे है. राष्ट्रीय स्तर पर 1100 रुपये ख़र्च होते हैं, जबकि बिहार में 513 रुपये. लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनाने में भी सरकार को अपनी ताक़त लगानी होगी. अगर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ गई तो बीमारों की संख्या ख़ुद-ब-ख़ुद कम हो जाएगी.

पिछली सरकार में निवेश के तो ढेर सारे प्रस्ताव आए, पर ज़मीन पर नहीं उतर पाए. वजह जो रही हो, पर इस कार्यकाल में नीतीश कुमार को इस पर विशेष ध्यान देना ही होगा. बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं. बिजली के क्षेत्र में तो जितना निवेश होगा, बिहार उतना ही चमकेगा. सर्विस सेक्टर में भी संभावनाएं हैं. बाढ़ नियंत्रण बिहार में विकास के तमाम रास्ते खोल सकता है. अब तक सरकार की सक्रियता राहत कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन इस प्रचंड जनादेश के बाद सरकार को बाढ़ के स्थाई समाधान पर गंभीरता से सोचना होगा. हर साल बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क़रीब 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है. इस कारण जान-माल का नुक़सान तो होता ही है, इसके साथ ही साथ विकास की गाड़ी भी आगे के बजाय पीछे दौड़ने लगती है. केंद्र सरकार को भरोसे में लेकर राज्य सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द ठोस क़दम उठाने होंगे. पलायन भी एक गंभीर समस्या है. इसे रोकने के संबंध में सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, पर हक़ीक़त यही है कि अभी भी पंजाब, मुंबई और दिल्ली जाने वाले बिहारी मज़दूरों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. काम की तलाश और शिक्षा के लिए बिहार के लगभग 20 लाख लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं. शिक्षा पर राज्य से लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों में चले जाते हैं. इसके अलावा अफसरशाही पर नियंत्रण भी नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. नीतीश अपने पिछले कार्यकाल में इन आरोपों से दो-चार होते रहे हैं. आम लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ अधिकारी सुनें और उनकी समस्याओं का हल निकालें. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ऐलान तो नीतीश अपनी सभाओं में कर रहे थे. इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण जनता को भारी राहत दे सकता है. लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और बिना घूस दिए उनका काम हो जाए तो नीतीश की लोकप्रियता में चार चांद लग सकते हैं.

आख़िर में राज्य की सबसे बड़ी समस्या और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर चर्चा ज़रूरी है. यह समस्या है नक्सलवाद की. बिहार के दो तिहाई ज़िले नक्सल प्रभावित हैं. इन ज़िलों में नक्सली न केवल विकास के काम को प्रभावित करते हैं, बल्कि वहां के सामाजिक ताने-बाने को भी नुक़सान पहुंचाते हैं. मुठभेड़ में नक्सली कम मरते हैं, जवान ज़्यादा शहीद होते हैं. जेल ब्रेक जैसी घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है. लोगों ने नक्सलियों की चुनाव बहिष्कार की अपील को दरकिनार कर नीतीश कुमार को वोट दिया है. इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समग्र प्रयास करने की ज़रूरत सभी महसूस कर रहे हैं. नई सरकार को भी चाहिए कि वह बिना समय गंवाए इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस बीमारी पर क़ाबू पाए, नहीं तो विकास के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे. जनादेश एक विकसित बिहार के लिए मिला है, इसलिए लोगों को पूरा भरोसा है कि नई सरकार इस कसौटी पर खरी उतरेगी. जनता ने अपना काम कर दिया, अब सरकार को अपना काम करना है. अगर सरकार ने अपना काम कर दिया तो बिहार को नंबर वन राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

कहीं दीप जले

कहीं दिल

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जदयू के बूढ़े शेर रामेश्वर पासवान लोजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस को 12 हज़ार 361 मतों से पराजित कर सिकंदरा के सिकंदर बन गए.

इस बार एनडीए को सभी जाति वर्ग के मतदाताओं के मत मिले हैं. इसे नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

एक नज़र इधर भी

पारस की बंध गई पोटली

खगड़िया ज़िले के बेहद पिछड़े विधानसभा क्षेत्र अलौली में अंतत: 33 वर्षों के बाद लोजपा प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की पोटली बंध ही गई. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के अनुज पारस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाने के बजाए ज़मीन पर पटक देगी. दरअसल हार से बचने के लिए उन्होंने अपने चहेते रामचंद्रा सदा को जदयू का टिकट यह सोचकर दिलवाया था कि उन्हें मुसहर समाज के तीन-तीन प्रत्याशियों के खड़े रहने से जीतने में मदद मिलेगी. हुआ उल्टा. महादलित समाज के लोगों ने एकजुट होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.

विकास की गंगा में बह गए विपक्षी

खगड़िया की जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने लगातार तीसरी बार खगड़िया विस पर क़ब्ज़ा जमाकर साफ़ कर दिया कि अगर जनाधार हो चुनावी वैतरणी पार होती ही है. उनके बाहुबली पति रणवीर यादव के विरुद्ध आरोप लगाकर एक ख़ास वर्ग के मतदाताओं ने उन्हें हराने की ठान ली थी. लेकिन वह भारी मतों से चुनाव जीतीं. उनके और रणवीर के द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ-साथ नीतीश कुमार की विकास की गंगा में विपक्ष पूरी तरह बह गया.

दो दशक से अधूरी पड़ी है नहर

गया ज़िले के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत उत्तरी कोयल नहर परियोजना पिछले दो दशक से अधूरी पड़ी है. इस परियोजना के लिये करोड़ों रुपये ख़र्च कर नहर की खुदाई की गई. लेकिन इस नहर में आज तक पानी नही आ पाया. किसानों को उम्मीद थी कि नहर में पानी आ जाने से उनके खेतों की रौनक बढ़ेगी और खुशहाली आएगी. लेकिन उनके अरमानों पर अब तक पानी फिरता रहा है. दो दशक पूर्व बनी इस नहर की स्थिति रोज़ और दयनीय होती जा रही है. किसी भी राजनेता ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया. **– डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा.**

विनय अग्रवाल नए प्रांतीय अध्यक्ष

मारवाड़ी युवा मंच का तृतीय प्रांतीय सम्मेलन 19 से 21 नवंबर तक देवघर में आयोजित हुआ. सम्मेलन में रांची के विनय अग्रवाल को निर्विरोध नया प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया. निर्वतमान प्रांतीय अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह मिशन टू के लिए संयोजक मनोनित किया गया. इस मौके पर विनय अग्रवाल ने कहा कि दहेज हत्या और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराईयों को समाज से दूर करने पर काम किया जाएगा. साथ ही, प्रांत में अधिक से अधिक रक्तदान शिविर, कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर एवं चिकित्सकीय कैंप लगाए जाएंगे. इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित थे. कार्यक्रम को सफल बनाने में पवन टमकोरिया, ओम छावछरिया, हरीश तोलाशरिया, शॉल्टी अग्रवाल, सौरभ बाजला, मनोज नेवर, आनंद मोदी और अभिषेक अग्रवाल की प्रमुख भूमिका रही. सम्मेलन में देवघर की महिला शाखा की भी सार्थक सहभागिता रही. **–रणजीत झा, देवघर**

जी टी रोड टूट रहा है

जी टी रोड का आख़िरी बार कायाकल्प केंद्र की राजग सरकार के ज़माने में हुआ था. पचास वर्षों तक बिना किसी मरम्मत के टिका हुआ, फोर लेन के नाम से चर्चित यह रोड राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 पर निर्माण के दो वर्षों के बाद टूटने लगा है. इतने कम समय में टूटती सड़क ने निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया. गया ज़िले के शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत आमस से लेकर बाराचट्टी प्रखंड तक इस फोरलेन में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं. बताया जाता है कि सड़क के घटिया निर्माण का कारण निर्माणकर्ता कंपनियों द्वारा पेटी कार्टेल पर काम करवाना है. इस राष्ट्रीय उच्च पथ के ए जी एम सत्येंद्र दुबे की हत्या को भी इसी निर्माण कार्य से जोड़ कर देखा जा रहा है.

झोलाछापों के सहारे ग्रामीण

सरकार के लाख दावों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के मरीज़ झोला छाप डाक्टरों के सहारे हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्साकर्मी ग़ायब रहते हैं. परिणामस्वरूप गांव की जनता नीम-हकीमों और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पर मजबूर है. शेरघाटी के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों के बोर्ड टंगे मिल जाएंगे, जिसे नर्सिंग होम का नाम देकर जनता को बरगलाया जाता है. हालांकि यह भी सच है कि सरकारी व्यवस्था के विपरीत ये झोलाछाप डॉक्टर ही मुश्किलों में ग्रामीणों के काम आते हैं. **– आशुतोष राज**

अविश्वास प्रस्ताव का मामला गरमाया

संग्रामपुर प्रखंड प्रमुख के ख़िलाफ़ पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रमुख द्वारा तिथि निर्धारण नहीं करने पर उपप्रमुख विनेश तिवारी ने नवंबर माह में ही तिथि निर्धारित की है. आचार संहिता लागू रहने से संग्रामपुर बीडीओ ने ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी और सह ज़िलाधिकारी से प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति मांगी थी. ज़िलाधिकारी द्वारा हरी झंडी भी मिल गई है. संग्रामपुर प्रमुख से पूछने पर उन्होंने कहा कि एक सात पहले भी उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जो न्यायालय में लंबित है. बिना न्यायालय से डिस्पोज हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कैसे होगी. रोचक पहलू तो यह है कि जब प्रमुख ने बीडीओ से पूछा कि क्या आपने वरीय पदाधिकारियों से प्रस्ताव पर चर्चा करने या न करने के संबंध में दिशा निर्देश लिए हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जवाब दिया कि उन्हें प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मौखिक अनुमति मिल गई है. इस बात पर पलटवार करते हुए प्रमुख ने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी मौखिक रूप से बता रहा हूं कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर मौखिक रूप से चर्चा नहीं होने दूंगा. एक तरफ़ प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बयानबाज़ी है वहीं दूसरी ओर अपने क़ीमती वोट देकर विकास कार्यों की ओर टकटकी लगाए आम मतदाता हैं. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी अथवा कोर्ट के आदेश का इंतज़ार होगा, यह तो समय ही बताएगा. बहरहाल संग्रामपुर प्रखंड का यह मामला काफ़ी दिलचस्प बन गया है और जनता फ़ैसले के इंतज़ार में आस लगाए बैठी है. **–अभय कुमार पांडेय, संग्रामपुर**

नीतीश जादूगर हैं

पिछले चुनाव की तरह इस बार भी खगड़िया ज़िले के तीन विधानसभा क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा जमाकर जदयू ने यह साबित कर दिया है कि नीतीश के जादू के आगे कोई टिकने वाला नहीं है.

राजेश सिन्हा

खगड़िया ज़िले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधायकों की कारगुज़ारियों से ख़ासे नाराज़ थे. मतदान के कुछ दिन पहले तक मतदाताओं ने ऐसे विधायकों को हराने की लगभग ठान ली थी. लेकिन मतदान के अंतिम समय में बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ख़ुश मतदाताओं ने ऐसा पैंतरा बदला कि तीनों विधानसभा क्षेत्र एक बार एनडीए के खाते में चले गए. हालांकि यह बात अलग है कि सूबे के परिवहन मंत्री रामानंद सिंह को राजद-लोजपा के उम्मीदवार राकेश कुमार उर्फ़ सम्राट चौधरी के हाथों हार झेलनी पड़ी. जबकि लोजपा के खाते वाले अलौली विधानसभा क्षेत्र को जदयू ने हथिया लिया. वैसे तो पूरे बिहार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे लेकिन खगड़िया के सभी चार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी कम चौंकाने वाले नहीं रहे.

33 साल से अलौली(सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम रखने वाले पशुपति कुमार पारस को इस बार जदयू के एकदम नए उम्मीदवार रामचंद्र सदा ने हरा दिया. रामचंद्र को 53 हज़ार 7 सौ 22 मत मिले जबकि पारस को महज़ 36 हज़ार 1 सौ 31 मतों से ही संतोष करना पड़ा. विकास से वंचित मतदाता नीतीश सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर ऐसे गोलबंद हुए कि पारस पटखनी खाने को मजबूर हो गए. परवत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक रामानंद सिंह को राजद-लोजपा के उम्मीदवार सह पूर्व कबीना मंत्री राकेश कुमार उर्फ़ सम्राट चौधरी ने पटखनी दी. बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो जदयू विधायक पन्नालाल पटेल मतदाताओं की नाराज़गी के बाद भी सुनीता चौधरी को हराने में कामयाब रहे. बहुचर्चित खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव की पत्नी पूनम देवी यादव चुनाव जीत गईं. लगातार तीसरी बार चुनावी पताका लहराने वाली पूनम से कुछ मतदाता नाराज़ थे. लेकिन फिर भी उन्हें कोई ख़ास नुक़सान नहीं हुआ. पूनम देवी यादव को जहां 48 हज़ार 7 सौ 29 मत मिले वहीं उनकी ही जेठानी लोजपा-राजद उम्मीदवार सुशीला देवी को महज़ 21 हज़ार 8 सौ 60 मतों से ही संतोष करना पड़ा. निर्दलीय प्रत्याशी ई. धर्मेंद्र 15 हज़ार 1 सौ 81 मतों से तीसरे तथा कांग्रेस की प्रीति वर्मा 45 सौ 33 मत लाकर चौथे स्थान पर रहीं. इस तरह पूनम देवी यादव ने अपनी जेठानी सुशीला को 26 हज़ार 8 सौ 60 मतों से धूल चटाई. यहां एक बात स्पष्ट करना ज़रूरी है कि खगड़िया नगर परिषद के सभी सोलह वार्ड पार्षद पूनम के द्वारा लगाए गए एक आरोप से इतने आहत थे कि उन्होंने उनकी चुनावी राह में कांटे बिछा रखे थे. लेकिन जनता का इन बातों से कोई सरोकार नहीं रहा और जीत उन्हें ही नसीब हुई. मारड़ के मुस्लिम मतदाताओं ने भी अपने स्वजातीय प्रत्याशियों की अपील को ठुकरा कर पूनम को अपना नूर-ए-नज़ीर समझा. बहरहाल, इतना तो कहा ही जा सकता है कि नीतीश के विकास की आंधी ने बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों के साथ-साथ अन्य विपक्षी पार्टियों के समीकरणों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

feedback@chauthidunya.com

शांति और विकास की चाहत ने जीत दिलाई

अतरी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के एक सामान्य कार्यकर्ता प्रो. कृष्णनंदन यादव को सफलता मिली. यह क्षेत्र राजद के गढ़ के रूप में जाना जाता था और यहां के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव के आतंक का सशक्त विरोध कोई भी नहीं कर पाता था. लेकिन इस बार जनता ने साहस दिखाते हुए राजेंद्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया.

सुनील सौरभ

गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों ने सभी को दंग कर दिया. ज़िले में राजद-लोजपा गठबंधन और कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब होगी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था. अमन और विकास की हवा ऐसी चली कि जदयू-भाजपा को दस में से नौ सीटें मिल गईं. अब तो यही कहा जा सकता है कि नक्सलवाद से त्रस्त और विकास से महरूम लोगों ने विकास की आस में जनादेश दिया है.

बात गया शहर विधानसभा क्षेत्र से शुरू करते हैं, जहां के विधायक और मंत्री प्रेम कुमार भाजपा के टिकट पर लगातार छठीं बार सफल रहे. मंत्री रहते शहर में पेयजल जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं करने के साथ-साथ शहरवासी की उपेक्षा करने का आरोप प्रेम कुमार पर लगता रहा. वजीरगंज विधानसभा से भाजपा के वीरेंद्र कुमार सिंह को सफलता मिली. वह पिछले कई चुनाव में अतरी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव हार चुके थे. यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था. यहां वीरेंद्र सिंह को अपने गठबंधन के ही सबसे अधिक बाग़ियों को झेलना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह जैसे दिग्गज को बड़े अंतर से हराया. बाराचट्टी विधानसभा सुरक्षित से जदयू के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी की समधिन ज्योति मांझी भी बड़े अंतर से जीतीं.

नवसृजित शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से पहले प्रतिनिधि के रूप में जदयू के विनोद प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे. बताया जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी का वरदहस्त उन्हें प्राप्त था. यहां राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ख़ान राजद प्रत्याशी थे. परिसीमन के बाद उन्होंने अपना क्षेत्र गुरुआ से बदलकर शेरघाटी कर लिया. लेकिन गुरुआ की उपेक्षा करने के मामले ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और करारी शिकस्त मिली. इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जदयू के लिए सबसे अधिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था. यहां से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी जदयू प्रत्याशी के रूप में थे. यहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने वोट बहिष्कार और उदय नारायण चौधरी के ख़िलाफ़ मत देने का आ वान अपरोक्ष रूप से किया था. बड़ी मुश्किल से उन्हें जीत मिली.

गुरुआ विधानसभा क्षेत्र पर पहले से राजद का क़ब्ज़ा था, लेकिन परिसीमन से क्षेत्र ऐसा प्रभावित हुआ कि यहां के विधायक शकील अहमद ख़ान को यहां से जाना पड़ा. यहां से भाजपा के सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा लगभग 11 हज़ार मतों से विजयी हुए. टिकारी विधानसभा क्षेत्र में डॉ. अनिल कुमार को पुन: बड़ी सफलता मिली.

अतरी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के एक सामान्य कार्यकर्ता प्रो. कृष्णनंदन यादव को सफलता मिली. यह क्षेत्र राजद के गढ़ के रूप में जाना जाता था और यहां के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव के आतंक का सशक्त विरोध कोई भी नहीं कर पाता था. लेकिन इस बार मतदाताओं ने पूर्व विधायक राजेंद्र यादव के आतंक से मुक्ति और विकास के सपने को साकार करने के लिए कृष्णनंदन यादव को करीब 20 हज़ार मतों से विजयी बनाया. बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्याम देव पासवान भाजपा के टिकट पर जीते. हालांकि यहां के तत्कालीन भाजपा के हरि मांझी के सांसद बन जाने के बाद हुए उप चुनाव में लोजपा के कुमार सर्वजीत ने सफलता प्राप्त की थी. लेकिन हरि मांझी के द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने के आक्रोश में कुमार सर्वजीत को विधानसभा पहुंचने में मदद मिली. कहा जा सकता है कि भाजपा-जदयू के किसी प्रत्याशी ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की. बेलागंज विधानसभा क्षेत्र राजद के पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव पुन: विजयी हुए. उन्होंने अपने विरोधी जदयू के मो. अमजद को क़रीब पांच हज़ार मतों से हराया. गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव का लब्बोलुआब यही रहा कि नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में विकास के साथ लोगों को अमन-चैन चाहिए और लोगों ने इसी उम्मीद से जदयू-भाजपा को एक बड़ा जनादेश दिया.

feedback@chauthidunya.com

जमुई

अजय - सुमित की धमाकेदार इंट्री

जमुई की जनता ने इस बार राजनीति की धारा ही बदल दी. दिग्गज ज़मीन पर और पहली बार अपनी क़िस्मत आज़मा रहे उमीदवार विधानसभा पहुंच गए. सबसे हैरान करने वाला नतीजा चकाई विधानसभा क्षेत्र का रहा. यहां लोजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को झामुमो के सुमित कुमार सिंह उर्फ़ विक्की ने 188 मतों से हरा दिया. चकाई की जनता ने सन 1977 के उस चुनावी इतिहास को दोहराया. उस दौरान बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फाल्गुनी प्रसाद यादव ने तराज़ू चुनाव चिन्ह पर 95 मतों से चुनाव जीता था. भाजपा प्रत्याशी फाल्गुनी प्रसाद यादव से उनके स्वजातीय मतदाता काफ़ी नाराज़ चल रहे थे. जमुई विधानसभा क्षेत्र में विजय प्रकाश की लालटेन बुझ गई. यहां से अजय प्रताप सिंह चुनावी समर में अजेय योद्धा साबित हुए. सिंकदरा(सु.) विधानसभा क्षेत्र में जाति-धर्म की राजनीति में विश्वास करने वाले राजद व लोजपा के नेताओं ने लोजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस को परिणाम के पूर्व संध्या पर ही जश्न मनाकर विजयी घोषित कर डाला था. लेकिन जदयू के बूढ़े शेर रामेश्वर पासवान लोजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस को 12 हज़ार 361 मतों से पराजित कर सिंकदरा के सिकंदर बन गए. कांगेस के प्रत्याशी सिंधु कुमार पासवान को मतदाताओं ने चौथे पायदान पर स्थापित किया. मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह के नुमाइंदे कांग्रेस का जलवा दिखाने के बजाए तीन सीट से जाकर सट गए. राजपूत-भूमिहार मतों में बिखराव पाया गया. लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी श्याम रजक को बहत दिलाने वाले झाझा विधानसभा क्षेत्र में माय समीकरण का जादू इस बार नहीं चला. समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत ने राजद प्रत्याशी विनोद प्रसाद यादव को 10 हज़ार 204 मतों से पराजित किया. झामुमो के आबिद कौशर ने 8736 मतों से तीसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं पूर्व ज़िला परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस प्रत्याशी मो. इरफान ने नए क्षेत्र से चुनाव लड़ने में 8286 मत हासिल कर अपनी कुशलता का परिचय दिया. नए परिसीमन में लक्ष्मीपुर प्रखंड के शामिल होने से यहां यादव मतदाओं के वोट बैंक में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ था, लेकिन पचपोनिया वोट के एकजुट हो जाने से इसका सीधा फ़ायदा जदयू प्रत्याशी को मिला. बताते चलें कि झाझा विधानसभा में सर्वाधिक 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे थे. बेलहर के जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव का प्रभाव इस क्षेत्र पर शुरू से रहा है और उनके प्रयासों से ही दामोदर रावत को काफ़ी लाभ मिला.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthidunya.com

पब्लिक को सब मालूम है

नीरज कुमार सिंह

अभी बिहारी जनता का मन बदल गया है. वह विकास, शांति और स्वास्थ्य व्यवस्था का अर्थ समझने लगी है. इस बार यहां के मतदाताओं ने खुलकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया. लेकिन वहीं किशनगंज में तस्लीम फैक्टर जदयू को फ़ायदा पहुंचाने में नकाम रहा. परिणामस्वरूप किशनगंज की चार सीटों में से किसी पर एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया. जैसा कि चौथी दुनिया ने चुनाव पूर्व सीमांचल की सीटों और रिजल्ट का आकलन किया था, चुनाव परिणाम ठीक इसी के अनुरूप निकला. किशनगंज की चार सीटों में से किशनगंज डॉ. जावेद आजाद, बहादुरगंज तौसीफ आलम, कोचाधाम राजद अख्तरूल ईमान और ठाकुरगंज नौशाद आलम की झोली में गया. पूर्णिया की सात सीटों में से छह सीटें एनडीए की पक्ष में गईं, जबकि 1 सीट कांग्रेस की झोली में आई. पूर्णिया के बायसी विधान विधानसभा के मतदाताओं ने अपना ऐतिहासिक फ़ैसला दिया, जिससे इस विधानसभा से पहली बार कमल फूल खिला. यहां से भाजपा के संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रत्याशी निसार अहमद को लगभग 8 हज़ार मतों से हराया. संतोष कुशवाहा को लगभग 39855 मत कांग्रेस को 30635 मत व राजद प्रत्याशी को 25639 मत मिले. अमौर से भाजपा प्रत्याशी सबा जफर ने कांग्रेस के जलील मस्तान को लगभग 26531 मतों से हराया. सबा जफर को 56498 मत मिले. सीमांचल से भाजपा कोटे से जीतने वाले सबा जफर एकमात्र अल्पसंख्यक विधायक हैं, जिसमें मंत्री बनने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है. पूर्णिया सदर से भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के रामचरित्र यादव को लगभग 20 हज़ार मतों से हराया. केसरी को 40372 मत मिले जबकि कांग्रेस को 21914 मत मिले. कसबा को परिणाम कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गया. यहां से अफाक आलम ने भाजपा के प्रदीप दास को 2700 वोटों से हराया. धमदाहा से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष लेसी सिंह ने राजद के वर्तमान विधायक दिलीप कुमार यादव को लगभग 45046 मतों से हराया. रुपौली से जद(यू) के बीमा भारती ने लोजपा के शंकर सिंह को लगभग 21 हज़ार मतों से हराया, वहीं बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषिदेव ने राजद प्रत्याशी को 47 हज़ार मतों से हराया. अररिया के जोकिहाट से तस्लीम के पुत्र सबा जफर ने जद(यू) प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराई. जबकि अररिया सीट से लोजपा के जाकिर अनवर जीते. फारबिसगंज से प्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र वेनु पदम रेणु ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. इस प्रकार से अररिया की कुल छह सीटों में पांच एनडीए के पक्ष में गईं, वहीं कटिहार की सात सीटों में से 6 सीटें एनडीए के पक्ष में चली गईं. जिसमें से 5 भाजपा के खाते में व एक जद(यू) के खाते में गई. किशनगंज में सीटों को लेकर भाजपा व जद(यू) के बीच मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में तस्लीम समर्थक अधिकतर प्रत्याशियों को टिकट मिला. लेकिन किशनगंज में तस्लीम फैक्टर हवा-हवाई साबित हुआ. अगर भाजपा की परंपरागत सीट बहादुरगंज व ठाकुरगंज थी. भाजपा के खाते में होती तो हवा का रुख़ कुछ और होता. लेकिन आपसी तालमेल के अभाव में एनडीए किशनगंज में पूरी तरह से समाप्त हो गई. वहीं तस्लीम फैक्टर जद(यू) का खाता तक नहीं खुलवा पाया. कुल मिलाकर सीमांचल में भाजपा सबसे अधिक सफल पार्टी रही है. जिसमें पूर्णिया के भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

अफ़ाक आलम

राज किशोर केसरी

लेसी सिंह

सबा ज़फ़र

रंजीत कुशवाहा

feedback@chauthidunya.com

नालंदा

एनडीए की हैट्रिक

अभी तक यहां जातीय आंकड़ों और समीकरणों के इर्द-गिर्द की राजनीति चलती रही है. नालंदा ज़िले की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही थी. लेकिन इस बार जिस प्रकार एनडीए ने ज़िले की सभी सातों सीटों पर जीत दर्ज की, उससे तो सभी पुराने राजनीतिक समीकरणों की परिभाषा ही बदल गई.

नीतीश कुमार के गृह ज़िले नालंदा में इस बार एनडीए ने जीत की हैट्रिक बनाकर सूबे में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ग़ौरतलब है कि फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में ज़िले में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सभी आठों सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया था. परिसीमन के बाद चौथी विधानसभा के विलोपित हो जाने के बाद नालंदा में कुल सात सीटें शेष रह गईं थीं. वर्तमान चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर सभी सातों सीटों पर जीत दर्ज की. इस बार के चुनाव में विकास एक सशक्त मुद्दे के रूप में उभरा.

यूं तो जातीय आंकड़ों पर राजनीति की बात बिहार में एक ज़माने से होती चली आ रही है. जातीय आंकड़ों एवं समीकरणों के इर्द-गिर्द यहां की राजनीति चलती रही है. नालंदा ज़िले की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही है. पिछले चुनाव के परिणामों में जातीय समीकरणों का प्रभाव देखा गया था लेकिन इस बार जिस प्रकार एनडीए ज़िले की सभी सातों सीटों पर जीत दर्ज की उससे राजनीति की एक नई परिभाषा दिखी. एक ओर चुनाव के पूर्व जहां एनडीए गठबंधन सुशासन एवं विकास को मुद्दा बनाकर चुनावी राजनीति बना रहा था वहीं विपक्षी जातीय आंकड़ों और सरकार की विफलताओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास कर रहे थे. नतीजे सामने आ गए. इसमें विकास का मुद्दा हावी रहा. इस बार एनडीए को सभी जाति वर्ग के मतदाताओं के मत मिले हैं. इसे नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अस्थावां विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी डॉ. जितेंद्र कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी लोजपा के कपिलदेव सिंह को 19570 से पराजित किया. यहां से जदयू प्रत्याशी को 54175 और लोजपा प्रत्याशी को 34605 मत मिले. बिहार विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने राजद प्रत्याशी आफरीन सुल्ताना को 23766 मतों से हराया. जदयू प्रत्याशी को 77573 मत मिले वहीं राजद प्रत्याशी को 53807 मत मिले. इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद प्रत्याशी वीरेंद्र गोप को 23807 मतों से पराजित किया. नालंदा विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार ने राजद प्रत्याशी अरुण कुमार को 21033 मतों से पराजित किया. हिलसा विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी ऊषा सिन्हा ने लोजपा की रीना देवी को 13202 मतों से पराजित किया. हरनौत विधान सभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी हरिनारायण सिंह ने लोजपा के अरुण कुमार को 15042 मतों से पराजित किया. राजगीर सुरक्षित क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव नारायण आर्या ने लोजपा प्रत्याशी धनंजय कुमार को 26951 मतों से पराजित किया.

कुमार प्रशांत

feedback@chauthidunya.com

छाया: कुमार प्रशांत

चौथी दुनिया
दिल्ली, 06 दिसंबर–12 दिसंबर 2010
Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

वाल्मीकी व्याघ्र परियोजना को दीमक की तरह चाट कर जंगल से हिरणों का सफ़ाया किया जा रहा है. इस काम में वन विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं.

वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना

अब हिरणों की बारी

जब हम किसी हिरण को लाठी से तड़पा-तड़पा कर मारते हैं तो सबसे ज़्यादा क़ीमत उसकी खाल की मिलती है. एक खाल के पंद्रह-बीस हज़ार रुपये मिल जाते हैं. गोली से मारने पर बहुत कम दाम मिलते हैं और ख़तरा भी बढ़ जाता है. यह काम मैं अकेले नहीं करता, पूरी टीम काम करती है. टीम का नेतृत्व हमारा मुखिया करता है. उसके पास दूरदराज से बड़े-बड़े बाबू लोग आते हैं, दाम तय करते हैं. उसके बाद उनके ठिकाने तक माल पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है. यह कहना है हिरणों को मारकर उनकी खाल और अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य का.

वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में हिरणों के जीवन पर सदैव ख़तरा मंडराता रहता है. बीते अक्टूबर माह में पुलिस द्वारा तीन लोगों को हिरण के सींगों, जाली नोटों, अवैध हथियारों और कैमरे के साथ गिरफ्तार किया जाना यह दर्शाता है कि परियोजना में सब कुछ ठीकठाक नहीं है. यहां अंतरराष्ट्रीय तस्करों का जाल बिछा हुआ है, जो एक रणनीति के तहत परियोजना को दीमक की तरह चाट कर जंगल से हिरणों का सफ़ाया कर रहे हैं. इस काम में वन विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं. दूसरी तरफ़ विकास के बजाए परियोजना का लगातार पतन होता जा रहा है. जबकि सरकार ने परियोजना के विकास के लिए वार्षिक योजना के तहत 2 करोड़ 91 लाख रुपये दिए हैं. इसमें केंद्र की ओर से 2.11 करोड़ और राज्य सरकार की ओर 80 लाख रुपये शामिल हैं.

वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है. इसकी परिधि 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 335 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षित क्षेत्र है. परियोजना संवर्द्धन के लिए यहां चीतल, बार्किंग डियर, सांभर, सांगरी और नीलगाय आदि छोड़े गए थे, लेकिन आज इन पर तस्करों की गिद्ध दृष्टि लग चुकी है. तस्करों के उत्पात के चलते मारे जा रहे हैं या फिर उचित देखरेख न होने से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ़ भाग रहे हैं. इसलिए हिरणों की संख्या दिनोंदिन घटती जा रही है. वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के अनुसार, 2002 में परियोजना में हिरणों की संख्या 6,000 थी. 2003 में यह संख्या घटकर 4,000 हो गई. 2007 की गणना के मुताबिक़, यह संख्या 1500 के आसपास रह गई है. 22 अक्टूबर, 2005 को वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 29 में चार नर चीतलों के मारे जाने की सूचना मिली. इससे परियोजना की कार्यशैली पर प्रश्न उठने शुरू हो गए. ग्रामीण मानते हैं कि बाबुओं की मिलीभगत से हिरणों की जान जा रही है. बरसात के दिनों में जब गंडक नदी का पानी परियोजना में घुस जाता है तो हिरणों की जान पर बन आती है. हिरण पानी के बहाव में दूर-दूर तक निकल जाते हैं. वे या तो ग्रामीणों द्वारा दियारा में पकड़े जाते हैं या मार दिए जाते हैं. विभाग द्वारा हिरणों की सुरक्षा के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि भोजन का इंतजाम न होने के कारण हिरण ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ निकल जाते हैं. 2007 के बाद लगातार हिरणों की हत्या के समाचार मिल रहे हैं. बीती 3 अगस्त को परियोजना के कर्मचारियों को सूचना मिली कि वाल्मीकि नगर के नया टोला हवाई अड्डा गांव में कुछ लोग हिरण को मारकर उसका मांस पका रहे हैं. रेंजर सुनील कुमार के नेतृत्व में छापा मारे जाने पर वहां चीतल का अधपका मांस बरामद हुआ. इस मामले में दो महिलाओं और एक पुरुष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. परियोजना के कर्मचारी उस समय विवाद के घेरे में आ गए, जब लोगों ने हरनाटॉड ग्रामीण परियोजना के निदेशक को बताया कि उन्होंने जिन दो हिरणों को पकड़ कर विभागीय कर्मचारियों को सौंपा था, उनकी मौत हो गई. इसका समर्थन विधायक कैलाश बैठा ने भी किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने हिरण जीवित अवस्था में सौंपे थे, इसकी सीडी भी मौजूद है. अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे विधानसभा में दिखाया जाएगा.

हिरण की खाल के बदले बीस हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं. विदेशी कारोबारी यहां आकर गिरोह के मुखिया से मिलते हैं और फिर यहीं सब कुछ तय हो जाता है. क्षेत्रीय निदेशक आर बी सिंह कहते हैं कि परियोजना की कार्यशैली फिर से चुस्त-दुरुस्त की जाएगी. जानवरों की सुरक्षा के लिहाज से चार वितंतु सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है और चेकपोस्टों की संख्या बढ़ाई जा रही है. सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि का इस्तेमाल जानवरों के रखरखाव और विकास पर ख़र्च किया जाएगा. हालांकि इस पर अभी संदेह बरकरार है कि हिरणों की घटती संख्या पर क़ाबू पाया जा सकेगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगरों के बाद अब हिरणों की बारी है.

अरविन्द नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

नीलाम हुआ लोकतंत्र

सौ रुपये का एक वोट

बिहार में लोकतंत्र भी बिकता है. विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और नीतीश कुमार की सरकार भी बन गई, लेकिन इस चुनाव में लोकतंत्र का एक घिनौना चेहरा देखने को मिला. गया ज़िले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में लोकतांत्रिक अधिकारों की बोली लगाई गई. इस बोली में दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी सभी शामिल थे. वोटों की खुलेआम ख़रीद-फरोख्त हुई. यह ख़रीदारी गांव से लेकर शहरों तक में हुई. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मतदाताओं की सभाएं बुलाकर बोली लगाई गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में बूथ और मोहल्लावार मतों के ठेके दिए गए. इस ठेके में पंचायत से लेकर नगर निकाय तक के प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई. विधानसभा में जाने को बेताब प्रत्याशियों ने मताधिकार की बोली लगाकर लोकतंत्र को नीलाम किया. गुरुआ, वजीरगंज, शेरघाटी एवं अतरी विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने वोट ख़रीदने के मामले में दलीय प्रत्याशियों को भी पीछे छोड़ दिया. हालांकि इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों ने कई दलीय प्रत्याशियों के विधानसभा जाने के मंसूबे पर पानी फेर दिया. यह काम कई तरीकों से अंजाम दिया गया. पैसे वाले प्रत्याशी टोले या मोहल्ले में नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क अभियान के बहाने पहुंचे. वहां उन्होंने लोगों की बातें सुनी, वादे किए और किसी सामूहिक काम के बहाने एकमुश्त राशि देने की बात कहकर वहां के सभी वोट अपने पक्ष में सुनिश्चित कर लिए.

बात पक्की होने पर प्रति वोट के हिसाब से या किसी सामूहिक कार्य के लिए राशि का भुगतान कर दिया गया. हद तो तब हो गई, जब अपने ही क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करने के बावजूद एक मंत्री को एक-एक वोट के लिए मशक्कत करनी पड़ी और अंत में प्रति वोट के हिसाब से रुपये बांटने पड़े. एक प्रत्याशी तो मतदान के एक दिन पूर्व बड़ी राशि के साथ गिरफ्तार किया गया. एक ग्रामीण ने बताया कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम लोगों और क्षेत्र की समस्याओं को देखने नहीं आएगा. अपने और परिवार के विकास में वह पांच साल लगा रहेगा तो हम लोग क्यों न अपने सामूहिक हित के लिए एक राशि वसूल लें. हालांकि इस मामले में ग्रामीण वोटरों ने ईमानदारी बरती, लेकिन शहरी वोटरों ने अपना दोहरा चरित्र दिखाया. ग्रामीण वोटरों ने जिससे पैसे लिए, उसी को वोट दिया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वोटरों ने पैसे लिए किसी से और वोट दिया किसी और को. गया शहर और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के दोहरे चरित्र को देखकर हर प्रत्याशी दंग रह गया. जिले के राजनीतिक जानकारों को मालूम है कि किस प्रत्याशी ने कितने रुपये बांटे और उसका क्या परिणाम हुआ. शहरी मतदाताओं के दोहरे चरित्र के पक्ष में बोलते हुए एक बुद्धिजीवी हंसते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र को भ्रष्ट करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com